MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, before we take up the Motion of Thanks, I would like to announce that the reply by the hon. Prime Minister to the Motion of Thanks is at 6.30 p.m. There are more than 18 Members to participate in the discussion. I request all the hon. Members to stick to the time allotted to their parties. Now, Shri Janeshwar Mishraji.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ करूं, उसके पहले मेरे मन में कुछ दुविधाएं हैं क्योंकि प्रस्तावक महोदय, जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं - केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, उनकी जानकारी और विद्वता की इज्जत भी करता हूं - उन्होंने थोड़ा सा हमें संकट में डाल दिया है। उन्होंने एक तरफ तो राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद दिया ही है, उसके साथ-साथ आखिर में कांग्रेस प्रेजीडेंट और प्रधान मंत्री को भी बधाई दे दी है। अब एक ही आरती से हम लोग कितने लोगों की पूजा करें, यह हम प्रस्तावक महोदय से जानना चाहेंगे? वैसे परम्परा यह रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब कभी भी चर्चा हुई है और किसी प्रस्तावक ने प्रस्ताव रखा है तो प्रधान मंत्री या उस समय की पार्टी जो सरकार में होगी, उसके प्रेजीडेंट को बधाई नहीं दी गयी। एक तरह से इसमें परम्परा टूट सी गयी है और लगता है कि इस समय जो लोग सत्ता में हैं, वे लोग अपनी तारीफ खुद कर लेना चाहते हैं। लेकिन प्रस्तावक महोदय, डा॰ कर्ण सिंह की मैं निजी तौर पर बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनसे यह उम्मीद नहीं करता था कि कांग्रेस प्रेजीडेंट और प्रधान मंत्री को भी वे राष्ट्रपति के साथ-साथ बधाई दे डालेंगे - यह मैंने उम्मीद नहीं की थी। इस तरह की हरकतों से थोडी-बहुत* की ध्वनि निकला करती है। महोदय, संसदीय लोकतंत्र एक जिन्दा बहस की जगह है, *की जगह नहीं है। मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बोलता, उसके पहले मुझे प्रस्तावक महोदय के भाषण पर बोलना पड़ रहा है, यह मेरी मजबूरी है। वैसे प्रस्तावक महोदय बहुत समझदार हैं। उन्होंने सारी योजनाएं, जो राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में - सरकार ने जो तय करके, तैयार करके दिया होगा - रखीं। उन सारी योजनाओं को कहते हुए एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है - मेरा ख्याल है कि उनको याद होगा - 'If properly implemented, it can transform the life of common man'. यह एक इतनी बड़ी शर्त है कि जो कोई भी योजना आए, 'If properly implemented' कहकर जो कोई भी आदमी होगा, अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है, एक मिनट के अंदर भाग कर सकता है क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। महोदय, इन्हीं की पार्टी के एक प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने एक बार कहा

---

*Expunged as ordered by the Chair.

था कि जो कोई भी योजनाएं इस समय देश के लिए जा रही हैं, अगर सौ रुपए की योजना होती है, तो केवल सत्रह रुपए का काम होता है, बाकी इम्प्लीमेंट नहीं होती 'If properly implemented' तो कह कर डा॰ कर्ण सिंह ने जिस * का इज़हार किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई जरूर देना चाहता हूं, यह बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है।

उपसभापति महोदय, बहुत से सवाल हैं, ज्वलन्त सवाल हैं देश के, सरकार की निगाह में वे सवाल नहीं उतर सके। सदन का दिमाग इस समय हलचल में है, उन सवालों को लेकर गर्म है, हम चाहते थे कि राष्ट्रपति महोदय उन मुद्दों को उठा देते ताकि हम लोग बहस करते, लेकिन पहले जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, हमारा धर्म है कि उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करें। सबसे पहले उन्होंने उठाया है कि आर्थिक विकास के मामले में हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर गया। पांच सैकड़ा से सात सैंकड़ा, सात सैकड़ा से आठ सैकड़ा पहुंच रहे हैं और यह हमारे लिए घमंड की बात हो सकती है, हम पढ़े-लिखे लोगों के लिए घमंड की बात हो सकती है लेकिन अर्थिक विकास की दर किसी आम जनता की बेहतरी का पैमाना नहीं हो सकती। थोड़े से प्रभु लोगों के पास पैसा चला जाए, खाते-पीते लोगों के पास पैसा चला जाए और अस्सी करोड़ लोग बेहाली में रह जाएं, तो उसको विकास दर नहीं कहते। मैं नहीं जानता कि हम लोग सत्ता और सत्ता के इर्द-गिर्द घूमते हैं, हम लोगों ने गांव को कभी ठीक से देखा है या नहीं, उसकी पगडंडी को कभी ठीक से देखा है या नहीं, उसकी धूल भरी सड़क को ठीक से देखा है या नहीं। उन सड़कों पर गरमी के दिनों में जब बच्चे दोपहर में छुट्टी के बाद चलते हैं, उनके पैर में जूता नहीं होता, तो वह जलती हुई मिट्टी, धूप में उनके पैरों को जलाती है। वे आधा पैर कभी ऊपर करते हैं, कभी नीचे रखते हैं, इस दर्द को इन लोगों ने समझा या नहीं समझा। वे कैसे चलते हैं, ऐसा लगता है कि कत्थक नाच कर रहे हैं, पैर जलने के कारण। जो गरीबी और अथाह गरीबी देश में है, उस गरीबी की चर्चा नहीं की। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी तालीम के बारे में कई योजनाएं सुनाई गई हैं। राष्ट्रपति महोदय के मुंह से हमने सुना भी है और पढ़ा भी है, लेकिन हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोगों के स्कूल में टाट-पट्टा नहीं होता था। हम लोग घर से बोरा लेकर जाते थे और यह बोरा हम लोगों की तकदीर के साथ चिपक जाता था। जो लड़का बोरा लेकर जाता था, अगर कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई नौकरी करने गया, तो वहां उसको बोरा ढोने की नौकरी मिलती थी और उसी समय, उसी उम्र के बच्चे देहरादून, ऊटी के स्कूलों में पढ़ते थे, वे कुर्सी पर बैठकर पढ़ते थे, और जो बच्चा कुर्सी पर बैठकर पढ़ता था, वह दिल्ली, कोलकाता जाने के बाद कुर्सी पर बैठने का काम पाता था। यह बोरा तकदीर के साथ चिपक जाता था। अबकी बार ''मिड-डे मील'' के नाम पर इन लोगों ने तैयार कराया है कि बच्चों को खिचड़ी दी जाएगी। अब सभी बच्चे कलम, दवात, कागज़ वगैरह तो अपने घर से लेकर जाते हैं, कटोरा भी लेकर जाते हैं बोरे के साथ-साथ और यह बोरा तो फिर भी काम दिला देता है, मज़दूरी दिला देता है, लेकिन कटोरा तो केवल भीख मांगने के लिए लिया जाता है। हिंदुस्तान के सभी बच्चों

*Expunged as ordered by the Chair.

के हाथ में कटोरा थमा दिया आपने, खिचड़ी देने के नाम पर! अब मास्टर बच्चों को पढ़ाता नहीं है, केवल खिचड़ी बनवाने की सोचता रहता है। बच्चे पढ़ते नहीं, कब खिचड़ी बनेगी, यह सोचते रहते हैं। इतनी भयानक स्थिति हो गई है और कभी-कभी बच्चों के मां-बाप भी खिचड़ी बंटने के समय अपने-अपने घर से कटोरा लेकर आ जाते हैं कि कुछ बचा हो, तो हमको मिल जाए। पूरे मुल्क को कटोराछाप बनाकर, एक तरह से हम बच्चों की मार्फत, भिखमंगा बना रहे हैं। एक जमाने में हमसे बोरा ढुवा कर हिंदुस्तान के गांवों के बच्चों को मिड-डे मील के नाम पर भिखमंगा बनाया जा रहा है। कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं हो सकता, इसके बारे में सोचना चाहिए। महोदय, सच तो यह है कि हम लोगों की उम्र जब बढ़ जाती है, तो हम अपना बचपन भूल जाते हैं। मनमोहन सिंह जी से पहले जो प्रधान मंत्री थे, एक बार उनकी फोटो मैंने देखी थी, रोज टेलीविज़न पर आती थी। दो बच्चे उनके अगल-बगल में खड़े हो जाते थे और दोनों बच्चों के साथ दस-बारह बच्चे एक साथ दौड़ते थे और कहते थे - ''चलो स्कूल चलें।'' तो एक बार डा॰ मुरली मनोहर जोशी से हमने कहा कि स्कूल जाते समय बच्चे कभी दौड़कर नहीं जाते। स्कूल से छुट्टी होती है, तब बच्चे घर आने के लिए दौड़ा करते हैं। अपनी उम्र के साथ अपना बचपन हम लोग क्यों भूल जाते हैं, यह मैं नहीं जानता। उपसभापति महोदय, हम लोगों को अपना बचपन याद रखना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग ही उनमें संस्कार डालते हैं, वे बड़े खतरनाक बन जाते हैं। आज जिन बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए कटोरा थमाया जा रहा है, कल के बाद जब वे कटोरा लेकर देश भर में निकल जाएंगे तो बड़ी भयानक तस्वीर बन जाएगी। क्या उनको काम नहीं दिया जा सकता? जिस स्कूल में उनको टाट-बोरी पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, उस बड़े स्कूल का मुकाबला करने की ताकत, इस सरकार में या किसी अन्य सरकार में लगता है नहीं बन पा रही है, लेकिन मैं यहां पर राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बहस करते हुए, मांग करूंगा कि क्या यह नहीं हो सकता है कि चौथे दर्जे, पांचवें दर्जे और सातवें दर्जे तक हिन्दुस्तान के जितने बच्चे हैं, चाहे वे बिड़ला सेठ के बच्चे हों, चाहे राष्ट्रपति के बच्चे हों, चाहे प्रधानमंत्री के बच्चे हों, चाहे M.L.A., M.P. और कलैक्टर के बच्चे हों और चाहे रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हों। सभी बच्चों को एक जैसे स्कूल में भेजा जाए। अगर रिक्शा वाले का बच्चा या हल चलाने वाले का बच्चा कटोरा लेकर जाता है तो उस जिले के कलैक्टर का बच्चा भी कटोरा लेकर जाए, हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री का बच्चा भी कटोरा लेकर जाए और तब हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर किसी जिले के कलैक्टर तक यह सोचने को मजबूर होंगे कि अब सभी बच्चों की तालीम ठीक करो वरना मेरा बेटा भी बिगड़ जाएगा। क्या सभी के लिए एक जैसी तालीम नहीं की जा सकती? सबके लिए अलग-अलग तालीम रखी जाएगी, प्रभु लोगों के बच्चों के लिए अलग तालीम, गरीब लोगों के बच्चों के लिए अलग तालीम तो गरीब का बच्चा कटोरा लेकर जाएगा। यह शिक्षा की बदहाली बहुत बुरी है। यह शुरूआती बदहाली है इसलिए मैं इसकी ओर इशारा कर रहा हूं। मैं B.A., M.A. की बदहाली के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में योजना और कार्य योजनाओं

में बेरोजगारी की तरफ भी इशारा किया है कि जब ये बच्चे जवान होते हैं तो काम मांगने लगते हैं। सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। कभी साल भर में 30 दिन का काम देकर, यह कहा जाता है कि हमने बेकारों को काम दे दिया है। कभी साल भर में 100 दिन का काम देकर कहा जाता है कि हमने बेकारों को काम दे दिया है। क्या उनको साल भर का काम नहीं दिया जा सकता है? मैं मुलायम सिंह की, उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ करूंगा। हम लोग लड़कपन में नारा लगाते थे कि बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो। उन्होंने पहली मर्तबा घोषणा की है कि अगर हम काम नहीं दे पाएंगे तो हर B.A. Pass नौजवान को 500 रुपया बेकारी भत्ता देंगे। ऐसा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। हम जानते हैं कि इस काम के लिए केन्द्र सरकार धन मुहैया नहीं कराएगी। मैं चाहूंगा कि अगर राज्य सरकारें बेकारी को दूर करने के लिए कोई संकल्प लेती हैं, 500 रुपए से नौजवान की जिंदगी नहीं कटेगी, लेकिन राज्य सरकार का यह संकल्प कहलाएगा। जब कभी भी राज्य सरकारें इस तरह का संकल्प लेने लगें तो केन्द्र सरकार को मुक्त-हस्त से उनकी मदद करनी चाहिए। सर, मैं यह निवेदन करूंगा कि बेकारी का सवाल बहुत भयानक है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारा बेटा जवान हो गया और अगर वह कुछ पढ़-लिख गया तो वह किसी काम का नहीं रहता है। वह M.A. की डिग्री लेकर चार दर्जे पास के नेता के पीछे-पीछे घूमता रहता है कि हमको कहीं काम दिलवा दो। उसकी हालत को देखकर रुलाई आ जाती है। मैंने मुम्बई स्टेशन पर, कानपुर स्टेशन पर और हावड़ा स्टेशन पर देखा है कि बहुत से लोग गिरोह बनाकर बच्चों को पकड़ लेते हैं और उनके हाथ-पैर काट देते हैं और आंख फोड़ देते हैं और उनको कटोरा थमाकर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देते हैं। वह बड़ा होकर भीख मांगने लगता है। अगर हम यह कहें कि वर्तमान शिक्षा पद्धति हिन्दुस्तान के नौजवानों को पढ़ने के बाद, दूसरों के सामने हाथ पसारने के लिए मजबूर कर रही है तो मैं उन भिखमंगों के गिरोह के सरगना को याद करने लगता हूं। आखिर इतनी बुरी तस्वीर क्यों है? क्या यह नहीं हो सकता कि जो कोई भी 18 साल, 20 की उम्र पार कर ले तो सरकार उसकी जिम्मेवारी ले और मूल अधिकारों में परिवर्तन करके यह जिम्मेवारी ले। जैसे मंदिर में जाने पर हमको कोई नहीं रोक सकता, मस्जिद में अजान पड़ने पर हमको कोई नहीं रोक सकता, अगर हम 18 साल की उम्र पार करने बाद काम करना चाहें तो हमको कोई रोक नहीं सकता, यह हमारा मूल अधिकार बन जाए। क्यों छोटी-छोटी योजनाओं में माथा-पच्ची की जा रही है। उस माथा-पच्ची पर प्रस्तावक महोदय कह देंगे, if implemented properly और हमारे जैसा आदमी संकट में पड़ जाएगा कि यह properly implement होगा या नहीं होगा? उपसभापति जी, ये तस्वीरें हैं, जिसका जिक्र मुझे करना था। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत सी तस्वीरें रखी हैं। लगता है कि वे सब्ज़बाग दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि उस सब्ज़बाग में गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है और यह संसद गरीबों की चुनी हुई संस्था है, यह अमीरों की जमात नहीं है, महाप्रभु लोगों का घर नहीं है। प्रस्तावक महोदय ने वैसे भाषण तो अंग्रेजी में दिया, लेकिन हिन्दी के एक शब्द "आम आदमी" का इस्तेमाल किया था। सवाल यह नहीं है कि दिल्ली से जो

खजाना बंटता है, वह आम आदमी को मिलता है, सवाल यह है कि समाज के अंतिम आदमी को वह खजाना कितना मिलता है और सच यह है कि अभी जब चिदम्बरम साहब का बजट बनेगा, तो समाज का अंतिम आदमी और आम आदमी, जिनकी तादाद 80 करोड़ है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, थोड़े से महाप्रभु लोगों के बीच — जो सेठ साहूकार होंगे, अफसर होंगे, कर्मचारी और अधिकारी होंगे–यह बजट बटकर रह जाएगा। यह बजट का रूप होता है।

जब उन्होंने "आम आदमी" शब्द का इस्तेमाल किया था, तो मैं सोचने लगा कि "आम आदमी" को देखकर कभी पैमाना तय नहीं करना चाहिए, अंतिम आदमी को देखकर पैमाना तय करना चाहिए, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति महोदय ने देश के विकास के लिए जिन योजनाओं का जिक्र किया है, वे योजनाएं थोड़े से बड़े लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, आम आदमी की तरफ वे योजनाएं झांकती भी नहीं हैं, उनकी जिंदगी को वे पहचानती भी नहीं हैं। यह तो मैं अपना दर्द कहूंगा, लेकिन बहुत से अनकहे दर्द भी हैं, जिनके बारे में राष्ट्रपति महोदय ने चर्चा तक नहीं की है, ऐसे बहुत से अनकहे दर्द हैं।

वैसे उन्होंने पानी के सवाल पर चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि पानी एक समस्या है और पानी से ज्यादा इस देश के सामने कोई समस्या नहीं है। जमीन के नीचे के पानी का दोहन बहुत जोर से हो रहा है। रघुवंश जी चले गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पानी पीने के काम भी आता है और पानी खेतों को सींचने के काम भी आता है। खेतों को सींचने के काम आने वाला पानी पिया नहीं जाता है, लेकिन आज हिंदुस्तान में पीने लायक पानी बहुत कम रह गया है। गंगा नदी जिसको हम बहुत पवित्र कहते हैं, अभी माघ मेला वहां लगा था, 15 दिनों तक गंगा नदी का पानी लाल-लाल बह रहा था, लाल रंग का पानी बह रहा था और साधू हड़ताल कर रहे थे, वे कहते थे कि इसमें हम डुबकी नहीं लगाएंगे। माननीय राष्ट्रपति जी पेयजल की बात करते हैं, यहां तो गंगा ही लाल हो गई थी और जब गंगा मैली हो जाए, तो उस समय क्या हुआ करता है? गंगा में बहुत से गुण हैं, लेकिन वह मैली कभी नहीं होती थी, इस बार लाल रंग का पानी दिखाई दिया।

उपसभापति जी, क्या सरकार कभी यह आंकड़ा जुटाने की कोशिश करेगी कि देश की आबादी का कितना हिस्सा शुद्ध पानी पीता है और कितना हिस्सा गंदा पानी पीता है? शुद्ध पानी और गंदे पानी को नापने के लिए मशीनें बन गई हैं, यह नापने का काम बहुत आसान है, लेकिन नापा नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं नाप पा रहे हैं। यह सच है कि बातों को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आज किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। उसकी हालत कभी भी ठीक नहीं होती है। कितनी भी योजनाएं बनें, वह बदहाली की हालत में ही रहता है क्योंकि उसकी जो पैदावार होती है, वह बड़ी कच्ची होती है। वह सवेरे के समय बाजार में टमाटर बेचने के लिए आता है, तो 10 रुपए किलो बेचता है, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, वह उसी टमाटर को एक रुपया किलो में देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन टमाटर सड़ जाएगा।

राष्ट्रपमि महोदय और वर्तमान सरकार ने किसान की पैदावार के कच्चे उत्पाद के बारे में कभी गौर ही नहीं किया है कि वह कितनी दुर्दशा की हालत में सब्जी लेकर आता है, कच्चा माल लेकर आता है। गेहूं को तो फिर भी वह छह महीने, साल भर तक थात लेता है, लेकिन कपड़े और लोहे के मुकाबले वह इसे नहीं थात सकता। कारखाने से जो चीज पैदा होती है, वह ज्यादा से ज्यादा एक साल तक चल सकती है, उसके बाद उसमें घुन पड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे। तो किसान मजबूर है। जो भाव आप तय कर दीजिए, वह उस पर अपना सामान बेचेगा। वह दस रुपए किलो का टमाटर, एक रुपया किलो में बेच देगा, वह गेहूं सस्ता बेच देगा। आपको उसे भरपेट खुराक के लिए गारंटी देनी पड़ेगी।

हम चाहते हैं कि सरकार सामान सस्ता बिकवाए, लेकिन इस समय जो बाजार भाव चढ़ा है, जिस तरह से महंगाई चढ़ी है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। खाने-पीने की चीज़ों से लेकर सारी चीजें एक बारगी महंगी हो गई हैं।

स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रपति महोदय ने कहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों, यहां तक कि एम्स ने जिस तरह से अपना रेट बढ़ाया है, गरीब आदमी अब अपना इलाज नहीं करा सकता है। वह बिना दवा के मर जाएगा। जब कभी भी हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं, तो स्वस्थ भोजन के साथ-साथ हमारे पास सस्ती दवा भी होनी चाहिए। यह सच है कि राज्य सरकारें भी कभी-कभी दवा महंगी करती हैं, अस्पतालों में भर्ती होने की जो पर्ची होती है, उसका दाम बढ़ा देती हैं, चारपाई का दाम बढ़ा देती हैं, डाक्टर के विजिट का दाम बढ़ा देती हैं, जो दवा देती हैं, उसका भी पैसा लेने लगती हैं, राज्य सरकारें अपने सरकारी अस्पतालों में कभी-कभी ऐसा कर देती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई, जिसने पहले वाली सरकार ने जो पर्ची का दाम 8-10 रुपया बढ़ाया था, उसको खत्म किया। उसने दवाई का दाम खत्म कर दिया, डाक्टर की विजिट और चारपाई का दाम खत्म कर दिया। हमने लड़कपन में नारा लगाया था, जब हम सोशलिस्ट पार्टी में थे - ''कपड़ा-रोटी सस्ती होगी, दवा-पढ़ाई मुफ्ती होगी''। यह नारा हमने लड़कपन में लगाया था। हमने नारा लगाया था कि बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो। हम जानते हैं कि यह सरकार भी समाजवाद की बात करती है और जब यह सरकार समाजवाद की बात करती है, तो मैं चाहूंगा कि दवा-पढ़ाई मुफ्ती हो, मैं चाहूंगा कि कपड़ा-रोटी सस्ती हो। कुदरत कभी भी हम लोगों को दो आंख से नहीं देखा करती है। सर, हम गंगा नदी में नहाने जाते हैं, तो गंगा नदी बहती रहती है, हमारी तरफ देखती भी नहीं। हम तो छोटे आदमी हैं, अगर जगद्गुरू शंकराचार्य या बिड़ला सेठ भी नहाने चले जाएं, तो गंगा यह नहीं कहेगी कि मैं अपना बहाव रोक रही हूं, महाराज डुबकी लगा लो। उपसभापति महोदय, वहां आज कोई दलित चला जाए या वहां कोई भिखमंगा चला जाए, तो गंगा यह नहीं कहेगी कि तुम हममें डुबकी नहीं लगा सकते। हम समझते हैं कि कुदरत ने हमको बराबरी सिखाया है, हमको समाजवाद सिखाया है। मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में यह ढूंढ रहा था कि कहीं बराबरी आएगी कि नहीं समाज में। समाज का अन्तिम आदमी और सबसे बड़ा आदमी किसी घाट पर एक

जगह खड़ा होकर बराबरी का पानी पीएगा कि नहीं, लेकिन हमको एक लाइन भी देखने को नहीं मिली।

बीच में, जिनका जिक्र नहीं किया गया, पीछे हमारे अमर सिंह जी शायद बैठे हैं या चले गए, ये हमारे सदस्य हैं। ये हमारे माननीय सदस्य हैं। ये कहने लगते हैं कि हमारा टेलीफोन टेप हो रहा है, हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है हम इस सदन के मैम्बर हैं, हमको यह खतरा हो जाए कि हमको कोई जान से मार डालेगा, तो हम गंगा के बारे में, हम कुदरत के बारे में, बराबरी के बारे में, अन्तिम आदमी के बारे में खुल कर बहस नहीं कर सकते। प्रभु वर्ग के लोग हमको पिटवा देंगे। आपकी तरफ से यह कहा जा सकता है कि यह मामला अदालत के विचाराधीन है। सेक्रेटरी-जनरल साहब शायद यही कहने गए हैं, लेकिन मैं अमर सिंह का मामला न उठाऊं, तो सर, मैं यह तो कह ही सकता हूं कि ये कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी है। सत्तारूढ़ दल समझता होगा कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन मार दिए जाएंगे, क्या उस दिन आप विश्वास करेंगे कि ये मार दिए गए और ये सच बोल रहे थे। यह कह सकते हैं कि कोई भी बदमाश आकर मार सकता है, यह कह सकते हैं कि कोई भी टेप करने वाली कम्पनी टेप कर सकती है, लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम पार्लियामेंट की मैम्बर्स दोनों सदन मिला कर मुश्किल से हजार होंगे, अगर हमारी जिन्दगी की हिफाजत भी आप नहीं कर सकते, तो 100 करोड़ लोगों की जिन्दगी की हिफाजत आप कैसे कर सकते हैं। असम्भव हो जाएगा। हम डर कर कोई बात नहीं बोलें कि कल को बोलेंगे, तो परसों कोई मार देगा, तो हमारी आवाज़ आज़ादी से नहीं निकल सकती। हम डर कर कोई बात नहीं बोलें कि हम जो कुछ भी बहस कर रहे हैं, कोई जानकारी ले रहे हैं, हमारे सर पर कोई टेप की तलवार लटक रही है। हम खुल कर जानकारी नहीं ले सकते हैं। ये अमर सिंह तो अमर सिंह, एक जज साहब ने रिटायरमैंट के बाद कहा, बेहतर होता कि लालू जी यहां होते, कि वे चारा घोटाले की जांच कर रहे थे, तो उनका भी टेलीफोन टेप हो रहा था।''एक गजब किस्म का माहौल बना है, जैसे हमारे पास प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हम अपनी जिन्दगी आज़ादी से जी नहीं सकते। जो लोग सत्ता में हैं और सत्ता के इर्द-गिर्द हैं, वे हम से इतना खौफ़ क्यों खाते हैं? हम हथियार उठाने वाले लोग नहीं हैं। वे जानते हैं कि बहुत बोलेंगे तो बात बोलेंगे, कड़ी बात बोलेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे। यह लोकतंत्र का लक्षण है। लोकतंत्र में जो विपक्ष में होता है, उसके तीन ही काम होते हैं— जो सरकार में होता है, उसको अपोज़ करें, जो सरकार में होता है, उसको एक्सपोज करें और अगर ताकत बन जाए, तो डिपोज़ करें। अगर हम विपक्ष में बैठ कर ये तीनों काम करने लायक नहीं रहेंगे और लगातार डरते रहेंगे, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उपसभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि हम सदस्यों को सदन में आज़ादी से बोलने दें और अपनी बात रखने दें। यह पंचायत है, यह कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अदालत नहीं है कि हम अपने-अपने पक्ष की बहस करेंगे।

एक दिन राजनाथ सिंह जी से हमने कहा था कि तुम दिमागी तौर पर हमारे विरोधी हो, लेकिन हम तुमसे बात करेंगे। तुम थोड़ा अपने आपको सुधारो और हममें कोई गलती हो तो बताओ, हम भी सुधारेंगे। हम एक-दूसरे को सुधारने और सुधरने के लिए बैठे हैं। हम अपनी ताकत-भर बहस करेंगे, जो समझते हैं। हम चाहेंगे कि शिवराज पाटिल साहब भी अपनी ताकत-भर बहस करें, जो जानते हैं। लेकिन अगर पंचायत में बैठने के बाद हमारी बात उनको अच्छी लग जाए, तो उन्हें मान लेनी चाहिए और उनकी बात अगर पंचायत में बैठने के बाद हमको अच्छी लग जाए, तो हमको भी मान लेनी चाहिए। यह अदालत नहीं है कि एक-एक पक्ष से हम खड़े होंगे। यह पंचायत कहलाती है। पंचायत का यह चरित्र, एक-दूसरे को समझाने और आदमी में एक दूसरे को समझने की जो क्षमता और धीरज होना चाहिए, वह स्वरूप खत्म हो गया है। मुझे इस बात का अफसोस है। वह स्वरूप खत्म होने पर किसी मैम्बर का फोन टेप होगा, किसी मैम्बर को जान से मरवाने की धमकी दी जाएगी। यह पंचायत ही नहीं जज ही तक चली जाएगी। तब इस समाज में जीना और इस पंचायती राज को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

यह सच है कि पंचायती राज थोड़ा स्खलित हुआ है। इसे हम लोगों ने स्खलित किय है। हम लोग जिस तरह का राज्यपाल केन्द्र से भेजते हैं, राष्ट्रपति महोदय भेजते हैं, वे राज्यपाल केन्द्र के मामले में दखल देते हैं। बिहार में जो कुछ भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस राज्यपाल को नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी और उसको त्यागपत्र देना चाहिए था। जब आप अपने राज्यपाल के मार्फत किसी सूबे के लोकतंत्र को नचाना, इधर से उधर करना शुरू करेंगे, तो दुनिया का जो महाप्रभु है, वह अपने राजदूत के मार्फत आपको धमकाना शुरू करेगा।

इधर हम लोगों ने ईरान के मुद्दे पर बहस की है। सर, इस समय लोकतंत्र नौकर-चाकर के मार्फत चल रहा है। यह जनता की इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है। अमेरिका का मालिक अपने राजदूत से धमकी दिलवाता है कि यह काम करो वरना ठीक कर दिए जाओगे। हमारे यहां भी एतराज होता है कि तुम कौन कहने वाले होते हो? मोहल्ले वाले भी कह देते हैं- अरे, बच्चा है, कह दिया। छोड़ो, उसको डांटेंगे। यह भाषा चला करती है। जमींदार साहब अपनी किसी प्रजा को गाली दे आते हैं। वह आकर एतराज करता है तो जमींदार साहब कहते हैं-बच्चा है, डांटेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ही डांट दिया गया। भारत एक लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र है। आज पूरा-का-पूरा एशिया खतरे में पड़ा है। दो देश बरबाद हो चुके हैं, अब तीसरे का नम्बर है। हो सकता है कि चौथा हमारा नम्बर आ जाये या पाकिस्तान का नम्बर आये। उसके बाद चीन का नम्बर भी आ सकता है। एक महाप्रभु अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सब को किसी-न-किसी बहाने नचाना चाहता है। उस समय हम दब जाएं और दब जाएं उसके एक कर्मचारी की धमकी से, तो हमारी तौहीनी की इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है। इस प्रकार लोकतंत्र तो आज खतरे में पड़ा है।

माननीय सदस्य डा॰ कर्ण सिंह जी ने ठीक ही किया है कि सोनिया गांधी जी को भी बधाई दे दिया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि असली सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है। '...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, I have got an objection to it. Shrimati Sonia Gandhi is not a Member of this House. (*Interruptions*)... He is the senior-most Member of the House and former Minister also. (*Interruptions*)... He should know these facts. (*Interruptions*)...

श्री जनेश्वर मिश्र: हमने नाम नहीं लिया है। ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: How is he making an allegation against her? (*Interruptions*)...

श्री जनेश्वर मिश्र: हमने नाम नहीं लिया है। ...(व्यवधान)... प्रस्तावक महोदय ने नाम लिया है। ...(व्यवधान)... यह रिकॉर्ड पर आ चुका है। ...(व्यवधान)... मैं पढ़ चुका हूं। ...(व्यवधान)... इसे आप पढ़ लीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: He gives a lecture on democracy and he is talking like this. (*Interruptions*)... It is the view of Dr. Karan Singh. (*Interruptions*)... He has taken the name of Shrimati Sonia Gandhi. (*Interruptions*). He has taken her name. Shrimati Sonia gandhi is not a Member of this House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If it is derogatory, I will look into it.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, it is derogatory.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will examine it. If it is derogatory, I will look into it.

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): नाम डा॰ कर्ण सिंह जी ने लिया है। ...(व्यवधान)... उनको धन्यवाद दे रहे हैं, कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार (आन्ध्र प्रदेश): रेफरेन्स करने में क्या गुनाह है? ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: He has made a sarcastic remark. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will look into it. (*Interruptions*).

SHRI JANARDHANA POOJARY: He has made a sarcastic remark.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Poojary, I will look into it.

SHRI JANARDHANA POOJARY: It has to be decided.

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, यह डा॰ कर्ण सिंह जी ने नाम लिया है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज, अमर सिंह जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... मिश्र जी, आप बोलिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, हमने किसी बुरी नीयत से कांग्रेस प्रेसीडेंट का नाम नहीं लिया है। चूंकि यह तो डा॰ कर्ण सिंह जी, जिन्होंने प्रस्ताव रखा, उन्होंने नाम लिया। ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, आप बैठिए, प्लीज। मिश्र जी को बोलने दीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: उन्होंने चूंकि यह नाम रखा है, तो यह बहस का विषय हो गया। प्रस्तावक महोदय अगर यह नाम नहीं लेते, तो यह इस सदन की प्रोपर्टी नहीं बनता। माननीय सदस्यों के लिए मैं यह बता दूं, लेकिन अगर उन्होंने नाम ले लिया, तो यह सदन का विषय बन गया। ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, he is charging her. He has made an allegation. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Poojary, I have said that I will look into it.

श्री जनेश्वर मिश्र: No charge. मैंने चार्ज नहीं लगाया। ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: He has made a sarcastic remark against her. She is not a Member of this House. (*Interruptions*).

श्री उपसभापति: पुजारी जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए प्लीज। ...(व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री उपसभापति: हम उसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र: जी, आप उस रिकॉर्ड को देख लीजिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री इसलिए बने थे कि सोनिया जी ने इनका नाम प्रपोज किया था, पहले वही प्रधानमंत्री बन रही थीं। हमारे जैसे आदमी को अच्छा लगता, क्योंकि उनके नाम पर वोट मिला था, वह बनतीं, हम लोग उनसे डायरेक्ट बहस करते तो ये लोग भी एतराज नहीं करते। उन्होंने एक दूसरे आदमी को

प्रधानमंत्रीजी बना दिया, जिसके नाम पर इनको वोट नहीं मिला था। अब हम इस पर बहस करें, तो किससे करें? और, अगर माननीय कर्ण सिंह जी ने उनका नाम नहीं लिया होता, तो इतनी मैं डिग्निटी जानता हूं, मैं उनका नाम नहीं लेता, कभी उनका नाम नहीं लेता, मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरी उनकी मुलाकात भी नहीं है और मैं मानकर चलता हूं कि एक बाहर की महिला हमारे देश की बहू बन गई, तो उसका सम्मान होना चाहिए, बहुत सम्मान होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री अगर उनकी मर्जी से बनता है तो हमारा लोकतंत्र तो कमजोर हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति की मर्जी से, गांधी जी की मर्जी से तो नेहरू जी नहीं बने थे या जय प्रकाश जी की मर्जी से मोरार जी देसाई तो नहीं बने थे। जिन दिनों बड़े-बड़े आंदोलन हुए थे और बहुत भारी भारी नेता थे। ... (व्यवधान)

डा॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उसमें सभी सांसदों की स्वीकृति थी। ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, is it not a charge against her? He is making an allegation. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Poojary, when your turn comes, you can reply to it. (*Interruptions*). I cannot direct...(*Interruptions*). I cannot direct a Member when he is speaking. If it is derogatory or unparliamentary, it is difficult for the Chair to decide. It is left to each Member to follow rules and give respect to each other. Beyond that, if you ask the Chair to give a ruling on this, what ruling can the Chair give? Please tell me. (*Interruptions*). Please listen to me. Mr. Poojary, please listen to me. I have assured that I will look into it if there is anything derogatory. (*Interruptions*). I will look into it. I have told you that I will look into it. Beyond that, what is it that you want? (*Interruptions*)

SHRI RAJEEV SHUKLA (Uttar Pradesh): Can the Prime Minister be nominated by anybody? It is a misleading remark...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shuklaji, please...(*Interruptions*) Mr. Poojary, please sit down...(*Interruptions*) I am telling you, please sit down. If any Member is using any language or expressing any opinion, you have every right to refute it. From your side also, there are speakers. You take that opportunity and refute whatever allegations have been made against any leader. With the same vehemence, you have every right to place your viewpoint. I am not denying that opportunity to anybody. But the Chair has a mandate and there are certain rules, and I have to act on this basis. Definitely the chair will not allow any derogatory remark about

any leader. It is not right for any Member to make derogatory remarks; everybody has to respect the leaders. But, if there is anything objectionable, I said, "I will look into the record." You have raised your exception and I will look into the record...(*Interruptions)*

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): It is a *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; * is not allowed. That is an unparliamentary word. I am removing it form the record...(*Interruptions)* Mr. Ramachandraiah, please...(*Interruptions)* Nothing will go on record...(*Interruptions)* Please sit down. Mr. Poojaryji, please...(*Interruptions)* Let the debate go on. I have expunged that word. That is the end of it.

श्री जनेश्वर मिश्र: उपसभापति महोदय, हमें दुख है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों को हमारी कुछ बातें नागवार लग गई हैं। उन लोगों को मालूम है कि अभी तक भी हम उनके समर्थक हैं और मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि समर्थक अगर बॅगल में खड़ा होकर कुहनी भी मार दे तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए ...(**व्यवधान**)। अभी तक हम उनके समर्थक हैं। आपस में जरा सी कुहनी तो चलती ही है और हम तो आप लोगों को केवल कुहनी ही मार रहे हैं, वामपंथी लोग तो कभी-कभी धक्का मारने लगते हैं और आप उसे बर्दाश्त भी कर लेते हैं ...(**व्यवधान**)। हम तो धीरे से केवल कुहनी मार देते हैं और आप नाराज हो जाते हैं ...(**व्यवधान**) ऐसा नहीं होना चाहिए। उपसभापति महोदय, अगर उन लोगों को तकलीफ हुई है ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: Hon. Members, I cannot stop the interruptions. But I just want to remind the hon. Members. क्योंकि आपकी पार्टी को 35 मिनट मिले हैं और अब तक 34 मिनट हो चुके हैं।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, बीस मिनट तो यूं ही शोर में चले गए हैं।

श्री उपसभापति: ठीक है, ठीक है, I just wanted to remind the House; I said this earlier also. क्योंकि इस डिबेट पर there are 18 Members more to speak. I request all the Members to confine themselves to their time. Time is the constraint for us. Everyone wants to speak. But we have to speak within the time given. I am just reminding you, 34 मिनट हो गए हैं और अब पांच-दस मिनट में ही आप अपनी बात को समाप्त कीजिए ...(**व्यवधान**) मैं तो आपको सिर्फ रिमांइड करवा रहा हूं, क्योंकि समय के लिए जब तक आपको रिमाइंड नहीं करवाएंगे तब तक बोलने वालों को यह मालूम नहीं चलेगा कि उन्होंने कितना समय ले लिया है। सर, अगर हमारे उन मित्रों को बुरा

*Expunged as ordered by the Chair.

लगा हो तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना तो कहने का अधिकार दीजिए कि अगर एक ही आदमी के हाथ में आप अधिकार दे देंगे तो उसके बाद लोकतंत्र की क्या दुर्दशा होगी, लोकतंत्र में अंतिम आदमी भी वोट देने का अधिकारी है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप खुद ही अपना अधिकार खो रहे हैं। यह बहुत गलत हो रहा है।

(उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) पीठासीन हुए)

इसलिए लोकतंत्र जब एक जगह से खिसकता है उपसभाध्यक्ष महोदय, तो वह कई जगह से खिसकता है। मैंने इसीलिए इशारा किया था कि अगर केन्द्र अपने गवर्नर का इस्तेमाल करेगा और कई जगह कर रहा है, मैं यह तो नहीं कहता कि आज ही सरकारिया कमीशन लागू कर दिया जाए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस राज्य में जो सरकार हो उसके मुख्य मंत्री से मशविरा करके तक गवर्नर रखना चाहिए। वह सूट करे न करे, क्या करें और यह नंगी तस्वीर हम लोग देख चुके हैं। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है हमारे कांग्रेस के मित्रों को, यह सच है कि हमारा समर्थन आप नहीं चाहते होंगे, क्योंकि जिस दिन समर्थन वाली मीटिंग थी, अमर सिंह जी के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ था, वह हम लोगों को याद है, लेकिन अपमानित होकर के भी हम आपका समर्थन इसलिए करते हैं कि साम्प्रदायिक शक्तियां फिर से न उभर जाएं। यह हमारी दृष्टि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन शक्तियों से जो मार हम लोगों को पड़ती है जो हम सबसे पहले झेलते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ही लोग बने रहें, आपको बर्दाश्त कर लिया जाए। लेकिन नीतियां गलत हो रही हैं और नीतियां न केवल आपकी, जिस तरह का देश बना है, सब जगह आपके समर्थक यह हमारे वामपंथी मित्र, एक दिन हमने अखबार में पढ़ा हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, एक अध्यापक 32 साल से केवल दो हजार पर नौकरी कर रहा है। यह कहीं एक जगह है, यह बड़ी-बड़ी हैडिंग में छपा था। हम जानते हैं कि केन्द्र सरकार बोल देगी कि यह राज्य सरकार का विषय है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह राज्य सरकार का विषय नहीं हो सकता, यह सारे देश में चल रहा है कि जहां प्राइवेट संस्थाएं चलती हैं डेढ़ हजार, दो हजार, ढाई हजार तक में मास्टर रखे जाते हैं और वे लोग स्कूल चला रहे हैं। इससे अध्यापक का पेट नहीं भरता। एक अजीब किस्म के अध्यापक की जिंदगी दुरूह होती जा रही है, वह गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया है। मैं नहीं जानता कि हमारे राष्ट्रपति महोदय को भारत सरकार ने यह पॉइंट कभी दिया या नहीं कि स्कूल के अध्यापकों की हालत कैसे सुधारी जाएगी। यह भी नहीं दिया है कि जो गांव के किसान आत्म हत्या कर लिया करते हैं, उनकी हालत कैसे बेहतर की जाएगी, जिससे वे आत्म हत्या न कर सकें। उसकी गारंटी भी नहीं दी गई। हमने एक दिन शरद पवार जी से एक सवाल पूछा था कि किसान तो पुराने दिमाग का होता है, दिमागी तौर पर ऑर्थोडॉक्स होता है, अगर समय से पानी नहीं बरसा तो उसकी कपास सूख गई, उसका तम्बाकू सूख गया और यह किसी कारखाने का कच्चा माल होता है कपड़े के कारखाने का, सिगरेट के कारखाने का, उसको पैसा नहीं मिला और सूख गया और इस कारण लोगों ने अपनी बीवी का जेवर

गिरवीं रख दिया फिर बाद में देखा कि वह इस जेवर को छुड़ा नहीं पाएगा तो वह आत्म हत्या कर लेता है। लेकिन उसी किसान का बेटा दिमाग का ऑर्थेडॉक्स नहीं है, तो वह हथियार उठा लेता है और हथियार उठाने के बाद वह जब निकलता है तो कभी-कभी मुख्य मंत्री जैसे लोगों को निशाना बना देता है, सड़क पर बारूद बिछा देता है और तब हम लोग चिंता करने लगते हैं कि अपराध बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। क्या यह सच नहीं है, उत्तर प्रदेश को छोड़कर के आजादी मिलते ही भूमि संशोधन के बारे में किसी भी राज्य में उतना इफेक्टिव कानून नहीं बना है। यह सच नहीं है, बिहार में नहीं बना, श्री बाबू मुख्य मंत्री थे, विधान चन्द्र मुख्य मंत्री आए थे, बंगाल में नहीं बना। अगर इन इलाकों में आतंकवाद बढ़ गया जमीन के सवाल पर और जमीन के साथ-साथ जाति जुड़ गई, सर, वे लोग जिनके पास जमीन नहीं थी समाज में उनकी जाति छोटी मानी जाती थी। जाति और जमीन दोनों का ह्रास और क्षय एक साथ बिहार में हो गया। नक्सलपंथ पहले बंगाल से चला था, जमीन के संशोधन के कानून आंध्र में नहीं बन सके, तो आज वहां भी आतंकवाद है। यह उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में कालाहांडी के इलाके में आदमी भूख से मर जाता है, लेकिन वह हथियार नहीं उठाता है। वह दिमागी तौर पर कंजरवेटिव है, अगर यह सरकार चाहती है कि हिन्दुस्तान का आदमी कंजरवेटिव रहे और भूख से मरता रहे और हल्ला न मचाये, तो मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा, लेकिन आदमी रोटी के लिए हल्ला मचाता है, हथियार उठाता है तब तो आपको निदान सोचना ही पड़ेगा, आदमी नहीं, तो आदमी का बच्चा उठा लेगा और जिस तरह से यह हालत बिगड़ी है, उपसभाध्यक्ष महोदय, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उनकी बेटियां, उड़ीसा के किसानों की बेटियां, केरल के किसानों की बेटियां विदेश नौकरी करने के लिए चली जाती हैं। उनके साथ क्या व्यवहार होता है, यह हम लोग जानते हैं। वे वहां मजदूर हैं, यहां श्रम विभाग होगा, लेकिन श्रम विभाग उनकी तरफ कभी भी नोटिस नहीं लिया करता है कि उनकी हालत कैसे सुधारी जा सकती है, वे भारत की बेटी हैं। वह भारत जहां कभी सीता थी, वह भारत जहां कभी द्रोपदी थी, जिनके नाम पर रामायण, महाभारत की लड़ाई लंका तक जाकर हुई थी। आज पता नहीं कितनी सीता और द्रोपदी की बेटियां बाजारों में अपनी इज्जत बेच रही हैं, विदेश में सरहद के बाहर जाकर के बेच रही हैं। इन मजबूरियों की तरफ अगर सरकार राष्ट्रपति महोदय का ध्यान अपने अभिभाषण में नहीं दिलायेगी, तो इस अभिभाषण का जिक्र, मैं सही कह दूं हिन्दुस्तान का आम आदमी कुछ नहीं जानता कि कोई अभिभाषण हुआ था। मैं अभिभाषण के दूसरे दिन गांव में गया था, गांव के लोगों से पूछा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया, तुमने कुछ सुना, उन्होंने कहा कि हम तो जानते ही नहीं कि ये कब हुआ, क्योंकि अखबार में कुछ छपा नहीं था। उनकी एक लाइन छपी थी कि यह भारत के हित में होगा कि अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे रहें, ठीक रहें और सुधरें, केवल एक लाइन छपी थी अभिभाषण कुछ नहीं छपा था उस अभिभाषण पर भी हम चले आवें, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय बड़े काबिल आदमी हैं, मैं उनको केवल विद्वान और काबिल आदमी नहीं मानता, बल्कि दुनिया में जितने भी फन होते हैं, जानकारियां होती हैं, सब का काबिल आदमी मानता हूं जिस तरह से उनके भाषण निकलते हैं।

क्या किसी मजबूत आदमी से कमजोर की दोस्ती होती है? क्या इसमें कमजोर फायदे में रहता है, उपसभाध्यक्ष महोदय, आप ही अपनी कुर्सी से इस पर जजमेंट दे दीजिए। कमजोर जब कभी भी मजबूत से दोस्ती करता है, तो कमजोर लूट लिया जाता है, बर्बाद हो जाता है। किसी बड़े किसान से छोटा किसान दोस्ती करता है, तो उसकी खेती बिक जाया करती है, यह हमने गांव में देखा है। इसलिए बड़े से छोटे की दोस्ती अशुभ मानी जाती है। लेकिन उन्होंने कह दिया है, अखबार में छप गया है कि हमारे संबंध सुधर रहे हैं। हमने सुना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति हिन्दुस्तान आ रहा है और भारत सरकार उसका स्वागत करने वाली है। यही सदन है माननीय मनमोहन सिंह जी इधर बैठे हुए थे, हम लोगों के नेता थे और उधर अटल जी बैठा करते थे, इराक पर हमला हुआ था। इस सदन में और उस सदन में बात चली कि निन्दा होनी चाहिए, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि सर्वसम्मत प्रस्ताव जाये, तीन दिनों तक सदन नहीं चला, सर, यह बहस होती रही कि ''कंडेम'' किया जाये या ''डिप्लोर'' किया जाये। आखिर में अटल जी की सरकार ने कहा कि अंग्रेजी में ''डिप्लोर'' किया जाये और हिन्दी में ''निन्दा'' की जाये, अगर आपको याद होगा। जैसे अमेरिका वालों को ''हिन्दी'' का तरजुमा करना नहीं आता है। यह कूटनीति की कौन-सी अक्ल है जो उस कुर्सी पर बैठने के बाद आ जाती है, चाहे आप लोगों को आती हो, चाहे हम लोगों को आती हो, यह हम नहीं समझ पाये। हम विरोधियों को भी वहीं अक्ल आ जाती है। यह अक्ल हम समझ नहीं पाये कि कैसे इसको हम लोग कर लेते हैं। ''डिप्लोर'' और ''निन्दा'' का फर्क तो अमेरिका वाले जानते होंगे, सब पढ़े लिखे हैं, कोई गंवार नहीं हैं और निन्दा का अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी कर लिया होगा। सबने निन्दा की थी। अमेरिका का राष्ट्रपति एक कंडेम्ड पर्सनलिटी है, इस सदन द्वारा कंडेम्ड पर्सनलिटी है, इस सदन द्वारा निंदित व्यक्तित्व है। क्या किसी condemned personality को वेलकम किया जा सकता है? उसके बाद भी हमारे लोकतंत्र, हमारे सदन और संसद की मर्यादा जिन्दा रहेगी, यह सवाल खड़ा हुआ है - condemned personlality - हमने निन्दा की है, बगल के सदन ने निन्दा की है, सबने एक स्वर में निन्दा की है। इसी का condemned personality कहते हैं। उसके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। सुनते हैं, आगरा आएगा या कहां आएगा, हम नहीं जानते। ऐसे व्यक्तित्व को - क्या होगा, अगर दस रुपए हमें नहीं देगा तो एक वक्त बिना खाए रह लेंगे, स्वाभिमान से तो रहेंगे, अपनी संसदीय मर्यादा की हिफाजत तो करेंगे। हमने एक प्रस्ताव पास किया। बड़े से बड़े आदमी की, जिसकी निन्दा कर दी जाती है, उसके दरवाजे पर और गांव में पानी नहीं पीया जाता। उसका छुआ हुआ खाया नहीं जाता है, निन्दा करने के बाद और उसका हम स्वागत करने के लिए आतुर हैं? क्या इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है, कल्पना की जा सकती है? इस प्रकार हम लोग एक अजीब तरह के विरोधाभास और विसंगति में फंसे हैं, हमारी संसदीय प्रथा भी फंसी हुई है। राष्ट्रपति महोदय ने कह दिया कि अमेरिका से दोस्ती या संबंध सुधारना भारत के लिए अच्छा रहेगा और उसी को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। गांव का आदमी इतना बारीक नहीं जानता है कि लोकतंत्र में क्या-क्या हुआ है। हम अपने को दुनिया का सबसे बड़ा

लोकतंत्र कहते हैं लेकिन क्या यह सही नहीं है कि हम सबसे बेबस और लाचार लोकतंत्र के रूप में जा रहे हैं? बेबस और लाचार लोकतंत्र के रूप में जाना यही होता है कि अपने प्रस्तावों से मुकर जाना। प्रस्ताव पास किया था, आपकी सरकार नहीं थी, इन लोगों की थी, बीजेपी वालों की, लेकिन प्रस्ताव संसद ने पास किया था, इसकी दीवारों ने नोट किया था, इसकी कार्यवाही में लिखा गया है। वह देश की धरोहर है, उसका सम्मान होना चाहिए था, वह नहीं किया गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विपक्ष के कुछ मित्रों से कहूंगा। बात-बात में हिन्दू-मुसलमान के नाम पर आप लोग तुनक जाया करेंगे तो हम लोगों को थोड़ी परेशानी हो जाएगी। किस वजह से पलटन में गिनती का सवाल आया, मैं नहीं जानता, लेकिन नेता विरोधी दल ने वह बात एक दिन उठा दी, सुषमा जी ने उसको और गरम कर दिया, पीछे एक माननीय सदस्य ने हमारे एक सदस्य को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, माहौल गरम हो रहा है। एक बहुत बड़ी तादाद है, उसको अगर यह खबर चली गयी कि अब हमको पलटन में भर्ती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो कितना बुरा हो जाएगा - देश चल नहीं पाएगा। हम लोगों को अपनी हरकत - हो सकता है उससे वोट का थोड़ा-बहुत फायदा नुकसान हो जाता हो - लेकिन अपनी हरकत को कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए मैंने भाजपा के अध्यक्ष से कहा था कि थोड़ा मौका दो, हम तुम्हें सुधारें। हमारे में गलती पाओ तो तुम भी सुधारना। थोड़ा-बहुत अपनी हरकत को कंट्रोल करना चाहिए। मैं केवल सरकारी पार्टी को नहीं कहता, इनको तो कहता ही हूं क्योंकि समर्थक हूं तो विरोधी भी हूं और विरोध भी करता हूं, लेकिन अपने विरोधी मित्रों से कहूंगा। अब खड़ा होना होगा तो आप ही के साथ में इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप यही हरकत करते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कहीं न कहीं कोई ऐसी बात आ जाती है, जिसकी वजह से मन भिनभिना जाता है। यह तो मैं विरोधी पार्टी के लोगों से कहूंगा और आपसे कहूंगा, यह सच है कि हिन्दुस्तान का अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसको रोजगार से जोड़ने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं हुआ, आज भी वह उस दिशा में नहीं जा रहा है, आपका कोई बजट नहीं जाता है। उनको अलग से रोजगार देने का पैकेज तो दिया जा सकता है। अपने वित्त मंत्री को आप समझा सकते हैं कि वे अपनी रोटी के लिए अपने को क्यों असुरक्षित महसूस करें? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जो लक्षण आया है कि संसद और न्यायपालिका, लगता है कि टकराव की हालत में हैं। दोनों के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। यह बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। यह बहुत पहले इंग्लैंड में हुआ था। जब हाउस ऑफ कॉमन्स जनता की चुनी होती थी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसकी प्रिवी काउंसिल भी बनती थी, वह नुमाइंदे होते थे। तो वहां के जज लोगों से हाऊस ऑफ कॉमन्स के जो लोग होते हैं, हमारे यहां तो ऐसी बनावट नहीं है। हमारे यहां तो संविधान ही पहली लाइन में लिखा गया है कि हम भारत के लोग इसको अंगीकार करते हैं। यह लाइन अगर मिटा दी जाए, तो वह डा॰ अम्बेडकर और डा॰ राजेन्द्र प्रसाद की लिखी हुई केवल एक बढ़िया सी किताब होती, वह संविधान नहीं रहता। जब हिन्दुस्तान के लोगों ने यह शपथ ले ली कि हम इसको अंगीकार करते है।, तो वह हमारा संविधान बन गया, वह आई॰पी॰सी॰, सी॰आर॰पी॰सी॰ से बड़ा

1.00 P.M.

कानून बन गया। सर, यह मान्यता पर हुआ करता है। हमारा लिखित संविधान है और भारत के लोगों ने जब अंगीकार कर लिया, तो भारत के लोग देश को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए, संचालित करने के लिए अपना एक नुमाइंदा चुनकर भेजते हैं और वह "लोक सभा" कहलाती है। भारत के लोग कस्टोडियन हैं भारत के संविधान के और कस्टोडियन लोगों ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं संसद में, तो संसद तो बड़ी हो ही जाएगी। लंदन की तरह से बहस यहां नहीं चलेगी, लेकिन बेमतलब के लिए कभी-कभी कोई जज बोल देता है कि फलां कानून बनाकर हम तुम्हें डायरेक्शन देते हैं कि इतने दिनों में हमें बताओ कि किस तरह से पास हुआ, उसका प्रारूप दिखाओ तो हंसी आती है। कभी-कभी हम लोग भी जब आपस में फैसला नहीं कर पाते, तो हम मैम्बर्स यहां से भागकर अपनी रिलीफ के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाया करते हैं। हम समझते हैं कि यह अच्छा लक्षण नहीं है। हमारी खुद की अपनी एक मर्यादा है, हमारी अपनी एक जगह है, हम अपनी जगह पर बहस करके रिलीफ पा सकते है। हम भाग करके अदालत न जाएं और अदालत.....

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): समय कितना लगेगा?

श्री जनेश्वर मिश्र: अदालत बेमतलब के लिए हमको दखल न दिया करे, यह हम चाहेंगे। यह सबसे बड़ा विवाद है।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): समय का थोड़ा सा ख्याल रखें।

श्री जनेश्वर मिश्र: हां, हम ख्याल रख रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय इसके मालिक हुआ करते हैं, वे जजों की नियुक्ति करते हैं। पहले जजों की नियुक्ति का मतलब था कि हमारा विधि मंत्रालय, जो हाई कोर्ट से नाम आते थे, उन नामों में से एक सूची तैयार करता था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से राष्ट्रपति को एक सूची देता था। बाद में माना गया, अपने आप सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों ने तय कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह अंतिम होगी। हमारा विधि मंत्रालय अब जज नियुक्त करने में बेकार हो गया है। बहुत सी जगहें खाली हैं, इस तनाव की वजह से। न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। पूरे बैंच के बैंच खाली हैं, कई हाई कोर्ट्स में। हम दे ही नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय को अपनी इस बेबसी को भी रखना चाहिए था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में इस समय जो अधिकारों को लेकर बहस चल रही है, इस बहस में मेरी भूमिका क्या होगी। यह उनको खुद रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रख पाए और सरकार तो कार्यपालिका होती है, जो भाषण तैयार करती है, वह इनको यह मुद्दा दे नहीं सकी, लेकिन कभी न कभी किसी प्लेटफॉर्म पर इस विवाद को हमें बहस करके हल करना ही पड़ेगा। हम नहीं कहते कि न्यायपालिका को झुका दिया जाए, लेकिन हम यह भी नहीं चाहेंगे कि संसद झुककर चले। दोनों बराबर पर चलें, बराबर की हैसियत से चलें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आप बार-बार समय की तरफ इशाग्र कर रहे हैं। हमारी तबियत भी ठीक नहीं थी, हमको कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बेमतलब रोका-टोका। उनमें से किसी के मन में हमारी गोली से अगर चोट लगी हो, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। मैं किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं बोल रहा था, बल्कि एक बात कह रहा था। अगर एक व्यक्ति को अधिकार दोगे, सर्वोच्च सत्ता पर बैठने के लिए, तो वह व्यक्ति आज एक को रखेगा, कल दूसरे को रख देगा। यह मत करना लोकतंत्र में, यह आपसे कहूंगा। अपने लोगों से भी कहूंगा। पूरा लोक चुनकर भेजता है, तब कहीं लोकतंत्र बनता है और किसी एक व्यक्ति के इशारे पर लोकतंत्र नहीं चलेगा। वह गांधी के इशारे पर नहीं चला, जय प्रकाश, कृपलानी के इशारे पर नहीं चला, आप लोग ऐसा कोई पूजनीय देवी-देवता मत बनाओ कि उसके इशारे पर भारत का लोकतंत्र चलने लगे, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : धन्यवाद मिश्र जी। सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House reassembled at two of the clock

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA) in the Chair

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA): Let us continue with the discussion. Shri Ram Jethmalani.

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Mr Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to extend my support to the Motion of Thanks which this august House is considering. But, Sir, it must be understood that when we ask by a motion thanks for the President, in Constitutional reality, we are asking an approval of the Government's performance in the past and the sincerity of their promises for the future. Judged in this way, Sir, I have no doubt at all that the Motion of Thanks does require to be fully supported for its verty first line which starts with a sense of optimism with which we look forward to the new year.

Sir, the common man looks forward with optimism only when our economic situation is something to be proud about. And, of course, politicians have other criteria of making judgment. One thing must be said that our economic achievement of 5 per cent growth which was available during almost a decade has now risen to 7.5 per cent during the last year and is poised to reach 8-8.5 per cent in the current year. I think, it excites

the envy of the whole world and, certainly, calls for gratitude of the common man in this country.

Sir, I understand, and this figure has not been contradicted by any one, that the savings rate is now over 29 per cent and the investment rate has gone up to 31 per cent. And what is still heart warming is that the inflation rate bears a very benign and a tolerable look.

Sir, the second thing about which I would congratulate the Government, and, therefore, heartily thank the President for his speech is that our democracy has survived all threats and no basic feature of our Constitution has been diluted or tinkered with. A regime of transparency and accountability has been instituted. No longer do we torment those who enter upon sting operations and expose misdeeds happening in any part of the polity. We had the tragic incident of the terrible persecution that my friends in the Telecom went through. I am glad that now we have learned to take sting operation in our stride and even to act upon the results achieved by those sting operations.

Sir, what is still better is that our secularism is safe and the minorities are enjoying now full security of life and property. The spirit of love, mutual understanding, and social harmony now pervades the atmosphere in the country.

The disgraceful events of violence, almost resembling a mini-genocide, which blackened the fair face of Hinduism and the impeccable image of the Indian nation in the international policy, are now beginning to be forgotten as some ugly nightmares never, never to recur again.

Sir, the emphasis on rural development in the shape of the Employment Guarantee Scheme, the Bharat Nirman, and the Rural Health Mission are great measures which, I have no doubt, will reduce, if not completely eliminate, the congestion and crime of our urban areas, the slums and illegal constructions which have been proceeding at a terrific rate, the health and hospital conditions which had been deteriorating for long, and I have no doubt that these will be considerably diluted because now you have decided to make rural life attractive so that it will provide no provocation or impetus for people to migrate from the rural areas into the urban areas and cause the problems which have disgraced us.

I find a very great concern for agricultural development and the need of a regular supply of water for agricultural purposes, and, then, Sir, for

infrastructure development which has impeded Foreign Direct Investment in this country, which has blocked all confidence of investors and other persons who want to come to India to participate in its growth and share its prosperity.

Sir, I have been a person who has been taking some interest in solving the Kashmir problem. I am very happy about the package of Rs. 24,000 crores for Jammu & Kashmir, which has endeared the people of India to the people in PoK and people in other Northern areas where previously the Indian munificence, the sense of brotherhood and friendliness were never understood before. I am glad that this has been done and, Sir, one of the greatest advantages of this package, and, perhaps, some kind of a light at the otherwise dark cloud is the appreciation which the Indian Army has, for the first time, earned from the people in Jammu & Kashmir on both sides of the LoC. Gone are those days when the Indian Army was being rubbished all the time, was being maligned, and was considered a tyrant and an occupying force. Now, they have been perceived as great friends who have participated in the noble task of eliminating the consequences of their disaster. But, Sir, when I say all these beautiful things about the President's speech, I will not be intellectually dishonest and conceal some of the errors, and some of the omissions in this great document. Let me start with number one. Sir, I said that the minorities have reasons to be gratified with the Government and its performance, but there is something which ought to have attracted the notice of the Government and it should have found a place in the President's speech, and that was a some what questionable judgement of the Allahabad High Court, which has declared *ultra vires* a statute of 1981 passes by the same political party's Government which is now in power. They have declared it *ultra vires* and, Sir, they have held that the Aligarh Muslim University is no longer a minority institution within the meaning of article 30 of the Constitution. This has caused, no doubt, great disappointment and dismay to the Muslims of this country. But, Sir, the Aligarh Muslim University is not merely an asset of the Muslim of this country. To my mind, those who are familiar with the teaching of Sir Syed Ahmed should regard this as an institution which is an asset of this great nation. And, if our muslim friends today are unhappy about the Allahabad judgement, eqally, we should share their frustration, we should share their disappointment, and it is time that the Government should, first of all,

extend to them, extend to the whole country, a promise that they are going to fight this Allahabad judgement in the Supreme Court properly. Sir, I speak with great respect for judges, and I have no doubt that the Allahabad High Court judgement is wrong; I have no doubt that it will be set aside on a proper argument being made in the Supreme Court. But, Sir, one never knows after all, the Supreme Court judges are also humans. They may behave the same way as the High Court judges have done. If that is so, this Government should in advance extend an assurance to the community that they will rectify this mistake, under all circumstances. Sir, I, for want of time, answered with a usual reluctance to strike a personal note. When this Aligarh Muslim University (Amendment) law was tabled by the then Congress Government in the year 1981, I remember that on 22nd of December, a debate took place in the Lok Sabha, of which I was then a Member. Sir, I had warned the Government at that time that look, I do not wish to drive a wedge between you and the Muslim voters of this country, but let me tell you as an independent and impartial student of Law that the Bill which you have introduced is going to encounter serious constitutional hurdles, and counter arguments in the courts of law, and it is your duty to rectify those defects. But, Sir, a that time, I was in the Opposition and the Congress men had little faith in me and my assertions, and, Sir, they did not rectify those mistakes at that time. The Bill has now been declared, after 25 years, *ultra vires* the Constitution, precisely for the defects which I had pointed out at that time. I have got the copy of my speech at that time, and I had prepared a draft Bill myself. I had introduced a Private members' Bill at that time. Sir, nobody gave me credit. I wish now the Government should extend an assurance that if we fail in the Supreme Court as well, a new Bill will be brought before Parliament, and we will rectify the errors of the past. Sir, I only want to read four lines from my speech. The Bill does not even pretend to be a bill to restore the minority character of this institution, nor is it designed by the nature of its provisions to achieve that object. It is only intended to throw dust." ...(*Interruption*)...

SHRI ARUN SHOURIE (Uttar Pradesh) Sir, I just wanted to ask this, so that all of us would be enlightened. You have pointed out the defects and Allahabad High Court has, on those very defects, found the Bill to be defective. Then why is the Allahabad judgement wrong?

SHRI RAM JETHMALANI: I am coming to that. Surely, this is too obvious and I must answer it.

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : आप कृपया समय का ध्यान रखते हुए बोलिए।

श्री राम जेठमलानी: साहब, मैं समय का बहुत ध्यान रखता हूं। Perhaps this House is Listening to my speech for the last time. I don't know whether I am going to continue here. Sir, I crave your indulgence, I don't know ...(*Interruption*)...

So, this is what I warned the House about. There were Muslim intellectuals on both the sides. I told them, 'I am surprised that you are not protesting against this Bill, but if you are satisfied with it, who am I to interfere? But my conscience tells me that I must warn you.'

Now, to the question, which my friend, Shri Arun Shourie, asked, the answer is very simple. The Bill was bad, but the Allahabad judgement is worse ...(*Interruption*)...

We act with great restraint when we talk about judgements delivered by the judicial branch. So, I don't wish to be harsh on them. But I had no doubt; I told in a public meeting in Lucknow the other day that 99.9 per cent, this judgement is going to be reversed by the Supreme Court.

When you get into the Indian Airlines planes, they always tell you, 'in the unlikely event of your landing on water...' Now, I do not know how you land on water! They always say what you have to do if you land on water. So, in the unlikely event, when you 'land on water', please do this, and extend this assurance to the community. They would be very happy about it. I am telling you that they are terribly worried.

Sir, the next important point which is second on my agenda is, what happened, unfortunately, in June 1998. At that time, I happened to be the Urban Development Minister in Atal ji's Government. Sir, I know that there was a Home Minister, there was a Foreign Minister, and there was a Prime Minister, But nobody knew that our representative in Rome, at a Rome Conference, where what was being discussed was the creation of an international criminal court, had voted against the creation of that court.

Sir, I have taken much interest in the creation of this international criminal court, because according to me, there are unfortunately states, which are in existence on the globe, on the surface of this earth, which do not genuinely wish to prosecute and punish criminals of an international order. Take, for example, terrorists. There are many States, which still consider that these terrorists are some kind of freedom fighters. They not only

refuse to prosecute them, but also provide asylum to them. And, when they are compelled to prosecute by public opinion, they go through the farce of a trial and the purpose of that trial is only to let them go.

Sir, therefore, an international criminal court was a must. One hundred and twenty one nations of the world voted in favour of its screation. Only seven States, some insignificant ones, voted against it. Twently-one States abstained and India happened to be amongst those twenty-one abstainers. We stood on the fence, not knowing whether we were opposing something, which was required to be opposed or not. I have examined the speech, which our representative had made. It is a disgraceful speech. I do not wish to go into the analysis of that speech. I hope this Government will take note of this great omission made in June 1998.

Sir, after a new months, I became the Law Minister. When I became the Law Minsiter, I tried to find out what had happened to my pet project about the international criminal court. I found that we had scuttled India's position; India was not a party to it! I went around Britain at that time, as the United States had also not supported it.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): That is why you did not support. It is because of that that you did not support ...(*Interruption*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): मनोज जी, आप अपनी बारी आने पर बोल दीजिएगा।

SHRI RAM JETHMALANI: I will allay your doubts; please, don't worry.

Sir, I got in touch with the Lord Chancellor of England. I personally went to see him in London. He promised that Britain would reverse its decision. And I am proud to say that Britain has since acceded. I talked to the Secretary of State of America. The Americans wrote a letter to me that we are considering what you have told us and we will join India in streamlining this Court when you next consider this matter. So, Sir, the great democracies have changed and it is our turn now to change in favour of the creation of this Court. Sir, there is the reference to foreign policy in our President's Speech and what has been said is one of those old shibboleths which we always use that the policy of our country is governed by enlightened self-interest. By adding the epithet 'enlightened self-interest', you don't make it in everybody's interest. But, Sir, when we say this what we forget is, and I have gone repeatedly talked about it and written about it, that our founding fathers in the Indian Constitution knew that they had

to do the unusual job of educating successor Governments, educating posterity how to conduct our foreign policy. They therefore, added article 51 to our Directive Pinciples of the Constitution in which they gave us advice on how India's foreign policy shall be governed by future Governments which will, from time to time, come into power in this country. Sir, these four articles are expressly based upon the teachings of Gandhiji. When the article was introduced, it contained only three clauses. The fourth (*Time-bell*) was added by way of amendment, which Dr. Ambedkar accepted. I am proud to say that the fourth clause was added at the instance of a Member, Mr. B.M. Gupte, from Bombay in those days and he said that you are trying to say that we will avoid war, but do you have an alternative to war. He said that Gandhiji's teachings show that there is an alternative available to war and that is arbitration. Sir, it is very unfortunate that after having added the fourth clause, we will have to see to it that international disputes are solved by arbitration. Leave arbitration alone, we are not even prepared to accept mediation. We are not wanting even the presence of a benign person, a benign mediator, who decides nothing, who only roughens out, who smoothens your rough angles and makes unreasonsable attitude a little moderate and acceptable for compromise. Once we heed Gandhiji that ultimately international disputes must be settled by arbitration, nobody in this country can have the vanity and the foolishness to say that you cannot find an international arbitrator who is honest. There are thousands of honest people available in this country, and now I come to the dispute with China. For the last 45 years, what are we doing? All that we are doing is exchanging maps for 45 years. This dispute can be settled in two years by appointing a Boundry Commission of three reputed jurists of the World. Give them the principles on which we are all agreed and the matter will be resolved. Similarly, Sir, there are problems outstanding with Pakistan including Kashmir, problem which can certainly be resolved and, according to me, it has now reached the stage where it can be resolved by the exercise of a little statemenship and by a little spirit of give and take. If these three countries in this region come to establish friendly and peaceful relations and avoid war, we can dump our nuclear weapons; we can save all that money for the poor men and we can see that war will become impossible. Democracies do not go to war. It was said by German Immanuel Kant many, many years ago and modern research has been conducted in various countries and they have said that wherever the Amercian's -- what is that famous fast food store --

Mcdonald is established, those countries never go to war. It is true. in a way, democracies have not gone to war and one fact is also known that those tyrants and aggressors who have started war ultimately had to eat humble pie and grind their nose in the dust. Sir, can I just take two minutes I have said that the economic picture is good. But I do wish to point out that there is one fly in the ointment. That fly in the ointment is that our external debt is today about Rs. 9000 crores. It is about $ 125 billion. And, our internal debt is another mind- boggling figure. I think it -- my friend knows the figure better -- runs into lakhs of crores. The servicing of these two debts appropriates 72 per cent of our tax revenue. Sir, what is left? The rest goes to bureaucracy; the rest goes to war. Nothing remains for the poor man and all this talk about caring for the poor man, employment guarantee, free education of which my friend talked this morning, all this is a waste. Please liquidate this debt and I appeal to my friends, particulalry him, that allow the Government to liquidate debts by selling its assets. When we will become rich again. we will re-buy them, but at the moment, you must dispose them of and liquidate the debts.

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल): सर, एक मिनट, मैं केवल एक ही सेंटेन्स बोलना चाहता हूं। What we are trying to do is stop the Government from liquidating itself and that is why, we are saying that you save the public assets and don't liquidate them.

SHRI RAM JETHMALANI: You have a great noble object and this will be reflected in your deeds.

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): राम जेठमलानी जी, आप कन्क्लूड करिए।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, next point is you have got the freedom of information, one of your great achievements. But, Sir, I find that the bureaucrats, who are now beginning to execute and operate this Act, have not changed their colours. They are still giving that told plea that Governments can only thrive on secrecy and, Sir, the Right to Informational Act is being reduced by successive bureaucrats to a dead letter and I have instances of it, which I will communicate to the Minister, but I have no time here to go into them.

Sir, we need judicial reforms. There was a reference to judicial reforms.

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): आपके दो मिनट से ज्यादा हो गए हैं।

SHRI RAM JETHMALANI: Judicial reforms can only come by appointing five times the number of current Judges. All these Lok Adalats and others, this is all hype and propaganda. It helps you to liquidate some cases but others keep pilling up and the arrears remain the same. No technology is going to help except marginally. Therefore, I had started working on it when I was the Law Minister. I had said, "If I don't put your judicial system on an even keel within two years, I will retire from all politics." What I wanted to do is published in the form of a book. I hope some Law Minister, some Home Minister have only the courtesy of reading through it and he will get the whole scheme.

And, Sir, lastly, may I say only one word about the demolitions which are taking place all over. It has become a nightmare for thousands and thousands of people. Sir, my simple solution is that please understand that these illegal structures could never have come up without the active co-operation of corrupt public servants. And, Sir, It is a well-known thing; even a LL.B. student knows that a master is responsible for the tort of his servant. Therefore, the State is responsible for the corruption of those officers who allowed these structures to come up. You cannot demolish any structure unless you first make that bureaucrat pay. He must fully pay the price of the structure and rehabilitate all the victims of his own fraud and corruption. It is true that those people who have constructed must also be parties, but people in need of shelter are not free people; free people are the corrupt bureaucrats who take money and allow all these things to happen. And, Sir, I feel that the Government should make an announcement and go to the court and tell them that these structures won't be demolished even if they order unless you have means to rehabilitate those people forthwith and not at an uncertain future.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले अपने-अपने क्षेत्रों के दो महारथी, एक माननीय जनेश्वर मिश्र जी और दूसरे माननीय राम जेठमलानी जी ने अपने विचार व्यक्त किए। हम सभी जानते हैं कि माननीय जनेश्वर मिश्र जी देश के एक जाने-माने समाजवादी हैं और माननीय राम जेठमलानी जी प्रख्यात जाने-माने विधिवेत्ता हैं। इन दोनों के बाद मुझे अपनी बातें कहने में थोड़ी कठिनाई तो महसूस हो रही है, मगर मैं अपने विचारों को, अपनी पार्टी के विचारों को सदन के समक्ष रख रहा हूं। महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय डा॰ कर्ण सिंह जी ने समर्थन का प्रस्ताव रखा। मैं उस प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने प्रारम्भ में ही जिस पंक्ति की ओर सदन और देश का ध्यान आकृष्ट किया, वह देश में जो आने वाला भविष्य है और सरकार की जो नीति है, जो रूपरेखा है उसको प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि हम नए वर्ष के आगमन पर आशावादी हैं। आशावादिता चाहे किसी समाज की हो या राष्ट्र का हो, एक बहुत बड़ी चीज होती है। उस उम्मीद पर कोई समाज, कोई राष्ट्र अपना महल खड़ा करता है और धीरे-धीरे अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से उस महल को तैयार करता है। महोदय, राष्ट्रपति जी की यह बात सरकार के संकल्प को और विश्वास को प्रदर्शित करती है। इसका सबसे पहला प्रमाण जो इस अभिभाषण में मिला है और जिसकी ओर कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है और उसके संबंध में कहा है कि 1999-2003 में विकास दर 5 प्रतिशत, 2004-2005 में विकास दर 7.50 प्रतिशत और आशा है कि 2005-2006 में यह वृद्धि दर 8 प्रतिशत तक जाएगी। महोदय, यह राष्ट्र के लिए भी और सरकार के लिए भी उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। राष्ट्रपति जी ने एक और बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा-राष्ट्र को विभाजित करने वाली चर्चाओं के स्थान पर हम ऐसी चर्चाओं को चलाने में सफल रहे हैं जो लोगों की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करती है और जो आम आदमी से जुड़े मुद्दों से ताल्लुक रखती है।

महोदय, अगर हम अपना पूरा समय, पूरी क्षमता, पूरी ऊर्जा राष्ट्र को विभाजित करने वाली जो ताकतें हैं, उन ताकतों को रोकने में लगाएं तो अच्छी बात है और उन्हें रोकना चाहिए जो राष्ट्र को विभाजित करने वाली ताकतें हैं। मगर साथ-साथ हमारा ध्यान जो आम जनता की समस्याएं हैं जैसे गरीबी उपशमन की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, रोजगार की समस्या जो मौलिक अवसर हैं, सुविधाएं हैं उनकी सुविधा और ग्रामीण विकास जैसे बुनियादी समस्याएं हैं, उनकी ओर.....।

(श्री उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

ग्रामीण विकास जैसी बुनियादी समस्याएं हैं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इनकी ओर जनता का ध्यान दिलाया गया है। महोदय, पांच स्तम्भों की बुनियाद पर विकास का एक मजबूत महल खड़ा करने की बात कही गई है। महोदय, गरीबों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। आजादी के 58 वर्षों के बाद भी इस देश में अभी भी एक-चौथाई लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, अभी भी हम उनको आर्थिक सुरक्षा नहीं प्रदान कर सके हैं। रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बुनियादी चीजें हैं, जो देश के सभी नागरिकों को चाहिए। मगर आजादी के 58 वर्षों के बाद भी हमने गरीबों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

महोदय, इस दिशा में यूपीए गवनमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम को सरकार ने पास किया है। ग्रामीण क्षेत्र के अभी 200 जिलों को इसमें चुना गया है, एक परिवार को सौ रोज़ का रोजगार दिया जायेगा और अगर उसको रोजगार नहीं दिया जायेगा, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। महोदय, जैसी मेरी जानकारी है, देश में 593 जिले हैं। हमने शुरू में 200 जिलों से प्रारंभ कर रहे हैं। जो पिछड़े जिले हैं, जो अविकसित जिले हैं, उनसे इसे प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है और ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उन्हें इस कार्यक्रम से बड़ा लाभ मिलेगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया जाये।

महोदय, एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना भारत निर्माण की योजना है। सरकार ने इसे पूरा करने का 2009 तक का लक्ष्य रखा है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन, मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान जैसे सर्वोन्मुखी एवं विकासेन्मुखी कार्यक्रम हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं, कि राष्ट्रपति जी का यह अभिभाषण देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए संकल्पित भाषण है। महोदय, मैं जिस कानून की बात कर रहा था, वह ऐतिहासिक कानून है, वह क्रांतिकारी कानून है इस देश के लिए, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कानून कहते हैं। महोदय, रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान जिसकी मैंने चर्चा की, इसके अलावा देश में सड़क, बिजली, पानी ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से देश बनता है, समाज बनता है। इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर है। जिस देश में ये तीनों चीजें होंगी, उस देश का विकास तेजी से होगा।

महोदय, भारत निर्माण का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में प्रत्येक गांव को बिजली उपलब्ध करवाना है। हम सभी जानते हैं कि बिजली की समस्या इस देश में बड़ी समस्या है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंचा सके हैं। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाना सरकार का महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। गांव में सड़कें नहीं हैं, एक हजार या उससे ज्यादा आबादी वाले जो टोले हैं, जो गांव हैं, उनको मुख्य सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है। पेयजल सुरक्षित करना–मैं फिर कहना चाहता हूं कि आजादी के 58 वर्षों के बाद भी हम पीने का शुद्ध पानी सभी लोगों को मुहैया नहीं करा पाये हैं। मैं किसी खास सरकार की बात नहीं कर रहा हूं–एनडीए की सरकार भी इसी बीच में आई, इससे पहले एक दूसरी सरकार थी, मगर यह हमारे लिए दुख की बात है कि हम अभी तक शुद्ध पानी भी लोगों को पीने के लिए मुहैया नहीं करा पाये हैं। महोदय, टेलीफोन हर गांव को उपलब्ध कराने की बात है लेकिन टेलीफोन से पहले, मैं समझता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य–ये सारी बातें हैं–टेलीफोन को मैं बाद की बात मानता हूं। एक करोड़ हेक्टेयर में

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना। महोदय, इस देश की अर्थव्यवस्था में बरसों पूर्व खेती का 51 प्रतिशत योगदान होता था जो आज 22 प्रतिशत पर चला गया है–खेती की यह हालत है। किसान हैं, पलायन कर रहे हैं। खेती अब लाभकारी नहीं रह गयी है। अगर नौकरी मिल जाती है, छोटी नौकरी मिल जाती है तो वह खेती छोड़कर चपरासी तक की नौकरी करने चला जाता है। यह स्थिति खेती की हो गयी है। एक बड़े भाग में अभी भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फिर बाढ़ आती है। मैं बिहार से आता हूं। उत्तरी बिहार के 15 से 20 जिले ऐसे हैं, जहां हर वर्ष बाढ़ आती है। नदियां नेपाल से आती हैं, हमारा उस पर नियंत्रण नहीं है। मैं जानता हूं कि कई वर्षों से इस पर वार्ता चल रही है मगर अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। बिहार में एक बूंद पानी नहीं पड़ता फिर भी घंटे, दो घंटे के बाद बाढ़ आ जाती है–एक बूंद पानी नहीं पड़ा फिर भी बाढ़ क्योंकि वह पानी नेपाल से आता है नेपाल मे पानी पड़ता है नेपाल से बाढ़ चलती है बिहार में बाढ़ चली आती है और कई हजार करोड़ रुपये का जान-माल का नुकसान होता है फसल का नुकसान होता है यह सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है कई ऐसे राज्य है असम है उत्तर प्रदेश है कई ऐसे राज्य है जहां नदियों में बड़ी बाढ़ आती है। उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। महोदय, आवास की भी बड़ी समस्या है। करोड़ों लोग सड़कों पर सोते हैं और गांव में उनके सोने के लिए अपना घर नहीं है, कॉमन दरवाजा गांव में होता है वहां सोने के लिए जाते हैं या किसी बड़े आदमी का दलान है, दरवाजा है वहां सोने के लिए जाते हैं, उनका अपना घर नहीं है योजना है कि ग्रामीण निर्धनों के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण करना है यह अच्छी शुरुआत है कि हम उन्हें रहने के लिए एक घर दे रहे हैं यही हालत स्वास्थ्य की है आप गांव में चले जाएं, कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो उसका गांव में इलाज नहीं होता । प्राइमरी सेंटर्स हैं पर कहीं मकान नहीं है, कहीं इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कहीं डॉक्टर नहीं है–यह कठिनाई है गांव में रहने वाले लोगों के साथ। आज भी साठ से सत्तर प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। गांव में प्राइमरी सेंटर्स खोलने हैं वहां डॉक्टर भेजने हैं। यह एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने बनायी है - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन । महोदय, मैं एक बात से सहमत हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र कह रहे थे कि यहां एम्स है बिहार के, नेपाल के, उत्तर प्रदेश में तो एक हॉस्पिटल है, काफी दूर से इलाज के लिए लोग आते हैं। एक योजना बनी थी जिसके अंतगर्त 6 अस्पताल एम्स की तरह के खोलने हैं- बिहार में भी एक अस्पताल खोलना है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो 6 अस्पताल खोलने हैं, उन अस्पतालों को खोलने की ओर सरकार ध्यान दे। एम्स में बहुत अधिक भीड़ होती है। महोदय, हम लोगों के पास रोज दो, चार, पांच, दस पेशेंट आते हैं और वे कहते हैं कि आप हमें पत्र लिख दीजिए, हमें इलाज कराना है लेकिन हम जानते हैं कि इतनी भारी भीड़ जहां होती है, वहां अगर मैं पत्र लिखता हूं तो एक तो पत्र देखने का उनके पास समय नहीं है दूसरी बात, अगर सिर्फ ऐसे पत्र लाने वालों का ऐडमिशन होगा तो बाकी लोगों का

क्या होगा? यह स्थिति एम्स की है। अगर आपको कभी एम्स जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि एम्स का जो बरामदा है वहां पर लोग सोए हुए हैं जो दो-दो, तीन-तीन दिन तक वहीं रहते हैं। इसीलिए जो 6 अस्पताल खोलने हैं, उन्हें शीघ्र खोला जाए। दूसरे राज्यों में भी एम्स की तरह अस्पताल खोलने चाहिए। महोदय, सर्व शिक्षा अभियान भी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। छोटे- छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप-आउट्स के बारे में आपको जानकारी है ऐडमिशन होता है पहले दर्जे में, दूसरे, तीसरे, चौथे और दसवें दर्जे तक जाते-जाते ड्रॉप-आउट्स की क्या हालत होती है? क्यों नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं?

मैं जनेश्वर मिश्र जी को सुन रहा था। बहुत अच्छी बात वे बोल रहे थे, सबको एक-समान शिक्षा मिलनी चाहिए। यह नारा काफी समय से है। बहुत समय से हम लोग यह नारा लगाते हैं। इस समय शिक्षा मे बहुत अंतर है। डी.पी.एस. मे पढ़ने वाला जो बच्चा और हिंदुस्तान के किसी देहात में पढ़ने वाला जो बच्चा, क्या वह डी.पी.एस. मे पढ़ने वाले बच्चे का मुकाबला कर सकेगा? गांवों में अच्छे-अच्छे स्कूल खोले जाएं। चूंकि उनके पास आर्थिक साधन नहीं हैं कि वे शहर में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, इसलिए वे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिलती है और मजबूर होकर बचपन में ही उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं, जब उसके हंसने, पढ़ने-खेलने के दिन होते हैं। मजबूरी और जबरदस्ती उनको फैक्टरी में जाकर लेबर के रूप में काम करना पड़ता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: भंडारी जी, दो-तीन मिनट में समाप्त कीजिए।

प्रो. राम देव भंडारी: महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। किसानों की समस्या के बारे में भी चर्चा हुई है हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। बड़े दुख की बात है, बहुत पीड़ा होती है कि जो किसान इस देश की रीढ़ रहा है, वह किसान आज आत्महत्या कर रहा है। बड़े-बड़े सूदखोर महाजनों के चंगुल मे फंसकर, वह आत्महत्या कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों नहीं उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं? आज 8-9 परसेंट ब्याज दर पर उनको ऋण दिया जाता है। ठीक कह रहे थे कि गाड़ी खरीदने के लिए 6 परसेंट पर ऋण देते हैं। वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि उसकी वसूली पक्की रहती है, इसलिए उसको ऋण देते हैं। एन.पी.ए. की वसूली क्यों नहीं होती है? किसानों को क्यों नहीं हम कम ब्याज दर पर ऋण दे सकते हैं? क्यों इस देश का किसान आत्महत्या करता है? यह सोचने की बात है, यह चिंता की बात है। इस देश का किसान आत्महत्या न करे, उसे कम ब्याज पर ऋण मिले, ऐसी व्यवस्था हमें करनी है।

महोदय, मैंने कृषि के बारे में चर्चा की । फसल बीमा योजना सरकार ने लागू की है। इस देश में फसल की कोई गारंटी नहीं है। पकने का समय आएगा, उस समय भी कोई ऐसी बात हो जाएगी

कि वह फसल अपने घर नहीं ले जा पाएगा। उनकी सारी पूंजी, सारी मेहनत बेकार चली जाती है। फसल बीमा योजना सरकार को पूरे देश में लागू करनी चाहिए।

महोदय, इस देश में 13 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम हैं और कुछ अन्य अल्पसंख्यक हैं। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है। हमें उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वे इस देश की मुख्य धारा में हैं, हमारे साथ हैं। हमें एक बार सर्वेक्षण कराना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है? न्यायमूर्ति सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उनकी हालत सुधारने की दिशा में काम करेगी।

महोदय, बी॰जे॰पी॰ के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी पहले दिन बोल रहे थे और कल पूर्व अध्यक्ष बोल रहे थे। कुछ अच्छी बातें राजनाथ सिंह जी के मुंह से निकलीं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और पदों की गरिमा तेजी से घटी है। निर्वाचन आयोग पर गर्व है। उन्होंने बिहार का भी reference दिया था। सभी को गर्व है संवैधानिक संस्थाओं पर जो निर्वाचन आयोग है, उस पर गर्व है। लेकिन मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि गुजरात का चुनाव हो रहा था और माननीय लिंगदोह जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, क्या उद्गार प्रकट किए थे, उस समय जो मुख्य मंत्री थे गुजरात के, उन्होंने क्या उद्गार प्रकट किए लिंगदोह जी के बारे में। भूल जाते हैं आप। आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब आपके पक्ष में कोई बात होती है तो आप गर्व करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो उसको गाली देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा किसने घटाई? किसने बाबरी मस्जिद के बारे में आश्वासन दिया था, सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर और फिर क्या हुआ? आपने पिछड़े वर्ग के मुख्य मंत्री को जेल भिजवा दिया। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप चेयर को एड्रेस कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): अगर माननीय सदस्य इधर मुंह करेंगे तो हमको भी कुछ बोलना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: आप मेरे मित्र हैं इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप हमको सुनाइए, हम सुनेंगे।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, जब राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने चर्चा की। एक यूपीए के मिनिस्टर्स हैं, उनके बीच में नोक-झोंक होती है, आपस में झगड़ते हैं। बीजेपी में क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: क्या हो रहा है, वह सब छोड़िए।

श्री कृपाल परमार: सर, प्वाइंट ऑफ आर्डर। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ...(**व्यवधान**)... बी॰ जे॰ पी॰ का नाम लेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: यहां बीजेपी कहां हैं? ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, बी॰ जे॰ पी॰ में क्या हो रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: यह सब छोड़िए। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलिए, बी॰ जे॰ जी॰ के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): बिहार में क्या हुआ? ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैं वह भी बता रहा हूं। पिछड़े वर्ग की एक बहादुर नेत्री को किस प्रकार अपमानित करके निकाला?

श्री उपसभापति: वह यहां की मेम्बर नहीं है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: आप बिहार की बात कर रहे हो, वहां पर हम कितने वर्ष राज किया है, 15 वर्ष राज किया है। ...(**व्यवधान**)... आप तो पांच-छः वर्ष भी राज नहीं चला सके। (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: शी इज़ नॉट ए मेम्बर ऑफ् दिस हाउस।

प्रो॰ राम देव भंडारी: आपने तो छः वर्ष भी राज नहीं चलाया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: छोड़िए यह सब। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, ये कहते हैं कि अगली बार अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो कल्याण सिंह मुख्य मंत्री बनेंगे। वहां पर उनकी सरकार बनेगी ही नहीं। एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ ठगने की बात हो रही है। यदि सरकार ही नहीं बनने जा रही है तो कल्याण सिंह मुख्य मंत्री कैसे होंगे? अगर सरकार बनती है तो माननीय राजनाथ सिंह जरूर चीफ मिनिस्टर बन जाते।

श्री उपसभापति: भंडारी जी, आप समाप्त कीजिए। समय बहुत कम है। अभी तीन-चार और हैं। क्योंकि हमको यह डिबेट 6.00 बजे तक खत्म करनी है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में रेल व्यवस्था के बारे में जो कहा है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: जब रेल बजट आएगा तब आप रेल बजट पर बात कीजिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, उन्होंने कहा है, यह इसमें है।

श्री उपसभापति: इसमें तो है मगर आपको अपोर्चुनेटी मिलेगी तब।

प्रो॰ राम देव भंडारी: अभिभाषण में है, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। उन्होंने कहा है कि एक बार रेल फिर अत्यधिक गर्व का स्रोत बनी है। मैं दोहराता हूं कि रेल व्यवस्था एक बार फिर अत्यधिक गर्व का स्रोत बनी है। सरकार ने बीस हजार करोड़ से अधिक का निवेश करके उच्च क्षमता वाले दो समर्पित माल कॉरिडोर-लुधियाना से सोननगर तक का पूर्वी कॉरिडोर का और जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास से दादरी तक का पश्चिमी कॉरिडार बनाने का निर्णय लिया है। एक वर्ष के अंदर इन परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। महोदय, अभी थार एक्सप्रैस का भी उद्घाटन हुआ है। यह एक्सप्रैस हिन्दुस्तान से पाकिस्तान जाती है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री कृपाल परमार: महोदय, यह परियोजना एक वर्ष में पूरी हो ही नहीं सकती। अभिभाषण में लिखा है कि एक वर्ष में शुरू की जाएगी।

श्री उपसभापति: जैसे रेलवे चलता है, वैसे ही चलेगा।

प्रो॰ राम देव भंडारी: थार एक्सप्रैस का अभी 18 तारीख को उद्घाटन हुआ है। यह रेल सेवा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने की दिशा में, दोनों देशों को नजदीक लाने की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है। इसलिए इसकी सराहना करनी चाहिए। इतना ही नहीं 150 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से ट्रेन चलाई जा रही है। यह रेल मंत्रालय की अभूतपूर्व उपलब्धि हुई है। पहले रेल मंत्रालय में घाटा ही घाटा होता था। हम बिना किराया बढ़ाए मुनाफा की ओर जा रहे हैं। यह सरकार बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, दृढ़ता और विश्वास के साथ जनता की सेवा कर रही है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अपनी पार्टी की ओर से तथा अपनी ओर से, मजबूती से समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I am supplementing this debate which my colleague, Shri Nilotpal Basu, has initiated. He has covered most of the points. I will be suplementing the same. In-between, there were certain points which were raised regarding the type of support, when we would bite, when we would bark, and so on and so forth. In this context, I would like to invite your kind attention to para 3 of his Address — I think, which is the major essence of the Presidential Address as I could see it:

> "Confidence in India, in our democracy and in our economy, has never been higher."

We have a reservation so far as the economy is concerned, but we have no doubt when he says, "We have been able to restore the pluralistice ethos that is the essence of India." I think, that is one of the issues, one of the the major points on which a Government has been changed and a new Government has come to power. But he also says in para 3 — and I quote, Sir:

> "We have been able to replace debates that sought to divide the nation with debates that matter to every day living of the people, dabates on issues of concern to the *aam admi.*"

Sir, if there is anything, so far as our support to this Government is concerned, for which we extend our support, we feel that this is the one point where we have been able to put our support in concrete terms. This is concerning the people's movements. This is the point, Sir. If someone goes into it then he can explain our stand, when we support, and also when we oppose. One point was very clear — it is of no use repeating that point. I am not going to react to that business at all why the NDA Government lost — that the NDA Government lost power. That is now history. What is our stand in future, what we feel, what is our perception, we have been making that very clear to this Government. The point is if you continue the same policies, so far as the economy is concerned, that the NDA Government had been following, you will have the same fate, and we cannot be a party to that. This is the major perception. Now, the point arises — Venkaiah Naiduji spoke very well—about the rate of P.F. interest. That is one of the redeeming points, Sir. Venkaiah Naidu spoke yesterday about the rate of P.F. interest of 8.5 per cent; I was so elated, Sir. For six years, I have not heard. When it had come down from 12 per cent to 9.5 per cent, it was not raised. yesterday, there was a debate on interest rate to farmers that—Mr. Chidambaramji was there and the House was together that the interest rate should come down, so far as the farmers are concerned. This is what 'the barking' means, or this is, what you say, 'the biting' means. That is what we want; yes. For six years, no one spoke when P.F. interest came down from 12 per cent to 9.5 per cent. I am happy Mr. Venkaiah Naidu has also understood. Now, it has come down. The Provident Fund interest rate has come down from 9.5 to 8.5 and there is a debate against

it. This was what we wanted. Now what does it mean? If you say what it means, इसका मतलब क्या है? 'Bite' कब करेंगे? अगर 'bite' करने का मतलब यह है, 1996-97 में Sir, there was a saying around "Old man in a hurry." तब एक सरकार को गिराने का चक्कर था. Now also, some old man is in a hurry! We know that. Unfortunately, we cannot oblige them. हम चाहते नहीं हैं। As a major opposition party, मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि वहां इसी चक्कर में BJP कोई गृहयुद्ध हो कि कौन बनेगा प्रधान मंत्री, यह हम नहीं चाहते हैं। हमारा समर्थन है मुद्दे पर और हम इसके बारे में यही कह रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, please do not try to hug that king of perceptions. अगर cadre को encourage भी करना है कि by default you are going to rule, आपको default में हम rule करने नहीं देंगे, पर Congress को चैन से भी rule नहीं करने देंगे unless you follow the Common Minimum Programme. What is our mandate? What is our support? Our support is not for any change of photos or for change of posters; our support is not to the Congress Party is as it is. Our support is to the National Common Minimum Programme, as long as they do not violate it, as long as they do not try to change the priorities. Where have we the problems? Sir, what does para 2 say? I repeat, Sir, if you say *aam admi* then you will have to speak in *aam admi's* language, and I like Raj Nath Singh's speech. आटा, गेहूं, चावल, दाल, केरोसिन, बिजली, इनकी कीमतों पर बात कीजिए, ये सब फिगर्स हमको कैसे मालूम हैं बताइए?

Para 2 says:

> "The rate of inflation has remained at modest levels despite a sharp rise in global energy prices."

I understand global energy prices. आम आदमी क्या समझता है? 14 essential commodities in the country. If you are a Government of *aam admi* then come out with the prices of 14 essential commodities. If this a Government of *aam admi,* then come with the prices of 14 essential commodities and say प्राइस कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ये बोलेंगे मेरे टाइम में 8.5 परसेंट ग्रोथ, फिर बोलेंगे 8 परसेंट, 10 परसेंट, यह सब शौरी जी जैसे लोग समझ सकते हैं, हमारे जैसा आदमी कैसे समझेगा, सर। क्या प्रेसिडेंशियल स्पीच में आम आदमी को प्रायरिटी है? But, I am afraid, it is not there. I may just mention that एयरपोर्ट की बात डा॰ कर्ण सिंह जी ने कही. It is not a question of airports. When is there a debate in the Parliament? Let there be a debate. As regards the Women's Reservation Bill, they are supporting. We are supporting. So many parties are supporting. One or two parties

3.00 P.M.

are not supporting. Everyone is supporting. Still because of reservation, it is mentioned in the President's Address that it will be done in the near future. It will be done in the near future. That is not the priority. But एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप जो भी बात बोलिए, we are opposing. We may be wrong. But we, the Left, are opposing it. किसी के सर की कसम दे रखी है कि 31 जनवरी तक करना है। यह किसका कमिटमेंट है? Which commitment forces the Government to go in for it when two major parties or allies are opposing it? I would like to know it. That is why I talk about infrastructure. What we don't like, we will tell you. हम आपको चैन से नहीं जीने देंगे, आपको पार्लियामेंट के पास आना पड़ेगा। Why did you say that? I am not talking about privatisation. I know, as far as the BJP is concerned, they are master of inconsistencies. But I am sure, both sides agree that on our points we have been consistent. Even if we are wrong, we have been consistent. We have not changed. They have been the master of inconsistencies. But I am asking the Congress Party, you were in powe from 1991-96. There was no coalition, no CPM. What did you do? You enacted the Airports Authority Act, 1994. The Prime Minister must answer this. He was the Finance Minister then. I am reading out from the Statement of Objects and Reasons of the Airports Authority of India Bill, 1994. At that time, Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai were under the International Airports Authority of India. Rest of the airports were under the National Airports Authority. They were merged and they were merged through an Act of Parliament by the Congress Government. What did they say in the Statement of Objects and Reasons in 1994? It is not pre-reform; it is post-reform. It says, "International airports are put to more intensive use and generate substantial cevenues which accrue to IAAI. Revenues of NAA—it means non-metro airports—are much less buoyant because a number of its airports do not have commercial air service..... To overcome this handicap and provide for closer integration in the management of airports and air traffic contract services in the country, it has been found necessary to merge the IAAI and the NAA" to make the Airports Authority of India. Today, the same Finance Minister is our Prime Minister. I have got a lot of respect for him. But, why is this inconsistency? It should be clarified in the Parliament. Today, you are saying just the opposite. Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai have to be separated so that the other non-metro airports can be developed. Why? It should be clarified. The debates and proceedings should take place in the Parliament. Should it be clarified in the Parliament or in the Delhi High Court? Some Johnny

bidder or XYZ bidder goes to the Delhi High Court and I have to look at them. The Secretary-General is here. I want to raise some point. Should I go to the Delhi High Court? I want this discussion to be here in the Parliament. It is transparency. What type of public-private partnership is required? Yes, it is required. Private sector is necessary to supplement investment efforts. What are the figures? Should I give the figures. In Dabhol, which has been revived, the cost is Rs.10,000 crores. The settlement has been done. Has it come to the Parliament? Mr. Ramachandraiah has raised a query. It must come to the Parliament. One of the things which this new Government is committed to, and we are supporting, is transparency. Why has settlement been done without taking the Parliament into confidence? This Rs.10,000 crores is public money. The NTPC is going to give Rs.500 crores; GAIL is going to give Rs.500 crores; the financial institutions are going to give another Rs.500 crores to revive an asset which is unviable. You are going to invest Rs.10,000 crores. Rs. ten thousand crores and others are financial institutions.*'दाभोल' करके चले जाएं,* अनवॉयबल हो जाए,* पार्टनरशिप हमको नहीं चाहिए in the name of public-private partnership. In airport also, I am giving you the figures. Sir, let the Prime Minister come and speak, clarify. He says the investors' confidence will be affected if we go back. Which is the investor? How much investment? I am giving you the figures. In Delhi airport, estimated capital expenditure for the next six years is Rs. 3000 crores. Nine hundred crores is the equity. Out of which the private investor is bringing Rs. 500 crores and the foreign investor is bringing Rs. 180 crores. From where is the rest of the money coming? Rs. 2150 crores is from financial institutions and public sector banks. This is also * 'पार्टनरशिप in the name of public-private partnership, we will not stand, we will fight in the Parliament and outside the Parliament.This will be and that is why I am offering you through this speech. We had given a notice for a discussion on this under rule 170. I was checking with Mr. Venkaiah Naidu. He said transparency. But do you support privatisation? He said, 'yes, I support.' That means let that be clear. Let it be clear. Lord Meghnath Desai, उनका कुछ चक्कर है, वे जानें। वह एलायंज़ अगर formalise हो रहा है Let it be clear in the Parliament. Under Rule 170 if we have not spared Arun Shourie, we are not going to spare Mr. Manmohan Singh. That is like BALCO. We want a discussion on airport under rule 170 and I am sure the Government will come out with a

* Expunged as ordered by the Chair.

permanent discussion on this. My second part is on power. Again I am worried. With this will end? I will not take much time. Sir, on this issue we want to be clear on Cong-BJP Correlation. When he says we get alarmed, it is on these issues and on the Iran issue, BJP supports. On Pension Regulatory Bill, I see a 'master' of inconsistencies. Pension Regulatory Bill, on the morning when the Bill was introduced, I was called by a Delhi Channel. There, Shri Yashwant Sinha said, 'we will support it'. The next day probably there was some problem in the Parliament. Shri Vijay Kumar Malhotra said, 'no, no, we will join in the Protest. I am not giving that much importance to this. But people must know on these issues what exactly the Parliament is thinking about. That is what the President should say. Para 6 says, 'to provide electricity connection to every village....'. It is very important. Again, we are repeating, '...provide electricity connection to every village. I think Government they said in power policy, 'in the country, the objective should be to provide electricity connection to the households'. We have seen this situation in every village. Poles are there. 87 per cent of the villages are electrified. But actually only 40 per cent of the households are electrified as per the latest figures. Whereas villages are 87 per cent. Our ambition is to have 87 or 100 per cent village electrification. Then under the Employment Guarantee Act, we are giving Rs. 60 as minimum wages. Is the cost of power to do anything with the availability of power? How many of these households can afford Rs. six or seven per unit cost? You were saying that 2003 Electricity Amendment Act would solve all the problem. Then NDA would have solved all the problem. Why couldn't they assure the village people that village electricity is available, वह एक्ट दिखाने से हो जाएगा? From 1994 onwards, we have been hearing that the independent Power Producers will solve the electricity problems. Ten years have passed. Some changes in thoughts, some changes in direction of thinking in economic policies we feel is necessary if this Government has to stick to implementing Common Minimum Programme. This is the fight; this is the struggle which will continue. किसकी कुर्सी बदलेगी, किसकी कुर्सी आएगी, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। What we are interested is: this is peoples' issue, we will go to the people. We will get it discussed here and outside and our support will be depending on what you perform, what we perform on these issues and I am sure these issues must be discussed. Parliament should not be kept in the dark. I have spoken on Dhabol issue. I have spoken on airport issue.

You have changed from this. You are saying, 'we will make world-class airports'. In the Presidential speech it is mentioned, Government intends to make world-class airports. Sir, Parliament has been taken for a ride! Here is the Annual Report of AAI for 2002-03. You can see it from 1995 onwards. This is the Annual Report of the AAI. What is its Corporate Mission? The whole of this tenet and everything is misguiding the whole country. This is the Corporate Mission of the AAI, 'Progress to excellence, customer satisfaction with world-class airports.' This Report was laid on the table of both the Houses of Parliament. When the Government — whether this Government or that Government — changed this Corporate Mission? If they have changed this Corporate Mission, have they come to Parliament? Without coming to Parliament, today, you will say that AAI cannot make a world-class airport. What is the transparency? What are we discussing? What for Parliament is there? So, I still demand that on this particular issue we have a serious difference with the Government. The Government must agree for a discussion under Rule 170 with regard to airport. Thank you very much.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Motion moved by esteemed senior colleague, Dr. Karan Singhji and seconded by Shri Rashid Alviji.

Sir, the Address of the hon. President truly reflects the outstanding performance of the UPA Government, led by our dynamic Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji, by getting inspiration and excellent guidance from our esteemed leader, Smt. Sonia Gandhiji, has single-handedly given a severe blow to the communal forces of the country and will continue to do so. In all our programmes and schemes, the focus is on common man. From late Prime Minister, Pandit Jawahar Lal Nehruji, to Dr. Manmohan Singhji, our focus has always been on the common man. There is a consistency in our policies towards the poor.

Sir, hon. President has rightly said that our economy has bounced back by recording 7.5 per cent growth in 2004-05 and this year it will cross 8 per cent. Though inflation has remained at modest level, rising prices of some essential items like wheat, pulses, sugar and edible oils, etc., are certainly a cause of concern. It has upset the budget of housewives like me. I hope the Government will take appropriate steps to contain the

rising prices. These days media is full of reports that rates of domestic LPG cylinder will go up by Rs. 150. It has worried households across the nation. I hope the Government will clarify to put speculations at rest in this regard.

Sir, hon. President has rightly stated that the National Rural Employment Guarantee Act makes a new beginning in our country towards guaranteeing the right to work. Presently, this Act will be implemented in 200 under-developed districts, but soon it would be implemented throughout the country which will provide jobs in the villages. While providing jobs in the villages, assets would be created. Here, I would like to give one suggestion to the Government. While creating assests, efforts should be made to construct personal toilets in every household of the village, keeping women and girls in mind. In the absence of toilets, the women and girls are forced to attend the call of nature in the open, be it in fields or adjoining areas. They wait for the sun to set and in the darkness they are bitten by snakes, Scorpios and other beasts and, sometimes, they may also lose their lives due to poisonous bites. And, sometimes, they become victims of rape and molestation. Hence, household toilets should be given priority in asset creation. Linking of water conservation with this programme is a welcome step. Since ground water level has gone down and the drinking water in the villages become a problem, linking of water in this programme is a welcome step. This will ease the driniking water problem in the villages.

Another laudable programme of our Government is the launch of the National Rural Health Mission to provide basic health care to rural masses. Mission approach, with time-bound targets, was first launched by late Shri Rajiv Gandhi. This Government has also launched many such schemes in social sectors which are to be appreciated. The National Rural Health Mission has been launched to bridge the health gap in the rural sector. I hope this Mission will take care of the health-related worries of women and girls in the villages. Many a times, I have raised this issue in the House through Special Mentions demanding posting of lady doctors and Gynaecologists in the health centres in villages so that girls and women can go freely and relieve their personal problems to the doctor. I hope this Mission will take care of providing maternity services and so on to the women folk in the villages.

Sir, I welcome the National Agricultural Insurance Scheme. It is being

expanded to cover risks in agricultural operations. I also demand that the Compulsory Marketing Intervention Scheme should be made compulsory to protect the farmers when they grow bumper crops resulting in steep fall in the prices of commodities forcing the farmers to bur their crop or abandon it in the fields or throw it on the roads. It happened recently in Karnataka that when tomato prices fell, lorry loads of tomatoes were thrown on road. So, to protect the farmers from such crisis, this Compulsory Market Intervention Scheme should be implemented.

Sir, I welcome the statement that the National Highway Development Project is being implemented on a national priority. There are some hurdles, in implementing highway projects, such as land acquisition by States, environmental clearance, forest clearance and so on, thus hampering the growth of national highways. Sir, the Government has to remove these hurdles on priority.

No doubt the Right to Information Act is a historic piece of legislation. It has given a right in the hands of the people, but misuse of this legislation has also started. Recently, I came across this fact that a single individual of an NGO is collecting same information from all the public sector banks regarding their precious data which can be very useful for private banks to compete with our public sector banks. I hope the Government will ensure that the Right to Information Act will not be misused for personal benefit and will provide penal provisions for its misuse.

I congratulate the Government for taking much care of women and children. As far as women are concerned, Sir, much care has been taken in cases of inheritance rights, domestic violence, adoption and maintenance laws, and proposal for compulsory registration for marriages etc.

The UPA Government, under the leadership of Shrimati Sonia Gandhiji, is committed to empower women politically, educationally, economically and legally. There is a need to enact the Women's Reservation Bill.

As far as children are concerned, Sir, the Government has enacted the Commission for Protection of Child Rights Bill, 2005. Through this legislation the Government envisages to fulfil its commitment to give children opportunities and facilities to develop in a healthy atmosphere with required freedom and dignity. It also ensures that their constitutional and legal rights are protected. Sir, the enactment provides for a National Commission

for Protection of Child Rights. Further for the development of children, a national plan of action for children is expected to be finalised soon. The Government is also planning to establish 30,000 creches for children to help the working women. So, the working women will work peacefully in the offices where their children will be looked after safely in the creches. Once again, I support the Motion and thank you for giving me an opportunity to speak on this Motion.

श्री उपसभापति: श्री कृपाल परमार। आप समय का ख्याल रखें।

श्री कृपाल परमार: धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं समय का पूरा ख्याल रखूंगा। पार्टी का समय 16 मिनट बचा हुआ है और बाद में समाप्त करने के लिए पांच-सात मिनट और चाहिए।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। उसमें भी कुछ आप छोड़ें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी पार्टी के दोनों वक्ताओं ने समय कवर कर दिया है।

श्री कृपाल परमार: उपसभापति महोदय, मैं अपनी समय-सीमा में रहने का प्रयास करूंगा। माननीय उपसभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की यह पुस्तिका हमारे पास आई, 22 पन्नों की और 62 बिंदुओं से युक्त। हर बिंदु को, हर पन्ने को बार-बार गौर से पढ़ा और जो बिंदु तलाशने का प्रयास किया, जिस बिंदु पर माननीय राष्ट्रपति के मुखारविंद से कही गई सरकार की कथित उपलब्धियों के बारे में राष्ट्रपति का धन्यवाद किया जा सके।

मान्यवर, बिंदु दो में यह कहा गया कि विकास दर जो है वह उत्साहित दर से 7.5 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है। यह शहरों में रहने वाले, स्टॉक एक्सचेंजों में काम करने वाले, शेयरों में निवेश करने वाले लोगों के लिए उत्साहित बात हो सकती है, लेकिन हिन्दुस्तान का जो जनमानस है, जो 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, उनका इस विकास दर से कोई मतलब नहीं है। अगर गरीब आदमी का कोई मतलब है तो वह महंगाई से है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मुद्रास्फीति की दर साधारण स्तर पर ही रही। मैं मुबारकबाद देता हूं कि अगर ये दो सालों में आपका कारनामा है कि इतनी तेजी से बढ़ रही मुद्रास्फीति को यह सरकार साधारण स्तर मानती है तो आने वाले समय में क्या गुल खिलायेंगे, यह आने वाला समय ही बतायेगा।

मान्यवर, गरीब का पेट जीडीपी से नहीं भरता है। गरीब का पेट दाल, चावल और आटे के भाव से भरता है, गरीब के घर का चूल्हा विकास दर की लौ से नहीं जलता है, बल्कि गरीब के घर में चूल्हा केरोसीन और गैस से जलता है। अगर हम पिछले दो सालों के कार्यकाल पर नजर डालें और मुद्रास्फीति की तरफ देखें, तो आटा, दालें, चावल, चीनी, केरोसीन और गैस के दाम लगभग दुगने के बराबर हो गये हैं। अगर दो साल में भाव ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: केरोसीन, गैस के दाम दुगने नहीं हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार: लगभग दुगना, मैंने पांच चीजों को कहा है। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज भट्टाचार्य: अभी तक हुआ नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार: हो जायेगा। अगर आपका समर्थन जारी रहा, तो जरूर हो जायेगा।..(व्यवधान)... आपके समर्थन से हो जायेगा। आप फिक्र मत करिये। मान्यवर, इस सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जानबूझकर मुद्रास्फीति के आंकड़ों को नहीं रखा। जब पूर्व वक्ता बोल रहे थे, तो उन्होंने बेरोजगारी की बात कही। हिन्दुस्तान में आज लगभग चार करोड़ से अधिक बेरोजगार हैं। बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन रोजगार कहां से देंगे, इसका अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है। मान्यवर, चार करोड़ बेरोजगारों में केवल पढ़े-लिखे लोगों का आंकड़ा लिया जाये तो जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, उनका आंकड़ा भी तीन करोड़ से ऊपर जा चुका है, जोकि एक चिंता का विषय है। लेकिन माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका भी जिक्र नहीं है।

मान्यवर, बिंदु छह में सब पाइंट्स दिये गये हैं कि देश के प्रत्येक गांव में बिजली दी जायेगी। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क पहुंचाई जायेगी। हर गांव में पीने के लिए पानी दिया जायेगा। हर गांव में एक टेलीफोन दिया जायेगा। एक करोड़ हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा और ग्रामीण निर्धनों के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण कराने का भरोसा दिया है। मान्यवर, जहां तक बिजली का प्रश्न है मैं पार्लियामेंट की पॉवर कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य हूं और मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले दो सालों से लगातार हाईडल और दूसरे जितने प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। सरकार ने 2012 तक गांव-गांव में बिजली देने का जो ऐलान किया है, वह मुझे लगता है कि वह 3012 तक भी सरकार इस रफ्तार से कार करे, तो पूरा नहीं कर पायेगी। मान्यवर, जिन गांवों को आज भी इलैक्ट्रिफाइड माना जाता है, उनमें अधिकांश गाँव ऐसे हैं जिनमें इलैक्ट्रिफिकेशन के नाम पर एक पोल खड़ा है और वह भी बिजली जलाने के काम नहीं आता बल्कि कुत्तों के दुरुपयोग के काम आता है। मान्यवर, पेय जल की व्यवस्था करने का आश्वासन सरकार ने दिया है। बहुत-से ऐसे गाँव आज भी हैं जहां पर लोग तालाब से गंदा पानी पीते हैं। बहुत-से गांव ऐसे हैं, जहां लोग दो-दो, चार-चार, छः-छः किलोमीटर पैदल चलकर सर पर घड़ा रखकर पीने के पानी का जुगाड़ करते हैं। मान्यवर, एक वर्ष में पूरे हिन्दुस्तान के गांवों को पीने का पानी कैसे देंगे और इसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करेंगे, इसका जिक्र सरकार ने नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि एक साल के अंदर हिन्दुस्तान के हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जहां तक एक करोड़ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई का प्रश्न है, मेरा मानना है कि जब तक वर्षा के पानी को रोककर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्रबंध पूरे देश में नहीं किया जाता, यह सपना साकार होने वाला नहीं है। महोदय, मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पर पानी की किल्लत नहीं है। हमारी नदियों से बहकर पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की भूमि को सिंचित करता है

लेकिन उस प्रदेश में भी पीने वाले पानी की कमी रहती है क्योंकि पानी जब हमारे सर पर गिरता है, हमारी छत पर गिरता है, हमारे खेतों में गिरता है तो उसको हम रोकते नहीं है और फिर बाद में हम जाकर नदियों-नालों से पानी लाने का प्रयास करते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि रेन वाटर हारवैस्टिंग को एक मिशन के रूप में अगर लिया जाए तो पूरे हिन्दुस्तान को सिंचित किया जा सकता है। मान्यवर, नेशनल हाइवे के दोहरीकरण की बात आयी। दिल्ली-कोलकाता, कोलकाता-चेन्नई और चेन्नई-मुम्बई को जोड़ने की बात आयी। उसके लिए सरकार ने कहा कि हमने 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। मान्यवर, यह खुशी का विषय है, लेकिन जिस तरीके से, जिस गति के साथ एनडीए की सरकार ने एक मिशन के रूप में इस काम को लिया था और इन सड़कों का निर्माण प्रतिदिन 11 किलोमीटर की रफतार से बढ़ रहा था, मुझे दुख के साथ इस सदन में खड़े होकर कहना पड़ रहा है कि यूपीए की सरकार ने आकर इस काम को ढिलाई में डाल दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे यह काम एनडीए और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश को जोड़ने वाला काम है। आपने भी राष्ट्र निर्माण का नारा दिया है और राष्ट्र निर्माण का नारा तभी पूरा हो सकता है जब इस देश को इन्फ्रास्ट्रक्चर से और सुचारू रूप से सड़कों से जोड़ा जाए। आपने ऐसा वादा इसमें किया है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बहुत से वक्ताओं ने यहां पर चर्चा की। मैं भी चंद शब्द उसमें जोड़ना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार ने अगले पांच सालों के लिए जिस राशि को रखने का फैसला किया है, वह राशि अपर्याप्त है। पंचवर्षीय योजना में केवल 17 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है और सरकार ने दावा किया है कि इस योजना के तहत 12 करोड़ बच्चे स्कूलों में लाए गए हैं। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक अभी भी दो करोड़ बच्चे, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको भी इस योजना के तहत लाने की जरूरत है। अगर दोनों को मिलाया जाए और उनकी संख्या 14 करोड़ से अधिक बनती है और अगर इनको भाग करके एक दिन का खर्चा निकाला जाए तो लगभग 70 पैसे प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा बैठता है। मैं मानता हूं कि यह अपर्याप्त राशि है, जिससे किसी को एक वक्त का मिड डे मील तो क्या, उसको बस में बैठने का किराया भी नहीं दिया जा सकता। जहां तक मिड डे मील का प्रश्न है, हो सकता है कि मिड डे मील के कारण स्कूलों में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी हो। लेकिन स्कूल का वातावरण, जो एक पाठशाला का था, वह लगभग बावर्चीखाने वाला बन गया है। वहां पर इंधन का इंतज़ाम नहीं है, रसोई बनाने वाले बावर्ची का इंतजाम नहीं है, पानी लाने वाले आदमी का इंतजाम नहीं है, बरतन साफ करने के लिए हैल्पर का इंतजाम नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, कि बच्चे उठ-उठकर रसोई की तरफ देखते हैं कि खिचड़ी पकी या नहीं और मास्टर सुबह आते ही लकड़ी और पानी के इंतजाम में लग जाते हैं। पढ़ाई वहां पर सैकेंडरी काम हो गया है, खिचड़ी प्राइमरी काम हो गया है मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर मिड-डे मील का सुचारू रूप से चलाना है, तो उन स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, वहां पर खाना बनाने के लिए पानी का इंतजाम सरकार को करके देना होगा, ताकि इसका भार वहां के बच्चों और अध्यापकों पर न पड़े।

मान्यवर, इस अभिभाषण में कहा गया कि कृषि में कर्ज़ों की दर साठ फीसदी बढ़ गई है। एक तरफ तो यह खुशी का विषय है कि किसानों को आसानी से कर्ज़ा मिलने लगा है, लेकिन जिस रफ्तार के साथ किसान कर्ज़े के बोझ में दबकर आत्महत्या की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, वह एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि किसान जिसके पास ज़मीन है, जमीन के ऊपर लोगों की निर्भरता बढ़ गई है। पहले दस एकड़ थी, बंटवारे में पांच एकड़ हुई और अब बंटवारा होते-होते परिवार के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि उस पर उस परिवार का गुज़र-बसर हो सके। किसान फसल बोता है, तो कर्ज़ा लेता है, खाद डालता है तो कर्ज़ा लेता है, ट्रैक्टर लेता है तो कर्ज़ा लेता है, लेकिन जब उसका गेहूं पककर तैयार हो जाता है, तो हमारी यू.पी.ए. की सरकार, जो किसानों को ऋण देने की बात तो कर रही है, वह गेहूं की खरीद के लिए आगे नहीं आती। मान्यवर, पिछले सत्र में पंजाब और हरियाणा से, सरकार ने एक षडयंत्र के तहत किसानों से पूरी फसल की खरीद नहीं की। जान-बूझकर 10 लाख टन का quota घटा दिया गया, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल सस्ते दामों पर आढ़तियों और मुनाफाखोरों को बेचनी पड़ी और उसका खामियाजा यह हुआ कि आज पंजाब का किसान भी, आंध्र और कर्नाटक के बाद, आत्महत्या जैसे कगार पर है और वहां भी लोग आत्महत्या के बारे में सोचने लगे हैं। मान्यवर, दुख जो तब होता है जब अपने देश का किसान, अपना खून-पसीना बहाकर सरकार से कर्ज़ा लेकर फसल पैदा करता है और सरकार उसको खरीदती नहीं और 6 महीने बाद एक और षडयंत्र के तहत, एक और घोटाले के तहत, सरकार पांच लाख टन अनाज विदेशों से आयात करके, वह देश जो अपने देशवासियों को पूरा खाना देने में सक्षम है, उस पर गेंहू के आयात करने का कलंक, सालों बाद, फिर यू॰पी॰ए॰ सरकार के दौरान लगता है। इस बात के लिए मैं किसका धन्यवाद करूं, मेरी समझ में नहीं आता।

मान्यवर, इस अभिभाषण में देश में बायो-डीजल को बढ़ावा देने की बात कही गई है अगर हिंदुस्तान में खाली पड़ी जमीन पर बायो डीजल की खेती की जाए, तो विदेशों से एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पेट्रो प्रोडक्टस हम आयात करते हैं, उससे बचा जा सकता हैं मैं मानता हूं कि अगर बायो डीज़ल के कार्यक्रम को पूरे देश की बहुत बड़ी बचत हो सकती है।

मान्यवर, 29वें प्वाइंट में माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारी निर्वाचन पद्धति दोषमुक्त रही है। किसी भी देश की निर्वाचन पद्धति उसके लोकतंत्र की जान कही जा सकती है, शान कही जा है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर दोषमुक्त रही है, तो उसको यह सरकार दूषित करने का प्रयास क्यों कर रही है?

आपके सामने नवीन चावला का उदाहरण है। मैं यह भी मानता हूं कि निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक पदों पर राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बनकर उनको अगर राजनीति में, राज्य सभा में या गवर्नर बनाकर पुरस्कृत किया जाएगा तो इस निर्वाचन की पद्धति को साफ-सथुरा नहीं रखा जा

सकेगा। मान्यवर, इसी के साथ मैं आपका ध्यान राष्ट्रपति के 46वें बिंदु की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें उन्होंने कहा है, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपके 16 मिनट खत्म हो गए हैं। आप समाप्त कीजिए।

श्री कृपाल परमार: मैं यहा पर उसका जिक्र करना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर को 24 हजार करोड़ रूपए का पैकेज दिया गया। इस पैकेज की आंतकवाद से पीड़ित प्रदेश को जरूरत थी। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आज तक जितनी मदद दी गई है अगर उसको वहां पर ईमानदारी से लगाया जाता तो जम्मू-कश्मीर में न तो यह आंतकवाद की समस्या आती और न ही जम्मू-कश्मीर को केन्द्र से मदद की जरूर होती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में यह पैसा ठीक तरीके से लगे ताकि असल में जो गरीब लोग हैं और जिनको इसकी जरूरत है, उन तक यह मदद पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा का जिक्र किया है। मान्यवर, यह वही क्षेत्र है जहां पर 1948 के तीन गढ़वाल रेजिमेंट ने एक लम्बे समय तक कबाइलियों से युद्ध करके, इस पूरे सैक्टर को कबाइलियों से आजाद करवाया था। उस गढ़वाल रेजिमेंट के कमांडिंग आफिसर हिमाचल प्रदेश के सपूत श्री कमान सिह पठानिया के नाम पर इस पोस्ट और पुल का नाम कमान सिंह सेतु रखा गया था। जब इस बस का शुभारंभ हुआ तो उसका नाम बदलकर अमन सेतु कर दिया गया। कमान सिह पठानिया के परिवार के लोगों ने इस पर ऐतराज किया तो आर्मी हैडक्वार्टर और रक्षा मंत्रालय ने उनको पत्र लिखकर सूचित किया कि उसका नाम कमान अमन सेतु रखा जाएगा। लेकिन मुझे दुख के साथ इस सदन को बताना पड़ रहा है कि 26 जनवरी को जब उसी सेतु की झांकी राजपथ पर, इस देश के

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) in the Chair]

राष्ट्रपति और सेना के सुप्रीम कमांडर के सामने लाई गई तो उसका नाम कमान अमन सेतु की जगह पर अमन सेतु था। मैं मानता हूं कि रक्षा मंत्राल के अधिकारियों ने उस झांकी को जब पास किया, क्लीयर किया तो उन्होंने देश के राष्ट्रपति के सामने उस महान सपूत का अपमान किया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है, वह इसकी जानकारी प्राप्त करें। जिन अधिकारियों ने ऐसा जानबूझकर किया है उनको दंडित किया जाए। मान्यवर, राष्ट्रपति जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्र को अपनी सेनाओं पर गर्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सेना को भी पिछले दिनों दुविधा में डालने का प्रयास किया गया, उसकी बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं यहा पर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Parmarji, your time is over. Please, wind up.

SHRI KRIPAL PARMAR: Sir, I am just concluding. लेकिन सरकार की बीस साल की अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो मैं मानता हूं कि इंग्लैंड के बैंक में क्वात्रोची दलाल के एकाउंट को खुलवाना, जिसके लिए सरकार ने खुद एक व्यक्ति को भेजकर उसके एकाउंट को खुलवाया, अगर राष्ट्रपति महोदय, उसका जिक्र भी इसमें करते तो मैं उनका धन्यवाद करता। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी ने सांसदों को प्रेरणा देते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि दोनों सदनों की कार्यवाही पर विचार-विमर्श हो, परिपक्व विचार-विमर्श हो और इसी हेतु सांसदगणों द्वारा अपनी सारी ऊर्जा लगाई जाए।

मान्यवर, हम सब लोगों ने वह भाषण सुना और कम से कम इस सत्र में हमने राष्ट्रपति जी की इस उम्मीद पर मुहर लगाई है और पिछले 7 दिनों से लगातार यह सत्र आराम से चल रहा है। विपक्ष ने इतना सुचारू सत्र चलाया है कि गैलरी में बैठा हुआ मीडिया भी परेशान हो गया कि कोई खबर नहीं मिल रही है।

अंत में मैं Quattrochi के बंद खातों को खुलवाने के लिए, देश में कमरतोड़ महंगाई के लिए, गरीब किसानों की हत्याओं के लिए और अमरीकी दबाव के सामने घुटने टेकने के लिए इस सरकार का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in this discussion. Sir President's Address is the sum and substance of the performance of the Government as well as the policy directives of the Government. It is an assessment, a balanced document explaining the policy directives as well as the performance of this Government during the last eighteen months.

Sir first of all, I would like to endorse the views expressed by Comrade Dipankar Mukherjee regarding the formation of this Government and the support that is being extended to this Government by the Left parties or the Left front. Sir, in the 14th Lok Sabha elections, the mandate given by the people is clearly a fractured mandate, the Congress Party did not have the absolute majority and there was a political instability in the country. The Congress Party won 145 seats. In order to avoid the political instability in the country as well as to keep BJP out of power, the Left political parties alongwith the Congress Party had detailed discussion and they finalised a document called the Common Minimum Programme, subsequently,

accepted as the Government's programme, the National Common Minimum Programme. So, the Left parties as supporting the Government in order to implement the programmes envisaged in the Common Minimum Programme.

I would like to give a suggestion to the Government, at this juncture, because the support of the Left parties to the Government is very critical nowadays in almost all the media. And yesterday itself, Mr. Venkaiah Naidu was speaking about 'breaking' and 'biting' of Left political parties, and, all these aspect have been discussed a lot. So, my point is that the support given or extended by our friends or our political parties is purely on the basis of the issues, on the basis of the policies and programmes which are envisaged in the National Common Minimum Programme. That is why, we are agitating on some of the issues. These are the issues of the common people in the country; these are the issues of the working class in the country. So, with a view to implement these programmes, we are extending our support to this Government. But, after 1/2 years of our experience, it is quite unfortunate to say that the Government is not fulfilling its commitment to implement the National Common Minimum Programme in its letter and spirit. And, due to this, a lot of criticism is coming from various corners, various political corners.

Sir, now, I come to the point regarding economic growth. I do appreciate it. His Excellency, the President of India, in his Address to the joint session of the Parliament, stated that the economic growth in the current financial year 2005-06 would definitely cross 8 per cent mark. It has gone up from 5 per cent to 7.5 per cent during the last financial year, and it will be crossing 8 per cent. My question is-and we always put up this question-whether the benefits of this growth are being reached to the poor and the common man of this country. That is the pertinent point to be answered by the Government. As far as we are concerned, when this economic growth comes, definitely, the purchasing power or the purchasing capacity of the people also increases. But, what about the sector on which mainly 70 per cent of the population depends on, that is agriculture sector? What is the state of affairs of agriculture? When we think about reforms in a country like India, where 60-70 per cent of the population depends on agriculture, definitely, we should think about the reforms in agriculture sector so as to protect the interests of the farming community, to protect the interests of

the peasants of our country. But, what is the present state of affairs of agriculture? My point is that not much attention has been given to redress the problems of the farmers of this country. Adequate attention has not been given by this Government to the agriculture sector. Everyday, we are experiencing that the farmers are committing suicide because of poverty and because of the reasons beyond their control. Therefore, this sector has to be given much greater attention. Then only we can say that the country is progressing. We can say that social progress has been achieved only if we are able to address the problems of more than 60 per cent of the population of this country.

I would now say something regarding the unemployment problem. Yesterday also, so many hon. Members spoke on the unemployment problem. What is the rate of unemployment when compared with economic growth? I don't think that it is satisfactory statistical figure. I don't think that unemployment problem has been eradicated or reduced to a satisfactory extent. I don't think so. It is being stated that most of the economic growth should be based on equity. The National Common Minimum Programme is also envisaging economic growth with justice and equity. And, the economic growth should produce jobs also. But, when we see the statistics, definitely, it is not satisfactory to say that we are able to contain the unemployment rate in accordance with the economic growth, which we have achieved during the last one or two years. So, these two problems have to be addressed and much attention and focus has to be given mainly to these two issues.

Another point, on which the Left is having total difference with the Government of India, is about the foreign policy of this country, especially the present policy. The conventional foreign policy, that is, the independent foreign policy of our country is being diluted during these days. It is well established in almost all cases. I am not going into the details. Apprehensions are still there regarding the civil nuclear energy cooperation agreement. Clarifications have not been brought out regarding civil and military differentiation as well as on reciprocal commitments even after months, after having this Joint Statement. Cooperation is based on reciprocal commitments. What are the commitments? The commitments have to be clarified. But it has been seen that during the last Iran vote in the International Atomic Energy Agency voting-the whole House was also very agitated yesterday-Mr. David Mulford, the Ambassador of America in

India, has very specifically given a warning to the Government of India. Indirect threat has been given to our country that if you are not going to vote in favour of America or in support of America in the International Atomic Energy Agency meeting, the consequences will definitely be bitter. Our country is a sovereign country. Such an indirect threat has been given to our country. Our independent foreign policy, which has been accepted throughout the world for all these five decades, is being diluted. So, we are having differences on this issue also.

Regarding the Foreign Direct Investment also, an assurance has been given by the Government several times with respect to the retail sector. Forty million people are engaged in the retail sector.

But what is the commitment? What is the assurance? And what is happening? Now-a-days, it is being explained that in the retail sector, they are allowing only single-branded items. But even under the single brands, there are more than 20,000 items. So, indirectly, all these reforms, which are being opposed by the people, which are being opposed by the political parties, are being indirectly implemented in our country. And those who are at the helm of affairs are giving the argument that it is in the national interest or some other things. In the name of reforms, it is being implemented. That is why we are suggesting to them that the National Common Minimum Programme (NCMP) is very clear in all these aspects.

Sir, now I come to the issue of public sector undertakings. Just now, Mr. Dipankar Mukherjee has spoken about the issue of the Airports Authority of India. It is a very pertinent issue as far as our country is concerned, because the Government is going back on its commitments. What does the NCMP say? It is very clear that no profit-making public sector units will be disinvested or privatized. What is happening now? That slogan is now being diluted. Except the Navratnas, that is, except nine public sector units, all the other public sector undertakings, though they are making profits, will be privatized. That means, it is the dilution of the programme or the commitments which we have made in the National Common Minimum Programme (NCMP). Out of the resources of these airports, namely, Delhi Airport, Mumbai Airport and Kolkata Airport almost all other airports are being maintained in a proper way. So, what is the interest of our country? This is not just privatization even. This is absolutely handing over of the national assets of our country to some multi-national corporations. It is

not mere privatization. These are the wealth and assets which we have accumulated during the last five decades. This has started from the days of Nehru. All these things are being taken away or are being handed over to the private monopolies and the multi-national corporations. By making mere investments, they are taking away the entire assets of this country. These assets are made out of the hard work of the people of our country. This is going into the hands of the private monopolies and multi-national corporations. That is why we are suggesting that if this Government goes like this, if the Government is not ready to honour the programmes as we have committed in the National Common Minimum Programme, then, definitely, this criticism will come; and this criticism will definitely go ahead also. So, I would like to caution this Government also.

Now, I come to the other aspect. I do accept that some commitments have been fulfilled. That also I would like to appreciate here. As far as the Rural Employment Guarantee Scheme is concerned, definitely, it is a welcome step. This is also a commitment in the National Common Minimum Programme. But I have a suggestion for this Rural Employment Guarantee Scheme. Even its modalities, its norms, the way of implementation of Rural Employment Guarantee Scheme.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please, try to wind up.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: This Rural Employment Guarantee Scheme is still vague; it is not clear. So, effective implementation of the Rural Employment Guarantee Scheme is required; otherwise, it can be indirectly said that because it is practically not possible or it cannot be effectively implemented in future, so it may be dropped. So, requisite norms have to be established, and effective implementation has to be made as far as the Rural Employment Guarantee Scheme and also the Bharat Nirman Scheme, which has been cited here, are concerned.

I would appreciate one more point of the President's Address. Three important aspects have been mentioned in the paragraphs. One is drastic administrative reforms to end the red-tapism and bureaucratism; second is drastic judicial reforms; and another one is electoral reforms. I absolutely agree with these three points. Administrative, judicial and electoral reforms are the need of the hour. The Government should focus on these issues and give them a high priority. I would, once again, urge upon the

Government that these programmes, which are being envisaged in the National Common Minimum Programme, be adhered to.

Yesterday, when Dr. Karan Singh was speaking, he was talking about the manifesto of the Congress. The people have not given the verdict to implement the manifesto of the Congress. Now, it is a coalition Government; it is a post-poll coalition Government on the basis of a document, and the document should be implemented. It is not the Congress policies; it is not the economic reforms policies of the Congress but of the UPA that are based on the NCMP. That should be implemented, so that the people as well as the Left Parties should have the impression that this Government is honouring its commitments and all the commitments are being implemented and fulfilled. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Thank you. Now, Shri Birabhadra Singh.

SHRI BIRABHADRA SINGH (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the time. Sir, the hon. President's Address on 16th February to both the Houses is the reflection of the Government's activities and intention to implement programme in future. Sir, many learned speakers have already pointed out many things and the pros and cons of these speeches. As Shri Raj Nath Singh was telling, it is not meant for criticizing the President, but for criticizing the Government policies at large.

Sir, I begin my speech from the last sentence on page 9, point 26. It is said, "Steps have been initiated for setting up the Sixth Pay Commission for Government employees." Sir, yesterday one of my friends, Mr. Sharad Joshi, was referring to the Sixth Pay Commission. Sir, really if the States are being ruined, it is only because of the Pay Commissions. It is only the Pay Commissions. Sir, if the backward States like Orissa and advanced States like Maharashtra are today in debts, it is only because of the Pay Commissions. The announcement of this Pay Commission puts us in trouble because, Sir, we are not having a vast source of income. When the Central Government is not in a position to handle these few employees, we are bound to follow the same policy without having any base of financial resources. Sir, we, particularly the backward States, have to face a lot of trouble in our development programme because only three per cent employees are consuming a share of 90 per cent population of our State and we are not in a position to spend money for development. That is the

4.00 P.M.

only reason, Sir, for setting up the Pay Commission. Therefore, definitely, we are not in a happy state of affairs. Secondly, Sir, what is your policy regarding debt relief? Is there any definite policy? Nothing is mentioned in the President's Address about getting rid of debts. Sir, terrorism is there in Punjab, Jammu and Kashmir and in some other States. The Centre is politically interested there and there are special packages. But Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand are now under serious terrorist threat by Maoists and Naxalites. Is there any policy to get rid of this? Sir, how can we go on with this condition, with a debt of Rs. 34,000 crores? Can we survive with this debt condition? We have done very well in arresting both revenue deficit and fiscal deficit. But there is no reward. A State like Orissa, having the highest percentage of population below poverty line and one of the two poorest States in the country, is not declared as a special category State for which we are demanding since long. That is the only step which can brings us out of this debt trap; otherwise, we have no way out.

Sir, in the morning Session, Shri Janeshwar Mishra was referring to the poor conditions of Kalahandi, Bolangir and Koraput districts, which is known as the KBK region. Sir, when Shri Rajiv Gandhi and Shri Narsimha Rao were the Prime Ministers, a lot of noise was made about the development of the KBK region. Big schemes were made for the development of this region, and a sum of Rs. 4,500 crores to Rs. 6,000 crores was to be spent within a period of seven years for the development of this region. But, you will be astonished to know that the Centre did not do anything until the NDA Government came into power. Till then, they kept quiet, they kept silent. But, when the NDA Government came into power, it sanctioned Rs. 100 crore or Rs. 200 crore every year. Sir, how long will it take to improve their conditions-25 years or 30 years or will it be just a lip-service to the people of this region? I urge upon the Central Government to take a serious note of this thing...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF P.J. KURIAN): Mr. Birabhadra Singh, you have two minutes more. Try to be brief.

SHRI BIRABHADRA SINGH: Sir, I would be very brief. Sir, in para 31 of President's Address, the hon. President has spoken about the development of the SCs/STs and the tribal population. But there is no clear-cut remark about these categories in President's Address. It is simply stated that we are thinking in terms of the development of the tribals. But, I can emphatically

say that if any development of the tribals has to take place, it can take place only if we extend the educational benefit to the tribals, and only then, tribals' interests can be safeguarded. Otherwise, the economically beneficial schemes are a total waste. Before the NDA Government came to power, the Congress Government was there which was laying a lot of emphasis on the beneficial schemes. I would say that it was totally of no use. Till now, there are so many communities or groups whom we call banvasis. We cannot call them tribals unless they are treated as tribals under the Act passed by the Parliament, and assented to by the President. That is why we call them banvasis. They are very much lagging behind in the developmental process. After 1956, in the year 1977, when there was no Congress Government, and when the Janata Party Government came into power at the Centre, the said Government intended to bring them under the category of the SCs/STs. After that, again, this scheme was thrown into the dustbin, and next time, when the NDA Government came into power at the Centre, it again reopened the issue of categorization of the SCs/STs, covering a large population, who are living in the backward areas.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please conclude.

SHRI BIRABHADRA SINGH: I am concluding, Sir. I come from a poor State, Orissa. I need two minutes more. I am completing my last point. Regarding the States which have poor infrastructure like the State of Orissa, there is no reference of special dispensation for such States in President's Address. About Rs. 5,000 crores are needed to complete the sanctioned railway project in Orissa, and these funds should come in the next five years at the rate of Rs. 1,000 crores per year , along with some additional allocation for new projects. Similarly, the Paradeep Port, which was constructed with the help of the State funds by our esteemed leader, Late Shri Biju Patnaik, should be expanded to handle cargo of, at least, 120 million tones so that the additional cargo to be generated by an investment of Rs. 1,50,000 crores on steel and aluminium plants can be handled over in the next 10 years. Sir, we are not touched by the eastern corridor nor by the western corridor of the Railways. We need a huge infrastructure in terms of national highways besides railways to use our mineral resources effectively as well as to combat Maoist and Naxalite danger.

Later, Sir, as a tribal, I urge upon the Central Government to create more facilities for the tribals. The residential schooling scheme is helpful to the tribals. The Mid-day Meal programme is introduced at the primary level, but the Residential Hostel Scheme is introduced at the secondary level. It is only beneficial to the tribals. Wherever there are '*ashram*' schools and residential schools, the results are more encouraging. We are going to post teachers in private institutions and Government institutions. Where can we get the educated students?

Therefore, my humble submission is, please create more and more residential school facilities for the tribals and *Harijans*.

I thank you, Sir, for having given me time to speak. I think, Sir, I have completed my speech with the time allotted to me.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): You have made very good points. Thank you.

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Sir, I supplement what my floor leader has already said. I have even posed questions to myself. Is it necessary to thank? Is it really essential? Has the UPA Government done something to thank them?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): To thank the President.

SHRI N. JOTHI: No, no; the President is only a figurehead. That is all written by these people. He only read. ...*(Interruptions)*... Sir, we are in politics; we know that.

Sir, I thought myself—and it struck inmy mind to go through the CMP—that the National Common Minimum Programme which is supposed to be the 'Magna Carta' of this Government, as Hon. Oliver Cromwell, when he brought democracy in England, was shortlived, would also be shortlived. This is 'Magna Carta' of this Government. What the 'Magna Carta' reads, let us see. 'Pleadge'. Hitler's Pledge! "Hail Hitler." Just like that, "Hail Pledge." What does his pledge say? 'To provide Government that is corruption free. No corruption in this Government.' Let us see that a little later. 'It is corruption free, transparent.' Very transparent! 'Glass. Globular glass. Accountable.' Every pie it will account. The whole payment it will account. 'Accountable'. It will be accountable. You can, any time, ask for the account. It will throw it. You can see it. It is accountable! Whenever

accountable, Sir? All times—midnight, early morning hours, late night hours! Every time, it is accountable; no problem on that. You can seek the accounts. 'And to provide an administration.' You are very efficient in administration. You will provde an administration. Of what nature, Sir? Of responsible nature! Responsible administration! 'Not only responsible; when you question, we will be responsible also. Our own Coalition will be responsible. When you question, we will be responsible.' 'Knock the door.' As it is said in The Bible, "Knock, and the door will be opened to you." You ask that, the door shall be open.' This is the 'Magna Carta' of this Government. Are they living up to even an iota of it? 'You will live up to a little bit of it.' Are they living up to it? Fissures are already there among the Coalition partners. I am very happy because in this session the Left has taken a right stand, but not to the extent which the country is expecting. I think, it is only a question of a few weeks. We will be very happy. We will play the role of a catalyst in the matter. There is no problem on that. You have mentioned a corruption-free Government. The BJP Member, while opening the debate mentioned that some Ministers were underground and all that. I am not on that. Those are all pre-oath administration offences. We can give some allowance to the regional parties with regard to these pre-oath offences. But what about corruption after taking oath as Minister? Please think about yourselves. Is the Government free from corruption? Everybody knows what is happening. People are seeing that. People are talking about that. You have said in your Magna Carta, "We will be accountable; we will be answerable; we will be responsive." You have said that your administration will be corruption free and there will be zero level tolerance of corruption. You have said, "We will not tolerate even zero level corruption". You are that much great people. I don't want to name persons. We have given, the country has given an opportunity to those Ministers with documentary proof. But not a piece of word has come as answer. I am even now waiting for an answer. In the meanwhile, this much proof has come against another Minister. We will take care of it next week. We have collected all the public documents. We don't want to disturb these proceedings. We will take care of it next week. This is the level of this Government. And you want us to thank! We are not thanking. We will be doing an injustice to the public if we thank. We don't want to do that injustice.

Sir, this Pledge is not an ordinary pledge. In the last page of the CMP, there is a column "A final World" where they say, "This Common Minimum Programme is, by no means, a comprehensive agenda." It is not an end. It is only a beginning. It is only a small step that they are taking. Their aim is elsewhere. They are such a great people. It is only a beginning. This is the minimum. They have to achieve a large world. They have to achieve the universe. They are not satisfied. They are going to do many more things. I was shocked when I read this. What type of Government is this? It is going to be a utopian one. It is going to be a model Government for the whole world. After seeing the persons who took oath of office, after seeing the manner in which the Government is functioning, I was disappointed. I know that English language has got a lot of vocabulary. English has got a lot of words which are borrowed and printed. They are not meant for implementation. They are meant only for advertisement purposes. They are meant to hoodwink the public.

Sir, I am having only one grievance against the Left Parties. How long will they tolerate this? They have a great burden on their shoulders. We don't have; they have. How long will they tolerate this? A stage is going to come. It should come within weeks. Otherwise, they will be called conspirators. I think, they are delaying it further.

Sir, this Common Minimum Programme mentions nice principles. But these nice principles are wrongly applied or not at all applied. Principles are only being spoken. Anybody can speak principles from the books of politics. This is the level of the Government that you are all running. Sir, at least we have spoken twice within a year about suicides of farmers. Yesterday, I asked a question from the Finance Minister who is from the Harvard University. Sir, I asked him a question, 'why are you limiting credit to the farmers to Rs. 50,000 with nine per cent interest when you are giving Mercedes car to people with six per cent interest? Sir, farmers are committing suicides. Everybody knows it. Everybody is talking about it. But no concrete steps are being taken. This Presidential Address is quite silent on that. So, suicides can continue. We can reduce the population. That seems to be the idea of this Government. Sir, I tell you if you are bankrupt in ideas please take the example of 1935 West Bengal, Bengal Famine Relief Act. It is available. When Bengal was reeling under famine, British Government gave relief to farmers. So also in Tamil Nadu — Tamil Nadu Members will understand — when MGR was the Chief Minister, debt

relief was given to the farmers. A moratorium was given. This Government will not listen to us. They will not take truth from us. They will only help industrialists. They will only help pot bellies and not starving people. Their eyes are different. Their world is different. Very unfortunate people! Sir, literally moratorium was given by MGR. That means you can file a case of arrest the limitation but you cannot pursue. Moratorium was given to farmers. For how many years? For six years. People got out of the problem. Moneylenders were given debt relief. For unsurious interest people were put inside. There was no question of 36 per cent in Tamil Nadu. Never heard for the past two years. At least take clue from us. At least borrow good things from us and try to understand. Mr. Poojary, I know how he will be feeling in his heart to see the things happening around him. I know that. I could see from his face. I know how he was friendly with poor people. Yes, he has given free loans. To whom did he give? he has not given to Dhabol. He has given to Mangatai, he has given to Kupaai, ordinary people, poor people. Even if we knock it off there is no problem. We can unburden ourselves by giving some loan to them. Sir, I used to think, my party used to think if we take three meals per day we are stealing somebody's food. This is the motto with which our party is functioning in Tamil Nadu. Sir, you are helping multi-national companies but you are not accounting to the Parliament. Even though in the Minimum Programme you have said, 'we will be transparent', you will be accountable, I am very sorry, Sir, I don't want to tell lies. How can I thank you when you are stabbing all over? How can I thank you? Sir, even if I am in Tamil Nadu I think about Left Parties. Julius Ceasar was stabbed by everybody. He sought help from Brutus. Even Brutus attacked him. Sir, I am using that terminology, 'you too Brutus Left Parties. Please don't be Brutus. Time has come for you to...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Jothi, there is time constraint.

SHRI N. JOTHI: Please permit me.

PROF. P.J. KURIAN: If you go to Shakespeare...

SHRI N. JOTHI: No, Sir, earlier it was interfered by Shri Narayanasamy. When my leader spoke, he has interfered.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): I am only saying that if you go to Shakespeare, everybody will be eager to listen and you will not stop.

SHRI N. JOTHI: Sir, let me shift from public to your propriety of Governance with other States. What did you say in Common Minimum Programme? Let us take page 15. Page 15 has said, 'UPA Government will make National Development Council a more effective instrument of cooperative federalism'. Not ordinary federation but hand shaky federalism. Rubbing shoulders with each other. The Central Government will not show its might. We are your friends. You want to shake hands with the State Governments. This is your idea in the NCMP. What is happening is that you are the true Congress people. Yes. you never changed your colours. Leopard will never shed its spots. You will continue to be like this. What Mr. Ram Lal did in Andhra Pradesh? He dismissed the NTR Government. Even now, you are chossing the same level of governance. Sir, in Tamil Nadu, there was a Governor by name...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Why are you going back to 25 years? ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Sir, whenever he interferes, I should be given two minutes more.

Sir, in Tamil Nadu, there was a Governor. His term did not expire...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Jothi, will you yield for a minute?

SHRI N. JOTHI: No, no. I am not yielding...*(Interruptions)*... Sir, I should be given two minutes more...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: It is the AIADMK Party which has gone to the court saying that the same Governor should continue in office. This was the sorry state of affairs...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: If you don't know anything, please don't show your ignorance here. He is exhibiting his ignorance here. It was the case of Chief Secretary...*(Interruptions)*... Please don't show your ignorance.

Anyway, you please read the plaint. Otherwise, I will give you that. You are a lawyer. You must speak with a little bit of sense.

So, Sir, that Governor was removed and another Governor, who was performing his gubernatorial functions in another State, brought in. Why? To trouble us.

SHRI V. NARAYANASAMY: You speak on President's Address.

SHRI N. JOTHI: you said, 'cooperative federalism.' Is this the cooperative federalism you are adopting? Shame. I am very sorry.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Jothi, time allotted to you is over. Please conclude.

SHRI N. JOTHI: Sir, I take only five minutes ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): No, no. Time allotted to you is over. You be brief and to the point.

SHRI N. JOTHI: The problem is, whenever I plead my case, I plead it before a very difficult or tough judge. And, whenever I speak, I always have a strict Vice- Chairman sitting in the Chair.

SHRI V. NARAYANASAMY: He will plead a difficult case and he will lose his case.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): Please conclude, Mr. Jothi.

SHRI N. JOTHI: Yes, Sir.

So many people have said so many things about Iran and also said that Mulford was troubling us. Whether it is Mulford or Bradford, no problem. We can manage. The problem is not with the Americans. But, the problem is with our own people. There is a saying in Tamil that if needle does not give way, thread cannot pass through. So, unless you yield, nobody can trouble you. You are yielding to outside pressure. Why? Sir, I am having a great doubt. It is not unauthenticated doubt. I am having authenticated information with me. Sir, people in-charge of formulating the foreign policy have their daughters and sons in America. They are the Green Card holders. I am demanding in this august House that let all the cabinet Minister file a return before this august House and in the Lok Sabha and let it known to the public whose children are there in America...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: First of all, tell your Chief Minister to file her return. Sir, for three years, she has not filed her returns...(*Interruptions*)... You talk about her return first...(*Interruptions*)...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

SHRI N. JOTHI: Sir, what is this? ...*(Interruptions)*... You don't know anything. Again you are showing your ignorance...*(Interruptions)*... You don't know what is the matter...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Now, you are talking about the Central Minister. For three years she has not filed her returns. And when you ask her, she says that she had forgotten...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi your flight is waiting. Conclude quickly. Otherwise, you will miss your flight.

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamilnadu): Sir, he has to go to attend some urgent case ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Sir, I am not going. I have cancelled my journey ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he will again loose his case there ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Sir, again, he is showing his ignorance...*(Interruptions)*... Sir, I don't want to be hijacked.

So, Sir, I demand, on behalf of the Opposition and general public, that let all the Cabinet Ministers and high officials disclose whose children—sons or daughters—are holding the Green Card in America. If it is known, we know about our foreign policy. There are two parties to concentrate on this particular problem. ...*(Interruptions)*... You are running the Government, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: We are not running the Government, we are supporting it. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: But for your support, the Government will not run, you know that. Sir, there is failure again on the part of the Government. I will tell you where they failed again. They failed in everything. Let me illustrate one or two points.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no time for illustration.

SHRI N. JOTHI: Sir, they have said ...*(Interruptions)*... They have said in the Common Minimum Programme on page 23, "Even as it pursues closer engagement and relations with the USA, the UPA Government..."

The UPA, according to me, means the Ultimate Pauperism Administration. Ultimate Pauperism Administration is the abbreviation for UPA.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whom are you seeing? You address me. Don't see the Press.

SHRI N. JOTHI: No, I am not seeing the Press. "The UPA Government will maintain the independence of India's foreign policy position." Independence! Now, independence has given way to enlightenment. It is the enlightened Indian policy. Sir, within one-and a half years, you have deviated from this policy. After the completion of five years, I do not know whether you will be independent India or colonial India once again! I do not know. Sir, you are all attacking me. You must go alone and put your head in shame. You must go and shed tears for this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi, please conclude...*(Interruptions)*... Please conclude.

SHRI N. JOTHI: Sir, in the CMP, you have said, "We will maintain unifrom policy; an independent policy." What are you doing now? What are you doing? It is a green card policy. ...*(Interruptions)*... 'Yes'. Sons are in America, wife is in America, and daughter is an American citizen. So, let us be *bhai, bhai* with America. Sir, we are all very sorry, we cannot go to another country. We can be here only. But we can do one thing, we can change this Government. We can change this Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You can get plenty of opportunities. With this, you can conclude.

SHRI N. JOTHI: Sir, I want to touch one last subject. At page 9 of President's Address, it is said that we are going to pursue reform of our judicial system. Sir, what is the greatness of the judicial system they have adopted so far? Let me present the Madras High Court scenario. ...*(Interruptions)*... Chennai? ...*(Interruptions)*... It is not Chennai. ...*(Interruptions)*....They have to amend themselves. Sir, in the Madras High Court, 49 judges are there. This is the total strength. Seventeen judges ...*(Interruptions)*.... Sir, 17 judges were recommended. ...*(Interruptions)*....I do not want this running commentary, Sir. ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You tell me. ...*(Interruptions)*.... You address the Chair. ...*(Interruptions)*....

SHRI N. JOTHI: Now, Sir, let the Prime Minister reply on this. ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete, otherwise, he will take another five minutes.....*(Interruptions)*....

SHRI N. JOTHI: YES, Sir, Seventeen judges were recommended. For eleven months this Governments sat on that. They did not move the file at all because of a very simple reason. One partner, one burdensome partner had said in the Lobby — they themselves outwardly admit it in the Lobby — that it is a nuisance and they are troubled like anything as if I have brought them on their shoulder. For eleven months they sat on that. ...*(Interruptions)*....

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI K. VENKATAPATHY): Don't give any wrong information.

SHRI N. JOTHI: Can I see your file, Sir? ...*(Interruptions)*.... Will you show the files to me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi, this is not the way. ...*(Interruptions)*....

SHRI N. JOTHI: Sir, they wanted their men to become judges.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, is you last point over? ...*(Interruptions)*....

SHRI N. JOTHI: The Supreme Court intervened and passed strictures ...*(Interruptions)*.... No, the Law Minister says, 'forget the past.' ...*(Interruptions)*.... Forget the past, this what the Law Minister said. ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. That was his last point. That is over ...*(Interruptions)*....

SHRI N. JOTHI: Sir, I am concluding.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you said that that would be your last point.

SHRI N. JOTHI: Yes, this is my last point. Sir, my last point is, para 28.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Mr. Jothi, try to understand my difficulty.

SHRI N. JOTHI: I understand, Sir. In para 28, page 9 of President's address, it is mentioned that there is a need to pursue reform of our judicial system, and speedy disposal of the ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi, give your suggestions.

SHRI N. JOTHI: Sir, we can only recommended the names of judges. If they are not appointed, what can we do? The file should go to the Supreme Court. They sat on that. They wanted their men. There are no qualified men with them.

SHRI K. VENKATAPATHY: This is wrong information. You are giving wrong information...*(Interruptions)*....

SHRI N. JOTHI: Sir, I want to see the file. Bring those 17 Judges; file here ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, that will not be allowed ...*(Interruptions)*....

SHRI N. JOTHI: Please bring the file, Sir ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that will not be allowed ...*(Interruptions)*.... Mr. Jothi...*(Interruptions)*....

SHRI N. JOTHI: Please bring the file, Sir ...*(Interruptions)*.... Why are you ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi, please address the Chair ...*(Interruptions)*....

SHRI N. JOTHI: No, you talk about transparency. There is no transparency even in the appointment of judges. That is the judicial reform, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI N. JOTHI: The only reform is, you must reform yourselves. You must refine yourself, otherwise, you will be thrown out within a few weeks. With these words, I conclude. thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Shri Varinder Singh Bajwa: Not present. Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ल: धन्यवाद, उपसभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन मुद्दों का जिक्र किया है, न केवल देश हित में वे सारे मुद्दे सही हैं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि पिछले 20 महीने के दरम्यान इस सरकार ने जितना काम किया है, उतना पिछले 7-8 साल की किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिला । जिस दिन मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, उसी दिन सुबह-सुबह मुझे मेरे एनडीए के एक मित्र का फोन आया और उन्होंने कहा कि अरे, यह क्या हो गया, देश में कहर बरपा, बाप रे, यह कैसी सरकार आ गई! मैंने कहा कि क्या हुआ? वे बोले कि सेंसेक्स दो हजार टूट कर नीचे गिर गया, स्टाक एक्सचेंज बन्द करना पड़ा, सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी? वे कहने लगे कि बिल्कुल। बिल्कुल सेंसेक्स से सारी अर्थव्यवस्था, अगर शेयर बाजार गिर गया, तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और व्यापार चौपट हो जाएगा, देश में त्राहि-त्राहि मच जाएगी। उसके बाद मैंने तत्कालीन हटे वित्त मंत्री जी का बयान भी पढ़ा, जो हमारे विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से शेयर बाजार गिरा है, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आज मैं उन्हीं लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि आज 57 साल के इतिहास में सेंसेक्स ने, शेयर बाजार ने 10 हजार का आंकड़ा छुआ है, आज उस अर्थव्यवस्था को वे क्या कहेंगे? हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री जी उस समय ताजे-ताजे हटे थे, उस अर्थव्यवस्था के लिए उनका क्या कहना है? क्या वे इसके लिए इस सरकार को शाबासी देंगे या नहीं देंगे? आज जिस तरह से 8 प्रतिशत की ग्रोथ, जो कल्पना के बाहर थी, हम प्राप्त करने जा रहे हैं और जिस तरह उस तरफ बढ़ रहे हैं, उससे इस देश की अर्थव्यवस्था को डा॰ मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार ने जिस तरह से मजबूत किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, आलोचना के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी जितनी भी सराहना की जाए, वह कम है । वह भी खास तौर से सड़क, बिजली, पानी, गांवों की समस्याएं, आम लोगों की समस्याएं, इनको ध्यान में रख कर किया जा रहा हैं अगर हम देखें, हमारी रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के तहत 200 जिलों में जिस तरह से गांवों के आदमियों को हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद थी कि लोग शाबासी देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि संसद का नियम होता है कि विपक्ष को आलोचना ही करनी है, तो अच्छे काम की भी आलोचना ही कर रहे हैं। उसके लिए शाबासी देने का साहस शायद वे नहीं जुटा पा रहे हैं। मेरे ख्याल से यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

मान्यवर, उपसभापति जी, अगर इस दो साल के पहले के 5 साल आप देख लें, तो किसी भी पावर प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ है, एक भी पावर प्रोजेक्ट हम नहीं लगा पाए। लेकिन आज इस सरकार ने न केवल 5 राज्यों में - मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र - पावर

प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, बल्कि हम बिजली समस्या से भी काफी निजात पाने जा रहे हैं। अगर न्यूक्लिअर एनर्जी समझौता ढ़ग से हो गया तो हमारी एनर्जी सिक्युरिटी की यह सबसे बड़ी गारंटी होगी और मुझे लगता है कि उसको अगर हमने प्राप्त कर लिया तो इस देश की तमाम समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।

सर, जो डोमेस्टिक वॉयलैंस एक्ट आया था, उससे महिलाओं को, चाहे वह गांव की महिला हो, चाहे समाज के निचले वर्ग की महिला हो, जो सबसे अबला है, उसको जो सुरक्षा प्रदान की गई, हो सकता है थोड़ी कुलबुलाहट हो पुरुषों के मन में, लेकिन उस एक्ट से महिलाओं को इस प्रकार सुरक्षा इस सरकार ने प्रदान की है कि अब उन महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और इस कानून के जरिए उनको एक ऐसा सहारा मिला है, जो सोनिया जी ने दिलवाया है। मैं उम्मीद करता था कि विपक्ष उसकी भी सराहना करेगा, लेकिन मुझे दुख है कि विपक्ष ने, विपक्ष उसकी आलोचना तो नहीं कर सकता, उसकी सराहना करने के बजाए उसक जिक्र ही नहीं किया।

नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए गांवों में हम पहुंचने जा रहे हैं, हेल्थ की समस्याओं के निदान के लिए। मान्यवर, इस सरकार का कमिटमेंट है कि 2009 तक हर गांव को बिजली और हर गांव को टेलीफोन मुहैया करा दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा काम है, जो होने जा रहा है।

माइनॉरिटीज के मामले में, अक्लियत के मामले में इस सरकार ने एक मंत्रालय का गठन किया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था और उनकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। मुझे इस बात का दुख होता है कि हमारे सामने के मित्र, जो भारतीय जिन्ना पार्टी, ओह सारी, भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन लोगों ने दो दिन तक काफी बड़ा * उठाया, हंगामा किया सेना में अल्पसंख्यकों की गिनती को लेकर और इस पर वोट की राजनीति करने का प्रयास किया। अब तो रक्षा मंत्री ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोइ प्रयास नहीं हैं, ऐसी कोई योजना नहीं है। इसलिए कम से कम अब उनको इस मुद्दे पर वोट की रोटियां सेंकनी बंद करनी चाहिए। मैं उनसे कहता हूं कि उन्हें अगर सैकुलरिज्म इतना प्यारा है, उन्हें अगर जिन्ना का सैकुलरिज्म अच्छा लग रहा है तो कम से कम खुद तो सैकुलरिज्म को अपना लें। दूसरों की प्रशंसा करते वक्त अगर खुद भी यही नसीहत लेकर उसको अपना लें तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा, उससे इस देश की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। इस मिनिस्ट्री ने जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के वैलफेयर के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने का फैसला किया है, वह निश्चित रुप से इस सरकार का सराहनीय कदम है।

---

*Expunged, as ordered by the Chair.

कार्टून विवाद पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, पिछले दिनों तमाम भाषण हुए हैं कार्टून विवाद पर और उनमें यह कहा गया कि सरकार ने कहीं न कहीं इस तरह से कदम उठाया कि इसको बढ़ावा मिला। सर, अक्तूबर माह में ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने डेनमार्क गवर्नमेंट से संबंध करके उनकी जबर्दस्त मज़म्मत की, उसी समय उनको इस बारे में लिखा था और हमारा बिल्कुल मानना है कि किसी भी धर्म के चित्र हों, चाहे वह देवी-देवताओं के चित्र एम॰ एफ॰ हुसैन ने बनाए हों, वे भी गलत थे। जर्मनी में अगर देवी-देवताओं को टॉयलेट वगैरह में दिखाया जा रहा है, हम उसकी भी भरपूर निन्दा करते हैं। उसके साथ-साथ जो प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून बनाकर उनका उपहास किया गया, उसकी भी हम निन्दा करते हैं।

श्री उपसभापति: शुक्ला जी, आपने जो * वर्ड इस्तेमाल किया, चूंकि * वर्ड अनपार्लियामेंट्री हैं, इसलिए उसको हम निकाल रहे हैं।

श्री राजीव शुक्ल: यह तो कई बार बोला जाता है।

श्री उपसभापति: वह जिस कॉंटैक्ट में बोला जाता है, वह इम्पोर्टेंट होता है।

श्री राजीव शुक्ल: ठीक है, सर, निकाल दीजिए।

सर, अभी जनेश्वर मिश्र जी यहां पर मौजूद नहीं है, मैं कुछ घंटे पहले उनका भाषण सुन रहा था। वैसे तो हमें समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनका भाषण सुनकार तो मुझे लगा कि जैसे कोई मुख्य विपक्षी दल का नेता बोल रहा हो।

श्री उपसभापति (उत्तर प्रदेश): समर्थन दे रहे हैं, गिरवी नहीं रख दिया है अपने आपको।

श्री राजीव शुक्ल: यही स्थिति हमारी भी वहां है, हम भी वहां गिरवी नहीं है। जनेश्वर जी की हालत हस्तिनापुर के भीष्म पितामाह की तरह है। अंदर-अंदर घर में बैठकर रोते हैं और बाहर आकर जबर्दस्ती उनसे भाषण कराया जाता है, पीछे से उनको प्रॉम्ट किया जाता है कि आप यह बोलो, आप यह बोलो। उन्होंने घर के बाहर एक तख्ती लगाई हुई है- ''लोहिया के लोग'', लेकिन पार्टी में दूरबीन लेकर खोजना पड़ता है कि लोहिया के लोग कौन हैं? पार्टी तो फिल्मी लोगों से भरी हुई है, पार्टी तो बिज़नेस वाले लोगों से भरी हुई है, पार्टी तो वित्तीय धांधली करने वाले लोगों से भरी हुई है से, लेकिन वह ''लोहिया के लोग'' का बोर्ड या तख्ती लगाकर ही खुश हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में अकेली सोनियां गांधी जी ही पावरफुल हैं और उनकी वजह से लोकतन्त्र को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वह किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती हैं और किसी को भी हटा सकती हैं। प्रधानमंत्री का चयन एक व्यक्ति कर रहा है, यह बहुत ही गलत हो रहा

*Expunged, as ordered by the Chair.

है और इसलिए पार्टी में किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी जनेश्वर जी यहां पर नहीं है, लेकिन मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक व्यक्ति की ताकत नहीं है, उनका यह गलत सोचना है। प्रधानमंत्री का चयन पार्लियामेंटरी पार्टी ने किया है। लेकिन उनके यहां पर जरूर एक व्यक्ति बहुत पावरफुल है और उसको लेकर पूरी पार्टी रो रही है। इस चीज़ को वह पहले अपने ऊपर, अपने घर पर लागू करें। उन्हीं की पार्टी का एक एमपी सब जगह बयान देते हुए घूम रहा है। वह एक व्यक्ति बहुत पावरफुल है, जो उनकी पार्टी चला रहा है। इसलिए जनेश्वर जी अगर वह फार्मूला खुद अपने ऊपर लागू करें और अगर उस एक व्यक्ति का हस्तक्षेप वह अपनी पार्टी में कम करें, उसकी शक्ति को कम करें तो मेरे ख़याल से यह उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा करने के बजाए वह दूसरों को तकरीर दे रहे हैं, दूसरों को भाषण कर रहे हैं।

उन्होंने महाप्रभु, अमरीकन अम्बैसेडर इत्यादि का भी जिक्र किया। अरे भई, अमरीकन अम्बैसेडर और अमरीका की बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप तो स्वयं ही अमरीकी नेताओं के लिए रैड कारपेट बिछाते हैं, मुख्यमंत्री निवास में अमरीका के पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए जश्न करते हैं।

श्री अरूण जेटली (गुजरात): तब आप यूपी के अन्दर ऐसी सरकार का समर्थन क्यों कर रहे हैं?

श्री सजीव शुक्ल: कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री आवास में, राज्यपालों और राष्ट्रपतियों के यहां शराब नहीं परोसी जाती है, लेकिन यहां ऐसी ही एक मुख्यमंत्री के आवास में पिंक शैम्पेन परोसी जाती है, स्कॉच बहाई जाती है। इसलिए क्या इन लोगों को या दीपांकर दा को इस संबंध में बोलने का कोई अधिकार है? लेकिन 57 साल से उनकी वही पॉलिसी है, वे किसी एक ही पॉलिसी पर दृढ़ नहीं रहते हैं। हम यह जानते हैं कि यह उनका अधिकार है और हम उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन जो लोग स्वयं रैड कारपेट बिछाते हों, वे अमरीका वाली बात करें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

कहा गया है कि बुश का स्वागत न करिए। हमारी परम्परा तो यह है कि अगर कोई राष्ट्रपति बाहर से आता है या हमने किसी को बुलाया है तो हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं, हम स्वागत करेंगे। वैसे ही स्वागत करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने इज़ारइल के राजपूत का किया था, जब वह लखनऊ में गए थे। अगर आप अपने मेहमान का स्वागत लखनऊ में कर सकते हैं, तो हमें बुश का स्वागत करने के लिए आप क्यों रोक रहे हैं? वह तो भारत सरकार के गेस्ट बन कर आ रहे हैं। अगर इसमें आपको आपत्ति है तो आप उन लोगों से यह बात बोलिए जो आपकी पार्टी के नेता भी हैं और अपने यहां पर राजदूतों को बुला कर उनका स्वागत भी करते हैं। मलफोर्ड को लेकर तो इतना हंगामा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इज़राइली

राजदूत से क्या बात हुई, वह भी सदन को बता दिया जाए, लेकिन वहां पर यह लोग चुप हो जाते हैं।

मान्यवर, दुनिया जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन हुआ था और रोज़ विधायक तोड़े जा रहे थे, तब स्पीकर कौन था। स्पीकर उनके पड़ोस की पार्टी का ही था और रोज़ वही इस चीज़ को मान्यता दे रहे थे। इस सरकार का गठन कैसे हुआ, इस बात को सभी जानते हैं, अत: अक्लियत की बात करना, माइनॉरिटी का बात करना, सेकुलरिज्म की बात करना, यहां कहां तक ठीक है? यह सब जनेश्वर जी से कहलवाया जा रहा है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वे बेचारे इस चीज़ को किस दबाव में कह रहे हैं, यह तो वह जानते हैं।

उन्होंने कहा कि हम आपको कुहनी मारते हैं तब आप इतना चिल्लाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वामपंथी दल आपको धक्का देते हैं, आप उन्हें कुछ भी नहीं कहते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वामपंथी दल धक्का नहीं देते हैं, जो भी बात होती है वामपंथी दल उसे सामने कहते हैं। वे समर्थन देने के बावजूद पीछे से छुरी नहीं चलाते हैं। यह केवल कुहनी मारने की बात ही नहीं है, इसकी पीड़ा कुछ ज्यादा ही गहरी है और इसके पीछे कोई और ही सोच छिपी हुई है।

उन्होंने एक बात और कही, जो खुद ही उनके मुंह से निकल गई थी कि मैंने राजनाथ जी को कहा है कि कुछ हम सुधरें, कुछ तुम सुधरो ताकि आगे अगर साथ खड़े होना पड़े तो खड़े हो जाएं। यह इशारा ही बहुत कुछ है और इसे समझना चाहिए। उन्हें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि यह क्या कहा गया है कि कल हम साथ बैठें और साथ खड़े हों, हमें यह मौका मिलना चाहिए।

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, मैं आपको लिए एक शेर कहना चाहता हूं –

''अपना चेहरा न पौंछा गया आपसे, आइना बेवजह तोड़ कर रख दिया''

श्री राजीव शुक्ल: वाह, वाह। उन्होंने टेप कांड की बात भी उठाई। मैं यह बात उनसे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार न किसी की टैपिंग करवाती है और न ही इसमें सरकार या कांग्रेस पार्टी का कोई रोल है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात होनी भी नहीं चाहिए और इससे पूरा सदन सहमत है। मान्यवर, एक बात मैं जुडिशियरी के ऊपर भी कहना चाहता हूं कि उस दिन भी बात आई थी, सवाल का पूरा जवाब नहीं आ पाया था, कम से कम जो न्याय लोगों को मिलना चाहिए उसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वह बात मुख्य रूप से छूट गई है कि 120 जुडिशियरी के पद ऐसे हैं जो सिर्फ हाई कोर्ट में खाली हैं। उसमें जो सवाल है, सरकार से आ रहा है कि व्यवस्था ऐसी है कि चीफ जस्टिस को जो प्रोपोजल भेजने चाहिए, वे नहीं भेजते। मेरे ख्याल से सरकार को इस तरफ ध्यान देकर जितनी जल्दी से जल्दी न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके, वह करनी चाहिए। जनेश्वर जी ने अपना भाषण खत्म करते वक्त कहा था कि किसी को बु..

लगे तो क्षमा करिएगा। तो मैं भी अपने भाइयों से कहता हूं, अबू आसिम भाई हैं, अगर बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा।

श्री राशिद अल्वी (आन्ध्र प्रदेश): सर, रूल-241, कल जब मैं इस मोशन को सेकंड कर रहा था, सुषमा जी यहां तशरीफ रखती हैं और मैंने भगत सिंह जी को यहां कोट किया था, तो कितने लोगों ने खड़े होकर मुझे टोकने का काम किया था, मुझे हाउस के अंदर मेंशन नहीं करने दिया था। सुषमा जी, यह किताब है भगत सिंह जी की और ए॰जी॰ नूरानी ने लिखी है। सिर्फ मैं इसे कोट कर दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): आपने ऑथर बता दिया तो आगे नहीं बताइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राशिद अल्वी: मैं आगे बताऊंगा, मैं यह बताना चाहता हूं कि फ्रीडम मूवमेंट के अंदर आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): आगे मत बताइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, अब छोड़िए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राशिद अल्वी: क्योंकि हिन्दुस्तान की जंगे आजादी से आपका कोई वास्ता नहीं रहा है इसलिए आपको इतिहास नहीं आता। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: दास्ताने नूरानी की नहीं पढ़नी हमको। ...(व्यवधान)... दास्ताने शहीद नूरानी की लिखी हुई नहीं पढ़नी हमको। हमें नहीं पढ़नी ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अब आप यहां ...(**व्यवधान**)...

श्री राशिद अल्वी: एक मिनट, सर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: किताब को कोट करने से, वह सब्जेक्ट नहीं है आपका ...(व्यवधान)... This is not a point of order. इसमें पोइंट आफ आर्डर आपका नहीं बनता।

SHRI RAASHID ALVI: Sir, under rule 241, please, allow me to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed, but some documentary evidence has to be given. That is what Members had asked. If you have got that, please place it on the Table of the House.

श्री राशिद अल्वी: सर, मुझे एक्सप्लेन तो करने चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह ए॰जी॰ नूरानी की लिखी हुई चिट्ठी, उसकी लिखी हुई किताब, बहुत अच्छा हुआ ऑथर का नाम बताकर उसकी क्रेडिबिलिटी बता दी। ...(**व्यवधान**)...

श्री राशिद अल्वी: अच्छा तो सुनिए, सर, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, कुछ नहीं सुनना अब। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: जिस वक्त उन्होंने शहादत दी उस वक्त यह किसी इंसान की या किसी इतिहासकार की आप कोई किताब लाकर बताइए ...(**व्यवधान**)... और तब फिर पढ़कर बताइए। नूरानी की किताब पढ़ा रहे हैं हमें। ...(**व्यवधान**)...

श्री राशिद अल्वी: ए॰जी॰ नूरानी पर ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। ...(**व्यवधान**)... भगत सिंह के बारे में ऐसी बातें बोलकर ...(**व्यवधान**)...

SHRI M.P. ABDUSSAMAD (Kerala): Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in this very important discussion on the Motion of Thanks to the hon. Rashtrapatiji. Many of the important points have already been covered and touched by the hon. Members who have spoken earlier. Considering the time constraint, I would like to confine myself to one or two issues, especially to the issue of welfare of minorities against which criticism was made by some hon. Members who have taken part in this discussion and other discussions which took place in this august House yesterday. I can't understand as to why even now, this hue and cry is made on the issue of minorities when the Government is coming forward with some concrete steps for the welfare of the minority communities in the country. It is nothing but in the interest of democracy that minority community is taken forward on the path of progress. They constitute a very important section of the population of the country and even now, it has been made an issue for poisonous propaganda by certain interested parties in the country. Sir, I can't understand this propoganda in this age of Right to Information. When the Central Government appointed a Committee, or the hon. Prime Minister appointed this high-level Justice Rajinder Sachar Committee for studying the condition of minorities, even that has been made an issue of propaganda. Sir, I believe, even now, some people in this country fear the facts and figures, they fear the realities, they fear the truth. Sir, in this age of Right to Information, where a lot of efforts are being

made, where we are speaking of transparency in the Government, transparency in administration, when such an effort is made by the Government to study the real condition of the minorities, it has been made an issue for tarnishing the image of the Government.

Sir, there was extensive marginalisation against minorities and there is disempowerment. Sir, there is inappropriate representation of the minority communities in the Parliament, in the State Legislatures, in Central Government service, police, para-military forces, judiciary, bureaucracy, public and private enterprises, in higher professionals and in institutions of higher learning. Sir, there is poverty, illiteracy and backwardness, and, in this background, to study the backwardness the hon. Prime Minister appointed a high-level committee headed by Justice Sachar. this backwardness of the minority community is an estblished fact and a number of official reports are there. So, why is this hue and cry being made on this? There were other committees/commissions also and so many reports are there. The Gopal Singh panel report, Reports of the 43rd round and 55th round of the National Sample Survey, the Programme of Action under the New Education Policy of 1986, such reports are there. It is not a new thing that the Prime Minister has appointed a Committee for studying the condition of the minorities. It is my appeal to the hon. brothers and comrades sitting on the other side of this august House that instead of making it an issue for political and even communal propaganda, they should consider the pathetic condition of the minorities in this country.

Sir, various schemes with regard to minorities launched by the Government have remained mostly on papers. Sir, there is a systematic campagin of vilification, hateful propaganda and communalisation of this issue. Communalisation of police is there. Wherever these riots took place against the minorites—all the Commissions have recorded and it is an established fact—the police behaved in a partisan way attacking the minorities instead of protecting their life and property. Sir, the Constitution guarantees freedom to all citizens and all sections of our society to profess their regligious beliefs, to establish and preserve their edcuational institutions.

So, under these conditions, the hon. Prime Minister has come forward with a bold decision of forming the Ministry for the Welfare of Minorities. I

congratulate the hon. Prime Minister for the glorious step that he has taken. That is golden action in the history of the welfare of the minorities in this country, and, we hope that the new Ministry will taken concrete steps, very creative steps to undo the backwardness of the minorties and to safeguard the tradition and ethnic identities, which are Protected by the Constitution.

Yesterday, Sushmaji was just arguing—I think, it was a verbal duel, just words and phrases—whether it is the 'minorities' or 'Muslims'. Everybody can understand that Muslims are minotrities. Many other minorities are there in this country but Muslims are the largest minority. It is the second largest Muslim population of this world but it is listed amongst the most backward communities so far as social, educational and economic backwardness are concerned. Sir, no country can be stable and vibrant if substantial section of its population fails to keep pace with the rest of the country, if they remains alienated from the mainstream, and, if it remains far below the national average in all walks of life. And, their representation in the Ministers, in the Government, is only below two percentage, And, Sir, only 1.6 percentage class I officers are from this community in the Central Government. So, urgent steps have to be taken by the Government to ensure the reservation of the backward classes and the minorities. Very recently, our Government in Kerala took a very concrete steps to fill the gap of reservation of the backward sections of the community, as per the report of Justice Narender. We did it in Kerala. Kerala is the cradle of communal harmony. We did it in a very harmonious way. There was no quarrel; there was no unnecssary feud or there was not any kind of communal propoganda.

This was done democratically, in a very secular manner, And, that has been described as a very historic step to ensure the reservation of the backward classes. Sir, it is a national necessity that the Government must draw this talented community into the mainstream. So, for that, the wonderful composite culture of the country has to be recognised. The Constitution has recognised it. The national leaders, the architects of the Indian Republic, recongnised it. I can't understand, why, even now, after passing more than fifty years of our march to democratic credentials and secular ideals , some of our people , some parties in this country, are not willing even to recognise the existence and the rights of the minorities. it is actually because they are not able to recognise the pluralistic culutre of

5:00 PM

India, the pluralistic nature of India. Sir, everywhere in the world, there is a need nowadays for the protection of the plural nature, pluralistic culture of the world. Everybody here was reffering to the onslaught of imperialism. The clash among civilisation which has been described as a new theory from the west is a very dangerous one. But, sir, our country has always stood not for the clash among civilisation but for the dialogue among civilisation, not for the fight but for harmony between cultures and civilisation. And, I believe, Sir, that it has a new relevance, latest relevence, in the present scenario of international and inter-culture relation that prevail in the world today. For this, we have to agree that everybody has to live in this universe. The pluralistic nature of the world and our country has to be recognised. Even now resisting that, even now criticising that, is not in the interest of the country. We must try not for exclusion but for inclusion. The marginalized minorities of the country do not need exclusion; they want inclusion. Sir, Muslims and other minorities are valuable assets. I would like to remind my hon. brothers there that they are valuable national assets. So, it is the duty of every Government to utilise that assets for the welfare of the nation, welfare of the country. Sir, I would like to quote Mr. Wilfred Smith, who is considered as one of the greatest historians of the modern period. He says, "Islam in India would emerge as more progressive, dynamic, liberal and creative than Pakistani Islam". Sir, I would like to repeat, " Islam in India would emerge as more progressive, dynamic, liberal and creative than Pakistani Islam". And, the Muslims of India, the minorities of this country, have always stood with the country. There is no monopoly for any people in this country on the basis of nationalism. Everybody in this country is patrotic and everybody is nationalist. They adore the country. When there was a need for any sacrifice for the country, the minorities were always in the forefront in making the sacrifices for the welfare and progress of the country. And, Sir refusing to recognise their existence even now is a crime against the nation in my very humble words. Sir, the Constitution protected their rights under Articles 25 to 30. I am repeating all these things. Even yesterday much of our time was wasted in discussing this minority, minority, minority. What is a appeasement of minority? What is this appeasment? They are below the national average and if something is done by the Government to protect them, to bring them forward, then, it is appeasement! What does this word 'appeasement' of the English dicitionary mean? That our hon.friends must expalin not

only to this august House, but to the country also. Sir, the national leaders recognised this, sometimes calling appeasement, sometimes questioning the loyality.

Sir, I am just reminded of one thing here. Formerly, the minorities of the country were called *Babar ke aulad,* the sons of Babar. Now they have changed this stand. Now, they say that they are not minorities, because the blood that flows in their veins is the blood of the same Hindu brethren. They have not come from outside. So, they are not minorities. This is the latest stand. A few years back, they were the sons of Babar. Now, they are the sons of the Hindu ancestors. They are changing their stand. They change their stand that suits their political stand. But, Sir, whatever may be the description, the minorities are Indians, and they belong to this country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: I am concluding in a few minutes , Sir, Sir, 99.9 per cent of Muslims and Christians have not come from outside. Hence they cannot be called minorities. This is the latest statement of a leader whose name I would like to quote here. But it is one statement. Sir, this is blind hatred. The Muslims, the Christians and other minorities are hundred per cent Indians, and they will remain Indians whatever may be the oppositions. But that does not mean that they ceased to be religious minorities. Even that does not mean that they ceased to be religious minorities. Even there are some section in our country, which are double minorities. For example, Kashmiri Muslims. They are ethnical minorities as well as religious minorities. There are the Christians in the North-East. They are religious minorities as well enthnic minorities. So, everywhere in the world now there is a movement going on for the protection of minorities; and our country has paved the way for that. We are the forerunners in this respect. We cannot go back on our stand for respecting all sections of our country. India is a country of different religions, cultures and languages. Therefore, its strength, solidarity, stability and progress depend upon the unity and harmony of all sections. (*Time-bell*)

Sir, I am reminded of the statement of Ms. Mary Robinson, who was the UN High Commission for Human Rights, and now she is the Head of the Ethical Globalisation Initiative. She says, "The ideal of equality if after all the touchstone on which the guarantees of international human rights have been built. It is the principle of non-discrimination. Ultimately, we are

sall striving to ensure inclusiveness and an end forever to exclusion and all forms of discrimination."

I think the Government's move is in the right direction to avoid discrimination and to ensure inclusion. For that, these kinds of steps are very much essential.

Even, Sir, the Ramakrishna Mission have petitioned the Calcutta High Court that they should be declared as religious minority. I don't know what will be the reaciton of our friends to this thing. But they have approached the Court. They are having their own sets of beliefs and customs. So, they want that they have to be recognised as minority community.

Finally, I would like to say about this cartoon issue. They are the symptoms of the same disease. All over the world, there is a very serious effort to bring theory of clash among civilisations is a meance to humanity. It is creating feud' they are trying to create tension in the world. What we want today in the world is vigilance against imperialism; a vigilance against every theory of clash among cultures and civilisations. Sir, I respect religious personalities whether they are Muslims, Hindus, and Christians, *devi-devata* or prophets or *acharyas*. They have to be respected. An artist's freedom of expression does not mean that it should wound the faith of crores and crores of people who live in this world. They should not be given such freedom. That will create tension. Plato in his *Republic* said, state is in his conception, there will not be any relevance for so-called artists who destroy the discipline of the country. For the society, discipline is important. So, Sir, I congratulate, once again, the Government and the hon. Prime Minister for all the concrete steps and also for the protection and welfare of the minorities. I support this Motion, Sir. I would just conclude it by saying,

"न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तां वालो,

तेरी बरबादियों के मशवरें हैं आसमानों में।"

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE (Assam): Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks on the President's Address which is a virtual statement of the Government's policies and programmes. I would like to mention a few points because we have no time. I understand it. First of all, I should congratulate my Government that they have taken five-pillar scheme, that is. the National Employment Guarantee Act, Bharat Nirman, National Rural

Health Mission, Jawaharlal Nehru Mission for Urban Renewal and Sarva Shiksha Abhiya. These programmes are aimed at providing income security to poor and bridge poverty gap, address gaps in basic health and provide for caring process of urbanisation and universal mid-day meal programme.

The national rural programme is a historic programme. I think, it is introduced for the first time in the world. It is a very important programme and 200 districts have been taken up. But in these discussions, no hon. Member ever mentioned about this historic scheme. Yes, Opposition has a right to criticise the Government. It is a democratic country and we should criticise on constructive basis and this scheme is a historical scheme. But everybody tend to criticise the Government for delay in implementation of declared systems. But, Sir, I must mention that on this Bharat Nirman and other schemes and national programmes, there are differences. I understand that there is a delay in no implementation. We have declared the scheme, but there is no implementation. There should be interest in every constituency. Particularly the representatives of Parliament should see the scheme in toto. The Government is dependent only on these bureaucratic officers. They mostly depend on their report. On the basis of their report, Government takes all the steps. This is a bad trend. I differ with it. Sir, everybody said that price rise is there. Yes, price rise is there. We are a developing country. We are competing in the world with powerful countries. Now, we are in the same position. Everywhere there is a price rise. Every Member has visited different foreign countries. I think they should realise what is the position of price rise in those countries. I also have visited some countries and observed that there is corruption, there is price rise. Everything is there. But our country is now rising day by day. There is no question of Congress Party or NDA or any other party. The question is, it is the greatest democratic country in the world and we are going to improve and we should mobilise our people. And at this time, we have already achieved our 50 per cent goal. It is a matter of great satisfaction that due to the highest priority given to welfare and development of rural economy, there has been an increase of 60 per cent in the credit of agricultural sector. A consensus reached between the Centre and the States will facilitate revival package for short-term rural cooperative credit structure, involving Rs. 14,000 crore. A study on revival package for long-term cooperative credit structure is also being made. That was discussed with the respective State Governments and that is why, the

Central Government has taken that decision. Then, better water management; the UPA Government has started water management policy.

The Railways has regained its pride position, with perceptible improvement in its performance. It is a matter of satisfaction that a decision has been taken to build two high capacity freight corridors—Eastern Corridor from Ludhiana to Sonnagar and Western Corridor from Jawahar Lal Nehru Port Trust to Dadri with an investment of Rs. 16,000 crore. However, it is a matter of concern that the work relating to conversion of meter gauge to broad gauge, which is being done in my belt, that is, the North-East, is not being implemented properly. The Government has declared that scheme a national scheme. Money is there, but the Progress is tardy. There is no Sign of visible progress in respect of the work relating to conversion of meter gauge to broad gauge between Lumding and Silchar in Assam besides Jiribum to Imphal and Kumarghat-Agartala railway lines in the North-Eastern region which were declared national schemes, work has not made much headway. I request the Government to give priority to this work as the same form part of development of the North-Eastern region. Otherwise, the object of declaring this scheme a national scheme will remain only on paper. I am compelled to criticise the Government, for various Shortcomings, though I am in the ruling party. We must bring those things to the notice of the Government, and the Government will definitely take action. Whenever the leaders from the Opposition, like Mr. N. Jothi, speak, every time, they give some constructive ideas to the Government, and the Government takes their suggestions seriously, and take steps in that direction. We are proud that the world economist is now the Prime Minister of India. He has taken some steps to improve the condition of the country. The Government has taken so many steps to improve the condition of the country, and the country would benefit from those steps. We have taken some new initiatives. But, we are also continuing with some steps taken by the previous Goverrnment, to improve the lot of this country. The Government has taken a number of steps to fulfil the commitments made in the National Common Minimum Programme, and to accelerate the pace of ensuring that information reaches the masses for bringing greater transparency, required for eradication of corruption and better connectivity, the Government has passed the Right to Information Act.

Sir, various communities live in this country. There is no question of Muslims, there is no question of Budhists, there is no question of Bengalis

or Hindus. All the communities are living together. This is combined India, secular India, according to the Constitution of India. We are following the Constitution of India. The Government may be having some shortcomings. I understand that thing. But, you will appreciate that India is one nation, and the Government is taking all steps to maintain the unity and integrity of India so that it remains as one nation. That is why we have taken such steps.

Now, I come to the question of foreign policy. From the time of Pandit Jawaharlal Nehru, when he took over as the first Prime Minister of the country, we have maintained the position of neutrality in respect of our foreign policy. We are having very good relations with America, China, Russia, Middle East, and our neighbouring countries and Pakistan. At present, our Government has taken some positive steps to improve the conditions in Jammu and Kashmir, as a result of which the law and order situation over there and the North-East is going to be improved. So, I fully support the President's Address.

Lastly, before I conclude, I would like to impress upon the Government to formulate some mechanism for close monitoring of the progress of various projects under the supervision of not only the bureaucratic set up, but also the elected representatives of the respective constituencies. I would like to suggest that a group of young and dedicated Ministers should be set up for this purpose, who by their wholehearted effort, will ensure the time-bound implementation of these projects, which would go a long way in achieving positive results for our country. Thank you.

श्री उपसभापति: श्री आर. षण्मुगसुन्दरम। माननीय सदस्य अनुपस्थित। श्री एम.एस. गिल।

डा॰ एम.एस. गिल (पंजाब): उपसभापति जी, पहले तो मुझे कितना टाइम मिलेगा, मुझे पता होना चाहिए। मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं करूँगा, एक अंदाज होना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are the last speaker of your Party. You are last but one. Totally, you have got 32 minutes. So, you can share between you and Nandi Yellaiahji.

श्री एम.एस. गिल: 15-20 मिनट मुझे मिलेंगे, आपने यही कहा न।

श्री उपसभापति: हाँ, मैंने यही कहा। इसलिए मैंने दोनों को बताया।

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश): मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए।

डा. एम.एस. गिल: यह तो हमारे आपस की बात है।

उपसभापति जी, धन्यवाद। चलो, शुक्र है, पंजाब की और मेरी बारी आ ही गई। मैं तीन दिन से इन्तजार कर रहा हूँ। यह मामला ऐसा है कि इसके ऊपर मुझे जरूर कुछ कहना है, क्योंकि यह पुराने काम का भी और आगे जो करना है, उसके बारे में भी राष्ट्रपति जी ने हमें जो अभिभाषण दिया था, उसमें बड़ी बारीकी में कहा है। मैंने इसे ध्यान से सुना था, मैंने इसको पढ़ा भी है। अब ये आंकड़े तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं कि 1999-2004 तक 5.5 परसेंट था, अब इस साल यह 7.5 या 8 होने वाला है और आगे 10 परसेंट जीडीपी ग्रोथ की भी आशा है। यह तो सब कह चुके हैं, लेकिन जो सेविंग्स रेट है, वह बहुत बढ़ा है, कि यह 29 परसेंट है और इंवेस्टमेंट 31 परसेंट हुई है। मैंने वह जमाना भी काटा हुआ है, जब गवर्नमेंट में 20-21 परसेंट की चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि सेविंग्स के बगैर आगे कुछ बन नहीं सकता, इंवेस्टमेंट नहीं हो सकती, चाहे कोई भी सरकार हो। यह सबको पता है। यह चीज बहुत अच्छी है। लेकिन मैं यह सोचता था, इसको पढ़-पढ़ कर और सुन कर, टिप्पणी भी और तारीफ भी, कि सरकार का नजरिया क्या है, किस नुक्ते के ऊपर वे सोच रहे हैं। मैं यह जरूर मानता हूं, जो राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारा नुक्ता प्लुरलिज्म, टोलरेंस, कंपैशन, डेवलपमेंट, आगे बढ़ने का, सारे लोगों को ले जाने का, सबके लिए सोचने का, इम्प्लीमेंट करने में डिफरेंसेज़ तो हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो सके, जो अपनी अक्ल और जो अपनी सूझ-बूझ कहे, अच्छी चीज़ बना का उसको जोर से लागू करें और आगे ले जाएं। उसके नतीजे भी जो कुछ हैं, जो सामने पेश किए गए, वे मैंने सुने हैं। ये जो 4-5 प्रोग्राम हैं, जिनकी बहुत चर्चा हुई-एम्प्लायमेंट का, भारत निर्माण का, रूरल हेल्थ का, अरबन मिशन का - ये सारी उसी दिशा में जा रहे हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं और मैं तो इसको खास मानता हूं कि इस देश में सवाल तो हमेशा यही रहेगा कि बिजली दो, पानी दो, सड़क दो, रेलवे लाइन दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, टेलीफोन दे दो, क्योंकि आजकल टेलीफोन भी कम्युनिकेशन ही है, वर्बल हो या सड़क से हो, बात एक ही है। इरिगेशन जरूर बढ़ाओ। पिछले 10-15 साल से इरिगेशन में इंवेस्टमेंट नहीं हुई है, मैं बार-बार सुनता रहता हूं, पढ़ता भी रहता हूं। रूरल हाउसिंग, शहर की हाउसिंग आजकल पिछले कुछ समय से बैंके जोर से लोन दे रही हैं, हर क्लास को अरबन में दे रही हैं, जो भी मिडल क्लास हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, सारे अपने मकान खरीद रहे हैं। ऐसा मैं पढ़ता रहता हूं। इसकी एक्सपैंशन हुई है। लेकिन अपनी ज़िन्दगी में मैंने यह देखा है कि रूरल हाउसिंग को कोई गिनता ही नहीं है। हम तो कच्चा कोठा खड़ा करें और वे खुद ही बनाएं और खुद ही रहें। इस देश में वह किसी की जिम्मेदारी नहीं रही है। को-ऑपरेटिव में मैंने सारी उम्र काम किया है, मैं जानता हूं, मैं रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव भी था, हिन्दुस्तान का को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी था। उस वक्त पहली दफा पंजाब को-ऑपरेटिव में बहुत आगे था। बहुत अच्छा था, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ। ग्रीन रेवोल्यूशन को-ऑपरेटिव क्रेडिट से ही आया। मैंने उस वक्त पहली दफा पंजाब में हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडेरेशन शुरू की और जो

कुछ अब काम कर रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत किया। गुजरात बहुत अच्छा मॉडल था, लेकिन शहरों में। 10-11 आदमी इकट्ठे हो कर प्लॉट लेते थे, उन्होंने बहुत इंवेस्टमेंट भी की। ये पुरानी बातें हैं मैं यह जो देख रहा हूं कि 60 लाख रूरल हाउसिंग करेंगे, अगर करेंगे, वह तो अभी देखना है, आने वाले साल में और उसके बाद, अगर करेंगे, तो यह करने का काम जरूरी है। क्योंकि सारा हिन्दुस्तान अब भी या तो झोंपड़ी में रह रहा है या कच्चे कोठे में रह रहा है। उनका क्या करना है? उनके लिए उनको 1, 2 परसेंट नहीं बल्कि 0 परसेंट पर एक-एक लाख रुपया ही दे दो, जो गांव वाला या किसान मांगता है, तो बात कुछ बनेगी। इसलिए मुझे यह अच्छा लगा और यह सारी दशा अच्छी है।

रूरल हेल्थ मिशन, हेल्थ की मैं बात करना चाहता हूं। मुझे आजकल चिंता है कि हेल्थ और ऐजुकेशन, ये दोनों कुछ देर से कमर्शियल की तरफ चले गए हैं मैं कुछ को कह सकता हूं होटल-हॉस्पिटल, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी कभी-कभी जाना पड़ता है। बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत बंदोबस्त है, तीन-तीन, चार-चार कमरे मिलते हैं या तो कोई सेठ खर्चा दे दे या सरकार दे दे, तो फिर मेरे को एक सुइट मिलता है दो कमरों का रहने के लिए। एक रात का उसका खर्चा बेअंत है। मैं कहता हूं कि दिल्ली में बहुत हॉस्पिटल बने हैं, शायद जमीनें भी उनकी सस्ती मिली हैं, इसलिए दो-चार गरीब भी बुलाएंगे, यह सब मैं पढ़ता रहता हूं। ये मेरे साथी बैठे हैं, अभी-अभी आए हैं, ये तो बहुत जानते हैं दिल्ली को कि वाकई कोई गरीब वहां से निकलता है या नहीं। यह एक सवाल है, इसे दिल्ली वाले जानें और दिल्ली वाले ही जवाब दें। लेकिन, आनेवाले समय में जब हम लिबर्लाइजेशन की बात कर रहे हैं, विदइन कोर्ट सारा कुछ हो रहा है, तो देश के लोगों को हेल्थ बंदोबस्त क्या मिलेगा, सवाल यह है? रूरल हेल्थ प्रोग्राम नहीं, बल्कि सारे देश का हेल्थ प्रोग्राम मैं तो देखना चाहूंगा। जैसे इंग्लैंड में सैकिंड वर्ल्ड वार के बाद लेबर गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ सर्विस चलाई थी, मैंने उसको देखा है, मैं जानता हूं और मैंने उसका इस्तेमाल भी किया है। पहले उनकी यह स्कीम थी, कि आप अगर बाहर से भी आएंगे तो भी हम आपका मुफ्त इलाज करेंगे। तो वह जो मैंने देखा है, यहां उसकी जरूरत रहेगी क्योंकि इस देश में अभी भी अगले 50 वर्ष तक तो बहुतेरे गरीब लोग रहेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं, चाहे जो मर्जी ग्रोथ रेट हो जाए। इसलिए मैंने एक दफा यहां कहा था कि सैंसेक्स बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, पर हम लोग सैंसेक्स के लोग न बन जाएं, बल्कि कम्पेशन के, चिंता के लोग रहें। आज दिल्ली में जो मेरे जैसे रिटायर्ड लोग हैं, उनका भी इलाज नहीं हो सकता, बहुत कच्चा बंदोबस्त है। नेशनल हेल्थ सर्विस में रिटायर्ड सैक्रेटरी, जाकर देखिए उनका क्या हाल है। जिसके पास पैसा है या कोई बंदोबस्त है या कवर है, उसी का इलाज हो सकता है, इतना ही कहूंगा।

अर्बन रिन्युवल मिशन, ठीक है, होना चाहिए। मुझे खुशी है कि 63 शहरों का, बड़े शहरों के बाहर के शहरों का भी नाम है। मैं एक चीज सोचता हूं कि हर चीज में आपको चिंता मुम्बई, बंगलौर, कोलकाता या हैदराबाद की नहीं होनी चाहिए, हिन्दुस्तान के जो बाकी कस्बे हैं - मोगा है, गाजियाबाद है, जबलपुर है, पटना है या कोई और है, उनकी भी चिंता आप करें। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर कंट्री साइड में डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर आप चाहे जितना करते रहो, कुछ नहीं होगा। यहां कॉमन वेल्थ गैम्स के लिए तो बहुत खर्चा करेंगे, लेकिन जो गरीब बैठे हैं, खास तौर से इन प्रान्तों में - यू०पी०, बिहार और उड़ीसा में, माफ करना मुझे, गुस्सा नहीं करना और जगह भी होंगे, वहां से यहां आबादी आती रहेगी और आप जो सॉल्यूशन करते हैं, झोपड़ी वगैरह को इल्लीगल करके, मेरी नज़र में वह कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसीलिए वे फेल होते रहते हैं। इसलिए सारे देश के अर्बन का सोचो, दिल्ली और बंगलौर जैसे बड़े-बड़े शहरों से बाहर भी सोचो।

सर्वशिक्षा अभियान, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज शायद यूनिवर्सिटीज़ जरूरत से बहुत ज्यादा बन रही हैं और इसमें मुझे एक और चिंता है कि अब लिबर्लाइजेशन के दौर में स्टेट्स 100-100, 50-50 यूनिवर्सिटी ऐसे सैंक्शन कर रहे हैं, जैसे लड्डू बाँट रहे हों। यह क्या हो रहा है? पंजाब, जालंधर में शायद अभी एक 'लवली यूनिवर्सिटी' बनने वाली है। आप 'पिंकी' बना लो, ये -'डिंकी' बना लें, ऐसा भी करलो। पंजाब में जब डेवलपमेंट थी तो पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला बनी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, दुनियां की मानी हुई एक यूनिवर्सिटी और गुरु नानक यूनिवर्सिटी, अमृतसर बनी और पंजाब कवर हो गया।

यह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं और यहां तक कि गवर्नमेंट भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बना रही है। उसके पश्चात् पंजाब में तीन-चार यूनिवर्सिटीज़ और भी बनीं, हरियाणा में भी बनी, लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं फ्रैंकली यह कहना चाहता हूं कि हम हायर एजुकेशन पर तो बहुत पैसा लगा रहे हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं पंजाब, अमृतसर इत्यादि जाता रहता हूं, वहां पर लोगों ने जो स्कूल बनवाए थे, आज वे सब खत्म हो गए हैं। मैं देखता हूं गांव में, खासकर लड़कियों के स्कूलों में कमरे बनाए जाने हैं, इस सवाल के बारे में सोचा जाना चाहिए।

इसमें दो चीजें और भी हैं। मैंने मिड डे मील के बारे में सुना था। ठीक है, बच्चों को यह मिलना चाहिए, उनके लिए न्यूट्रिशियन्स की जरूरत है, लेकिन इसके अन्दर एक बात और भी सोच ली जाए कि कहीं ऐसा न हो कि वे सारा दिन रोटी ही पकाते रह जाएं, टीचर भी रोटी पकाएंगे और बच्चे भी पकाएंगे या फिर वे लकड़ियां ही लाते रहें।

मैंने एक बात और भी गांव में सुनी थी, जो अभी-अभी मेरे दिमाग में आई है और उसके लिए मैंने कमीशन वाले साथियों से भी बात की कि अव्वल तो टीचर आते ही नहीं हैं, मैं पंजाब के बारे

में तो जानता हूं, अव्वल तो वहां पर पूरे टीचर हैं ही नहीं और अगर हैं भी तो या तो वे सैन्सस के लिए गए हैं या वे मवेशियों को गिनने के लिए गए हैं या फिर वे इलेक्शन कमीशन की लिस्टें बनाने के लिए गए हैं। पचासों ऐसे काम हैं जो उन्हें सौंप दिए जाते हैं और जिसके बहाने वे हाज़री लगा कर वहां से चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस विषय पर विचार करना होगा।

एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही थी। कल भी कुछ लोगों ने जज़्बातों में इसके बारे में बात की थी और मैं अब भी इसके बारे में कहना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव क्रेडिट या अन्य जो भी चीजें हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके कारण क्रेडिट बढ़ा है, मैं मानता हूं कि सरकार उसे बढ़ा रही है, वह तो ठीक है, लेकिन हमें एक और चीज़ को भी बारीकी से देखना होगा। मैंने कोऑपरेटिव क्रेडिट पर काफी समय तक काम किया है और मैं इसके बारे में जानता भी हूं और मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप फिगर तो दे रहे हैं लेकिन उसका फायदा किसे पहुंच रहा है? कोऑपरेटिव वाले ने जो क्रेडिट लेना है, वह तो उसे ले ही नहीं सकता है क्योंकि उसके लिए वह एलिजिबल ही नहीं रह जाता है। जब वह एलिजिबल ही नहीं है तब आप चाहे जो देते रहें, उसका क्या फायदा होगा? बैंक फिगर तो दिखा देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को शायद उससे थोड़ा-बहुत ही फायदा पहुंचता होगा और वे उसी को उस कोटे के अन्दर गिन लेते होंगे। मैं आज वहां पर इस चीज़ को चैक नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूं, लेकिन इस चीज़ का मुझे पूरा अन्दाज़ा है। आप इस चीज़ को बारीकी से देख कर बताइए कि पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र के अन्दर कितने छोटे किसानों को फायदा मिला है, हमें असली चीज़ तो यही देखनी है और इसके बारे में हमें सोचना होगा।

मैं एक बात व्हीट इम्पोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में गंगानगर एवं नॉर्थ इंडिया में कई स्थानों पर गेहूं पैदा की जाती है जल्दी ही उसकी फसल भी आने वाली है। मध्य प्रदेश के अन्दर तो उसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है और हमारी तरफ भी शुरू हो चुकी है। इस समय जिस प्रकार से तेज़ी के साथ गर्मी फैली है, विंटर क्रॉप के ऊपर, ऑयल सीड्स एंड व्हीट के ऊपर इसका खराब असर पड़ेगा। चूंकि टेम्परेचर बहुत जल्दी काफी ज्यादा बढ़ गया है, दिसम्बर की बारिश एवं बर्फ भी नहीं आई, फरवरी की बारिश भी नहीं आई और अब तो इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है, इससे ग्रेन श्रिवल हो जाता है और सरसों इत्यादि फसलों को भी एसिड लग जाता है। इन इलाकों में गेहूं की फसल को लेकर बहुत चिन्ता है क्योंकि हमारे ट्रेड पर भी उसका काफी असर पड़ता है और वह ट्रेड को डिप्रेस कर देती है। एक तरफ तो वे उसे खरीद लेंगे और दूसरी तरफ डबल प्राइस पर उसे बेच देंगे। हमारे पुराने वाइस चान्सलर डॉक्टर Jow इसके बारे में बार-बार लिख रहे हैं और लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि पिछले 2000 से 2005 तक हम 3.5 करोड़ टन अनाज का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इस बारे में हमारा सोचना बहुत आवश्यक है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं?

अब मैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, मैं इसके बारे में बहुत समय से पढता भी आ रहा हूं। आज अगर टेक्निकली इसकी जरूरत है और हमें इसे समय की मांग के हिसाब से करना है, तो इस पर अवश्य सोचा जाए। यहां पर बेतवा वाले विषय का भी जिक्र किया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक दिन सुबह इतनी आसानी से यह कह देता है कि सारी नदियों को पांच लाख करोड़ के अन्दर लिंक कर दिया जाए। यह तो इकोनॉमिक पॉलिसी है, टेक्निकल पॉलिसी है, लेकिन यह आया जुडीशियरी की ओर से है और वह भी तब जब इसके बारे में कोई केस नहीं चलाया गया न ही कोई और बात हुई। इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूटिव्स ने ही करना है, चाहे वे इधर के हों या उधर के, उन्हीं को इसके बारे में सोचना है और देश का परामर्श भी लेना है। मेरा ख़याल है कि अब मैं इस मसले को उठा रहा हूं, यदि हम इस पर कुछ सोच रहे हैं तो वह बहुत अच्छी बात है।

हाईवे डेवलपमेंट की बात भी हुई थी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ही बोलूंगा कि जो क्वाड्रीलेटरल बना रहे हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि नॉर्थ इंडिया दिल्ली में तो खत्म नहीं होता है, वह तो अमृतसर में खत्म होता है। कश्मीर की तरफ तो पहाड़ी सड़क जाती है, नहीं तो श्रीनगर भी उसी में शामिल होता है। इसके ज़रिए अब आप अमृतसर से लाहौर तो नहीं जाएंगे बल्कि आप काबुल जाएंगे। मैंने फॉरेन एफेयर्स की कमेटी में भी इस बात को उठाया था और वे मेरी बात को स्वीकार भी करते हैं। आगे आने वाले पांच-सात वर्षों में वह सड़क काबुल को जाएगी, काबुल से वह तुर्कमेनिस्तान को जाएगी और फिर तुर्कमेनिस्तान से लंदन तक ट्रक जाया करेंगे।

गैस की पाइप लाइन अभी तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाली है और उसमें हम भी शामिल हैं। यह ख़बर अभी कल ही की है और मैंने इसके बारे में फॉरेन एफेयर्स मिनिस्ट्री से भी बात भी की है साथ ही साथ अख़बारों में भी इसके बारे में आया है। तो यह जो है क्वाड्रीलेटरल, अमृतसर से शुरू होती है और छः लाईन आपको अमृतसर में जरूरी इकॉनोमिकली है। पहले भी था, नहीं बना, अब तो बनाना ही पड़ेगा, सोच लें। जो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन रही हैं, मैं इस वक्त उस झगड़े में नहीं पड़ूंगा, न इतना टाइम है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए कि अमृतसर में 80 करोड़ पिछले 5-7 साल में सैंक्शन करके दो-दो ईंटे लगती रहीं। अब फिर शायद कहते हैं कि 80 करोड़ लगाएंगे। तो हमारा भी पांच सौ करोड़ लगा दो। That is a supplementary airport to Delhi. Delhi is overcrowded. You talk about all that. That is your Western gateway, both land and air. दिल्ली भी है लेकिन उसके आगे वह है। अगर लाहौर 100 इंटरनेशनल फ्लाइट लेता है तो अमृतसर को जो मैं 30 साल पहले कह चुका हूं more buffaloes than men, why should we have it? So, please think about it. रेलवेज का जो कॉरीडोर बनाना है, मैं उसकी तारीफ करता हूं कि यह बहुत अच्छा आइडिया है नौर्थ साउथ भी और सोनागार को भी। लेकिन लुधियाना में ही उसका अंत क्यों

होगा, वह तो अमृतसर से चलेगा और आपका ही नुकसान होगा अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे। किसने सोचा है, क्यों सोचा है, मेरे से कोई बात कर ले और उससे आगे वही चीज, रेल भी आपकी काबुल से आगे सोलांगपास से आगे लंदन तक भी जाएगी। ऐसी टेक्नॉलोजी है, अगर हम ट्रेन कश्मीर ले गए हैं, श्रीनगर में मैं एक-एक पहाड़ जानता हूं, तो आपका ख्याल है कि सोलांगपास वह अफगानिस्तान का है, वह नहीं निकलेगी? आगे तो फलेट ही है पंजाब की तरफ। तो सोचिए इसका। आप अमृतसर को क्यों भूल जाते हो। स्पेशली इकॉनोमी जोन, वह बेचारा सिद्ध उधर रोता रहता है, वह वहां का एम॰ पी॰ है, लेकिन वह अमृतसर का भी बना दो, जो भी मंत्री हो, सोच लेना, जुडिशियरी सिस्टम का जिक्र किया, मैं इस पर जरूर कुछ कहना चाहूंगा।

श्री उपसभापति: नहीं-नहीं, आप बोलिए। आपके कुलीग ने कहा कि वे तीन मिनट लेंगे। वे तीन मिनट लेंगे, इसलिए उनका टाइम भी मैं आपको दे रहा हूं।

डा॰ एम॰ एस॰ गिल: I will finish. I will finish. जुडिशियल सिस्टम, बड़ी देर से चला आ रहा है, कुछ शायद प्रपोजल भी हैं। जो कंटैम्प्ट लॉ का अभी चेंज हुआ है, लोक सभा में हो गया, इधर आ रहा है, अच्छी बात है, सबको आर्ग्यूमेंट का पता है, हमें भी पता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जुडिशियल अपोइंटमेंट हैं, there cannot be self-cloning. No democracy, no system in the world allows it. So, what it used to be, made by Ambedkar it has been modified by judicial decisions and you are now thinking of a system—all sides have been thinking—have a good system but there has to be democratic, reasonable system. I heard also Mr. Jethmalani, if you think that you will solve India's pendency of cases by simply having more judges, then, according to Parkinson's law, soon all Indians will be judges and then there will be no injustice. That is not the way. No, Sir. Change the procedure. When a decision is given by a single judge, why are you appealing to the division bench, then to full bench? That is one thing to look at.

Secondly, compare the American System and our system. Why are the lawyers allowed to plead forever and ever? They will also repeatedly take dates. We have enough senior lawyers here from the S.C. They can go on arguing. And, it is a very expensive argument. Who is paying? Mangal Singh or Sangal Singh is paying if he ever gets to the S.C. But, actually, thank God, he never gets there. Change these systems. In America, the S.C. takes written arguments. Let there be discipline and hard work in lawyers offices. Submit written arguments to the court. And, then, you will get half-an-hour to orate in Court. That is all. I am saying this with great respect to everybody that you cannot stretch court arguments as you can stretch in Parliament.

श्री अबू आसिम आजमी: (उत्तर प्रदेश) वाइस चेयरमैन सर। ...(व्यवधान)...

شری ابوعاصم اعظمی : وائس چیئرمین سر،....مداخلت.....

एक माननीय सदस्य: इनकी पार्टी का कितना समय बचा है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: इनकी पार्टी का टाइम तो ऐक्सीड हो चुका है ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आजमी: सर, हंगामे में समय ज्यादा चला गया। ...(व्यवधान)...

شری ابوعاصم اعظمی: سر، ہنگامے میں سے زیادہ چلا گیا۔

श्री उपसभापति: उसमें हंगामा कुछ नहीं है, 35 मिनट का टाइम था, हंगामे के पांच मिनट और जोड़ दिये तो 40 मिनट का टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने बोलने में 50 मिनट का समय ले लिया। ...(व्यवधान)... आप दस मिनट बोल लीजिए।

श्री अबू आसिम आजमी: वाइस चेयरमैन सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे वक्त दिया, राष्ट्रपति महोदय की तकरीर पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का वक्त मिला इसके लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण की पूरी तैयारी केबिनेट करती है, राष्ट्रपति जी सिर्फ बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे मुल्क में किसान आये दिन खुदकुशी कर रहा हो, जब कर्जों की अदायगी नहीं होने पर गरीब किसान के खानदान तबाही के दहाने पर खड़े हों और जब गेहूं के दाम आसमान को छू रहे हों, जब प्याज के दाम 20-25 रुपये किलो हों और हुकूमत लाखों टन प्याज इम्पोर्ट करने पर मजबूर हो, जब रिटेल सैक्टर में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोलने से गांव-गांव और गली-गली की किराने की दुकानों का रोजगार खतरे में हो गया हो, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्राईवेट हाथों में देकर लाखों मुलाजमीन के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिये गये हों, ऐसे में महज आंकड़ों की बुनियाद पर ख्वामख्वाह वाहवाही बटोरना, मैं कहूंगा कि आप जैसे मुदब्बिर और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत के लिए दुरुस्त नहीं लगता।

वाइस चेयरमैन सर, आंकड़ों की अपनी जगह है, उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन आंकड़े इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं हैं। सदर-ए-मोहतरम ने अपनी खिताब में तस्वीर का एक ही रुख पेश किया है, जबकि दूसरा रुख इस सरकार के निकम्मेपन को जाहिर करता है। एक खोखली तरक्की या खोखली तरक्की का प्रोपोगंडा जिसके तहत गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। हर साल आखिर पूरे मुल्क में कर्जे के बोझ तले दबे हुए किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? जबकि फाइव स्टार होटल्स में, सेवन स्टार होटल्स में खुशियों के शादियाने बजाये जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार का सोशलिज्म एक दिखावा है, जिस राज में अमीर और ताकतवर तरक्की कर रहें हों, गरीब और कमजोर तबका परेशान होता आ रहा हो, वह भला शाबासी पाने और अपनी पीठ

†[]Transliteration of Urdu Script.

थपथपाने के काबिल कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस जिस तरह से राजपाट चला रही है उसके लिए तो मैं शायर की जुबान में एक शेर कहूंगा--

"जो है तिश्ना-लब, उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम, उन्हें दम-ब-दम।

ऐ साकिया तेरे मयकदे का यह तौर है कि मजाक है।"

सदर-ए-मोहतरम ने अपने सदारती खुतबे में इस बात का भी जिक्र किया है कि अगले साल हुकूमत-ए-हिन्द पहली जंग-ए-आजादी की 150वीं सालगिरह बड़े शानदार तरीके से मनाने की तैयारियां कर रही है। मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहूंगा कि अंग्रेज मुल्क में ताजिर बनकर आया था, हमारे हुक्मरानों की गलती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिन्दुस्तान में कम्पनी सरकार बन गई और इसी कम्पनी सरकार के खिलाफ 1857 में आम हिन्दुस्तानियों ने ऐलान-ए-जंग किया था जो हिन्दुस्तान की दौलत बेरूनी मुल्क में मुन्तकिल कर रही थी, आज एक बार फिर अंग्रेज अमेरिकन मल्टी नेशनल कंपनियों के जरिये मुल्क में आ चुके हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पब्लिक, प्राईवेट पार्टनरशिप की आड़ में एयरपोर्ट की नीलामी, फायदेमंद पब्लिक अंडरटेकिंग्स का प्राईवेटाइजेशन, रिटेल सैक्टर में एफडीआई ...(व्यवधान)... और दीगर मामलात यह साबित कर रहे हैं कि कंपनी सरकार के खिलाफ होने वाली हिन्दुस्तानी बगावत के 150 साल बाद आजाद हिन्दुस्तान की जम्हूरी हुकूमत मल्टी नेशनल सरकार बन चुकी है, जिसके राज में आम हिन्दुस्तानी शहरी से ज्यादा मल्टी नेशनल कंपनियां फल-फूल रही हैं। एक आम हिन्दुस्तानी शहरी के मुकाबले में मल्टी नेशनल कम्पनियों को हाथों - हाथ लिया जा रहा है। यही वजह है कि हमें जहां कम्पनी सरकार के खिलाफ पहले जंग-ए-आजादी का जश्न मनाना चाहिए, वहीं मल्टी नेशलन कम्पनी सरकार मजदूर दुश्मन, अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन और किसान दुश्मन के खिलाफ भी आवाज बुलन्द करनी चाहिए।

सर, ईस्ट इंडिया कम्पनी मुल्क में तिजारत के बहाने आई थी, लेकिन हिन्दुस्तानी हुकूमत को अपनी मनमानी पालिसियों पर अमल करने पर मजबूर करते-करते, वह यहां की हुक्मरान बन गई। कांग्रेस सरकार का भी मल्टी नेशनल कम्पनियों, गैर-मुल्की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और बड़े मुल्कों के दबाव के आगे झुककर अपनी पालिसियां बना रही है, इस तरह से देश को दुबारा गुलामी की तरह ले जाया जा रहा है। सर, यह बात हकीकत है कि अगर मरकज़ में आज यूपीए की सरकार आई है। तो इसमें गुजरात के दंगों से मुल्क में फैलने वाली नाराज़गी का सबसे बड़ा सबब है जिसके तहत सैक्युलरिज्म, सैक्युलर आवाम और खास तौर पर अक्लियतों, दलितों और मुसलमानों ने एनडीए के खिलाफ वोट दिया। कांग्रेस ने यूपीए का सहारा लेकर हुकूमत तो बना ली है, लेकिन कांग्रेस का ख्वाब, कि सेंटर में उसकी हुकूमत खुद अपनी ताकत पर आए, याद रखें, मुसलमानों और अक्लियत की मदद के बगैर यह ख्वाब कभी मुमकिन नहीं हो सकता है। इसलिए अक्लियतों को , खास तौर पर मुसलमानों को लुभाने के लिए ड्रामे किए जा रहे हैं, सिर्फ * बनाने की कोशिश की जा रही है। माज़ी में मुसलमानों को ऐसे खिलौनों से बहलाया गया, जिनसे

* Not recorded.

आज एक बार फिर कांग्रेस खेल रही है, ताकि मुसलमानों को फरेब देकर मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा किया जा सके। सर, सदर-ए-मोहतरम ने जस्टिस राजेन्द्र सच्चर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आजमी साहब, * शब्द अनपार्लियामेंटरी है, इसका इस्तेमाल मत कीजिए।

श्री अबू आसिम आजमी : सर, जो अनपार्लियामेंटरी है, उसे निकाल दीजिए।

श्री उपसभापति: आप लफ्जों को बरतने मे एहतियात बरतिए।

श्री अबू आसिम आजमी : मैं कोशिश करूंगा।

श्री उपसभापति: जो भी लफ्ज अनपार्लियामेंटरी है, वह निकाल दिया जाएगा ...(व्यवधान)... वह देखा जाएगा मगर*अनपार्लियामेंटरी है, अब आप इस्तेमाल मत करिए। ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आजमी : जो अनपार्लियामेंटरी है, उसे निकाल दीजिए।

श्री उपसभापति: लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो जरा एहतियात बरतिए।

श्री अबू आसिम आजमी : मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई गलत हो तो काट दीजिए प्लीज़। कहां जज्बात में ...(व्यवधान)... सदर-ए-मोहतरम, जस्टिस राजेन्द्र सच्चर की सदारत में अक्लियतों के तालीमी, समाजी और इक्तिसादी मामलात की तहकीक करने के लिए जो हाई लैवल कमेटी बनायी गयी है, यह कोई नयी बात नहीं है। यह कोई अनोखी और कोई बहुत ज्यादा लुभाने वाली बात नहीं है बल्कि साबेका रिकॉर्ड के मुताबिक मैं यह कह सकता हूं कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इस कमेटी का वही हश्र होगा, जो गोपाल सिंह माइनॉरिटी पैनल रिपोर्ट का हुआ था। अक्लियतों और मुसलमानों को रिझाने के लिए 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने डाक्टर गोपाल सिंह माइनॉरिटी पैनल कायम किया था और इस पैनल ने बड़ी मेहनत के साथ मुस्लमानों समेत मुल्क के तमाम मज़हबीअक्लियतों, समाजी, तालीमी और इक्तिसादी सूरते-हाल का रिसर्च करके जायजा लिया था और मैं तो यह कहूंगा कि वे सिफारिशात पेश की गयी थीं और उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई बावेला नहीं मचा था कि यह रिसर्च नही हो सकता लेकिन उसके बाद भी आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। सर, इसी तरह का खेल कांग्रेस आज नहीं, आजादी के बाद से खेलती चली आ रही है। कमेटियों और कमीशनों की सियासत से मुसलमानों और अक्लियतों को बहलाया जा रहा है। उर्दू हिन्दुस्तान की जबान है और हिन्दुस्तान मुश्तरका गंगा-जमुनी तहजीब की रवायत है लेकिन आजादी के बाद से हिन्दुस्तानी मुसलमानों ने उर्दू को गले लगा रखा है और एक तरह से हिन्दुस्तान में अक्लियतों की जुबान, माइनॉरिटी लेंग्अुएज होकर रह गयी है। इस जबान की तरक्की का ताल्लुक अक्लियती तबके, मुसलमानों की समाजी, तालीमी, इक्तिसादी तरक्की से है न कि मुसलमानों के मुसलसल मुतालबात के तहत कांग्रेस सरकार ने उर्दू जबान की तरक्की और फरोग के लिए आई.के.गुजराल कमेटी का

* Not recorded.

गठन किया था, तकरीबन चालीस साल पहले, और आई.के.गुजराल कमेटी ने उर्दू जबान के ताल्लुक से काफी तहकीक और मेहनत के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश की । आज तक उस रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं हुई। उसकी सारी रिपोर्टें धूल चाट रही हैं। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। नानावटी कमीशन दिल्ली में 1984 के दंगों के लिए बनाया गया था। वह रिपोर्ट आयी और जगदीश टाइटलर साहब का नाम उसमे था, उन्हें निकाल दिया गया। मैंने इस हाउस के अंदर देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे सिख भाइयों से माफी मांगी । मगर उसी के साथ कहना चाहता हूं कि मुम्बई के 1992-93 के दंगों की रिपोर्ट श्रीकृष्ण कमीशन रिपोर्ट भी आयी और उस रिपोर्ट के अंदर * नाम के एक मिनिस्टर का नाम है, लेकिन आज तक * के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, उन्हें नहीं निकाला गया। मुम्बई और दिल्ली में क्या फर्क है? क्योंकि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई थी और श्रीकृष्ण कमीशन पूरे का पूरा उस चीज़ को दिखा रही है लेकिन आज तक * के खिलाफ कुछ नहीं हुआ।

श्री उपसभापति: जो इस हाउस के मैंबर नहीं है, उसका नाम न लिया जाए। वह नाम निकाल दीजिए ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आज़मी : ठीक है, नहीं हैं। सोनिया गांधी का बार-बार नाम ले रहे हैं। ...(व्यवधान)... सदर-ए-मोहतरम, आपकी तवज्जह श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में वजीरे-आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम की तरफ भी मैं लाना चाहता हूं, Prime Minister's 15 Point Programme for Minorities. उसका इसलिए तज़करा करना चाहता हूं कि आपने अपने सदारती खुतबे में फरमाया है कि हुकुमत-ए-हिन्द अक्लियतों के लिए एक नया 15 नुकाती प्रोग्राम तैयार कर रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी के जमाने में अक्लियतों की फनाह-बहबूदी के नाम पर वज़ीर-ए-आज़म का जो 15 निकाती प्रोग्राम शुरू किया गया था आखिर उस पर क्या अमल हुआ? कुछ अमल नहीं हुआ? इस प्रोग्राम की क्या कार्यवाही देखी है? इससे अक्लियतों को कितना फायदा पहुंचा है। हमारी मालूमात के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम बराए अक्लियत को महज़ कागज़ी खानापूर्ति बना दिया, और 25 वर्षों में इस 15 निकाती प्रोग्राम के तहत मुस्लिम अक्लियत का न तो कोई भला हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने जरूर इसका propaganda करके मुस्लिम वोट हासिल कर लिए हैं। इसलिए मेरा मुतालिबा है कि वज़ीरे-आज़म के पंद्रह निकाती प्रोग्राम, माइनॉरिटीज़ का पच्चीस सालों में कार्यकरदीगी और अमल का जायज़ा पहले लिया जाए और उसके बाद कोई नया announcement किया जाए। पहले हुकूमत जवाब देगी। इंदिरा गांधी ने अक़ल्लियतों के फलाह बहबूदी के लिए पंद्रह निकाती वज़ीरे-आज़म का जो कार्यक्रम शुरू किया था, क्या वह कामयाब रहा? इस प्रोगाम से अकल्लियतों की खैर-ख्वाह फलां नहीं हुई, तो इसकी वजूहात क्या है? इस बिना पर पंद्रह निकाती प्रोग्राम पर हम यकीन नहीं कर सकते, सिर्फ कागजी बहलावे के लिए मुसलमानों को * बनाकर वोट बैंक लेना सरकार बंद कर दे। एक तरफ मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के डाटा का मसला आया, तो

* Expunged as ordered by the Chair..

बहुत लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अकल्लियतों की जो भी हाई लेवल कमेटियां या कमीशन बने, वे नुमाइशी कितने हैं और हुकूमत की नीयत इसके बारे में कितनी दुरुस्त है, यह सवाल माजी के तजुर्बे से लगाया जा सकता है। कांग्रेस सरकार ने जस्टिस सच्चर की सदारत में जो हाई लेवल कमेटी कायम की है, वह तकरीबन 11 राज्यों का दौरा कर चुकी है और मुसलमानों के ताल्लुक से सरकारी महकमों से भी डाटा हासिल करने में उसे दुश्वारियां हो रही हैं। जस्टिस सच्चर ने जब गुजरात का दौरा किया, तब उन्हें कितनी दिक्कत आई। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के सूरते-हाल, गुजरात के मुसलमान की इक्तिसादी, तालीमी सूरते-हाल और दीगर मामलात पर डाटा हासिल करने में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि गुजरात रियासत में तो ह्युमन राइट्स का भी कयाम नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जस्टिस सच्चर रिपोर्ट में हिन्दुस्तानी अफवाज में मुसलमानों के ताल्लुक से जो तनाजा पैदा हुआ है, यह एक बहुत ही अफसोस की बात है और इससे ज्यादा अफसोस की बात है कि पी.एम.ओ. ने इस तनाजे से अपना दामन झाड़ने की कोशिश की है। मैं आज बता दूं, जो लोग एक तरफ इस पर बहुत बावेला मचा रहे हैं, मेरे दाएं और बाएं तरफ, दोनो में कोई फर्क नहीं है। एक *बनाते हैं और एक जो हैं। ... (व्यवधान)...

श्री डेपसभापति: * शब्द फिर इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको निकाल दीजिए।

श्री अबू आसिम आजमी: अच्छा, गलत है, तो इसको निकाल दीजिए। ये सिर्फ Propaganda कर रहे है। और इंप्लिमेंटेशन नहीं हो रहा और एक तरफ के लोग जबरदस्ती अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनके खिलाफ जब कोई बात आती है, तो इस हाऊस में उसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। ...(व्यवधान)... मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि 1947 से अब तक किसी फौज का बड़ा कोई मुसलमान क्यों नहीं बना? सिर्फ एक बना और वह इद्रीश लतीफ, वह भी कांग्रेस की सरकार में नहीं ...(व्यवधान)... एक बार इद्रीश लतीफ बने, वह भी कांग्रेस की सरकार में नहीं मोरारजी देसाई की सरकार में बने आपके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं होता, सिवाय समाजवादी पार्टी के। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: तीनों फोर्सों का सर्वोपरि राष्ट्रपति होता है।

श्री अबू आसिम आजमी: आपका काम हो गया है ।...आपका काम हो गया है, आपने कह दिया है।

श्री उपसभापति: आपका वक्त भी हो गया है आजमी जी।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री अबू आसिम आजमी: मैं एक बात कहता हूं। अगर मैं कोई चीज ला रहा हूं इस हाऊस के अन्दर, तो बीस करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं।, मैं कहना चाहता हूं, राजू भाई सुन लीजिए आप-

''मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है,

तो दुश्मन क्यूं न हो, उससे मुहब्बत और बढ़ती है।''

समझे आप? आप जरा खुश होइए अगर मैं कोई चीज आपके सामने ला रहा हूं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कुहनी लगने से आप इतना चिल्ला रहे हैं और दीपांकर जी इतना बोले, तो उनको प्यार कर रहे हैं आप! कल ऐसा न हो कि हमारी भी जरूरत पड़ जाए आपको। दुश्मनी ऐसी कीजिए जो ठीक-ठीक रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज अकल्लियत के नाम पर जितना शोर-शराबा हो रहा है, आज इस मुल्क में, अभी हमारे साथी ने डाटा दिया, अभी जो रिपोर्ट आई है कि 14 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं, लेकिन नौकरियों में कितने हैं? डेढ़ परसेंट कहीं दो परसेंट और कह रहे हैं कि अगर मिलिटरी और डिफेंस में कहीं गिनती हो गई, तो ये तास्सुब इससे होगा। इसमें राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, मैं बोल चुका हूं इसके ऊपर, ये सारी चीजें हैं इसमें, फिर मुसलमानों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? बताइए। हम इस बात का यकीन करते हैं कि हमारे भाई मुसलमान थे, जो 1947 में इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। हमारे खून के लोग हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी इस मुल्क में जंग का बिगुल बजा है, तो उन्हीं मुसलमान भाइयों को मारने के लिए इन्हीं मुसलमानों ने हथियार उठाए हैं और उनके हाथ कांपते नहीं हैं। मैं आज डिमांड करना चाहता हूं कि मुसलमानों को भी इस मुल्क में आगे बढ़ने का चान्स दीजिए। साथियों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब भी हिन्दुस्तान की सरहदों पर बिगुल बजेगा, आज मुल्क में दो परसेंट मुसलमान अगर मिलिट्री में हैं, तो दस परसेंट मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी पेश की है। इंशाअल्लाह पचास परसेंट कुर्बानी पेश करेंगे और इस मुल्क का झंडा उठाकर ''इंकलाब जिन्दाबाद'' का नारा लगाते रहेंगे, लेकिन आज भी मुसलमानों के लिए कुछ होता है, वोट के चक्कर में जब बाहर निकलते हैं, तो गले मिलते हैं हमसे। अरे, भाई यह तो हम हाउस के अन्दर इसलिए सुना रहे थे कि थोड़ा छप जाए। आप यह सब बन्द कीजिए। आप इस बात को याद रखिए, 20 परसेंट मुसलमान, एक इंशान के बदन का पांचवा हिस्सा, अगर काट दोगे तो यह मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने ईरान के सामने हाथ जोड़ा तो में एक शेर कहूंगा, 'यह मेरे मुल्क का नक्शा नहीं ये कांशा है, यहां से जो गुजरता है, एक सिक्का डाल जाता है।'

श्री उपसभापति: आप शेर के साथ ही खत्म कीजिए।

श्री अबू आसिम आजमी: अमरीका के सामने हाथ जोड़ना बन्द किजिए इसने दुनिया में तबाही और बर्बादी कर दी है। अगर आपने अमरीका का साथ दिया तो आप उस अंजाम को भी सोच

लीजिए। इंशा अल्लाह ताला, आपको इसकी पूरी की पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। मैं इसी के साथ यह कहना चाहता हूं कि अक्लियत के लिए जो कार्यक्रम बने हैं, इसमें सिर्फ अन्य दिनों की तरह से ...(व्यवधान)...

प्रो. राम बख्शसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): अमरीका ने स्वागत क्यों किया है ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आजमी: अरे भाई, वह तो एक शख्स का किया है और वह भी वहां पर बिजनेस करने के लिए किया है। ...(व्यवधान)... उनसे डिसकशन हो रहा है, ...(व्यवधान)... लेकिन कोई दबाव नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अच्छा ठीक है।

श्री अबू आसिम आजमी: वह अमरीका जिसने अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, बगैर युएनओ की परमिशन के , वह अमरीका जिसने तमाम इराक को बर्बाद कर दिया। वह अमरीका आज ईरान की तरफ ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप तो समाप्त कर रहे थे?

श्री अबू आसिम आजमी: मैं कहता हूं कि अगर अब की बार यूपीए सरकार ने ईरान के खिलाफ वोटिंग की जो मुझे पूरी उम्मीद है कि वे जिनसे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, वे भी इंशा अल्लाह ताला आगे आएंगे और आपके सामने हश्र भी आएगा मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)... मैं खत्म करूंगा। मैं इसी के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में रहने वाले बीस करोड़ मुसलमानों के साथ नाइंशाफी नहीं होनी चाहिए, सदर-ए-मोहतरम, जो यूपीए, कांग्रेस का बनाय हुआ जो ऐजेंडा था, वह पढ़ दिया, लेकिन आप इनको बुलाइए ओर कहिए कि यह जो आपको सैक्युलर सरकार कहती है, इंसाफ करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।

†[شری ابو عاصم اعظمی ''اتر پردیش'' : وائس چیئرمین سر بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا
... مہودے کی تقریر پر، دھنیواد پرستاؤ پر مجھے بولنے کا وقت ملا اس کے لئے میں آپ کا شکرگزار ہوں۔
... مہودے کے ابھیبھاشن کی تیاری پوری کیبنیٹ کرتی ہے، راشٹرپتی جی صرف بولتے ہیں۔ میں کہنا
چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ملک میں کسان آئے دن خودکشی کر رہا ہو، جب قرضوں کی ادائیگی نہیں ہونے پر
غریب کسان کے خاندان تباہی کے دوراہے پر کھڑے ہوں اور جب گیہوں کے دام آسمان کو چھو رہے ہوں،
جب پیاز کے دام بیس، پچیس روپے کلو ہو اور حکومت لاکھوں ٹن پیاز امپورٹ کرنے پر مجبور ہو، جب ریٹیل سیکٹر

†[]Transiteration in Urdu Script.

میں ڈائریکٹ فارین انویسٹمینٹ کے لئے دروازہ کھولنے سے گاؤں گاؤں اور گلی گلی کے کرانے کی دوکانوں کا روزگار خطرے میں ہو گیا ہو، ہمارے انٹرنیشنل ائرپورٹ کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دیکر لاکھوں ملازمین کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دئے گئے ہوں، ایسے میں محض آنکڑوں کی بنیاد پر خواہ مخواہ ہی واہ واہی بٹورنا، میں کہوں گا کہ آپ جیسے مدبر اور معزز شخصیت کے لئے درست نہیں لگتا۔

وائس چیئرمین سر، آنکڑوں کی اپنی جگہ ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آنکڑے انسان کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ صدر محترم نے اپنے خطاب میں تصویر کا ایک ہی رخ پیش کیا ہے، جبکہ دوسرا رخ اس سرکار کے نکمے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک کھوکھلی ترقی یا کھوکھلی ترقی کا پروپیگنڈا، جس کے تحت غریب اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہر سال آخر پورے ملک میں قرضے کے تلے دبے ہوئے کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ فائیو اسٹار ہوٹلس میں، سیون اسٹار ہوٹلس میں خوشیوں کے شادیانہ بجائے جا رہے ہیں۔ کانگریس سرکار کا سوشلزم ایک دکھاوا ہے، جس راج میں امیر اور طاقتور ترقی کر رہے ہوں، غریب اور کمزور طبقہ پریشان ہوتا جا رہا ہو، وہ بھلا شاباشی پانے اور اپنی پیٹھ تھپتھپانے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کانگریس جس طرح سے راج پاٹ چلا رہی ہے اس کے لئے تو میں شاعر کی زبان میں ایک شعر کہوں گا ''جو ہے کسنہ لب انہیں کم سے کم، جنہیں پیاس کم، انہیں دم بہ دم، اے ساقی آ تیرے میکدے کا یہ دور ہے کہ مذاق ہے۔

صدر محترم نے اپنے صدارتی خطبے میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگلے سال حکومت ہند پہلی جنگ آزادی کی ۱۵۰ ویں سالگرہ بڑے شاندار طریقے سے منانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر یاد دلانا چاہوں گا کہ انگریز اس ملک میں تاجر بن کر آیا تھا ہمارے حکمرانوں کی غلطی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں کمپنی سرکار بن گئی اور اسی کمپنی سرکار کے خلاف ۱۸۵۷ میں عام ہندوستانیوں نے اعلان جنگ کیا تھا جو ہندوستان کی دولت کو باہری ملک میں منتقل کر رہی تھی، آج ایک بار پھر انگریز، امریکن ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے ملک میں آ چکے ہیں۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پبلک، پرائیوٹ پارٹنرشپ کی آڑ میں ائرپورٹ کی نیلامی، فائدہ مند پبلک انڈرٹیکنگس کا پرائیویٹائزیشن، رٹیل سیکٹر میں ایف.ڈی.آئی. .....مداخلت.....اور دیگر معاملات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کمپنی سرکار کے خلاف ہونے والی ہندوستانی بغاوت

کے ۱۵۰ سال بعد آزاد ہندوستان کی جمہوری حکومت ملٹی نیشنل سرکار بن چکی ہے، جس کے راج میں عام ہندوستانی، شہری سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پھل پھول رہی ہیں۔ ایک عام ہندوستانی شہری کے مقابلے میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جہاں کمپنی سرکار کے خلاف پہلی جنگ آزادی کا جشن منانا چاہئے، وہیں ملٹی نیشنل سرکار مزدور دشمن، عوام دشمن، غریب دشمن اور کسان دشمن کے خلاف بھی آواز بلند کرنی چاہئے۔

سر، ایسٹ انڈیا کمپنی ملک میں تجارت کے بہانے آئی تھی، لیکن ہندوستانی حکومت کو اپنی من مانی پالیسیوں پر عمل کرنے پر مجبور کرتے کرتے، وہ یہاں کی حکمراں بن گئی۔ کانگریس سرکار کا بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں، غیر ملکی انویسٹمینٹ، انویسٹرس، آئی.ایم.ایف.، ورلڈ بینک اور بڑے ملکوں کے دباؤ کے آگے جھک کر اپنی پالیسیاں بنا رہی ہے۔ اس طرح سے دیش کو دوبارہ غلامی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔

سر، یہ بات حقیقت ہے کہ اگر مرکز میں آج یو.پی.اے. سرکار آئی ہے تو اس میں گجرات کے دنگوں سے ملک میں پھیلنے والی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے جس کے تحت سیکولرزم، سیکولر عوام اور خاص طور پر اقلیتوں، دلتوں اور مسلمانوں نے این.ڈی.اے. کے خلاف ووٹ دیا۔ کانگریس نے یو.پی.اے. کا سہارا لیکر حکومت تو بنالی ہے، لیکن کانگریس کا خواب، کہ سینٹر میں اس کی حکومت خود اپنی طاقت پر آئے، یاد رکھیں، مسلمانوں اور اقلیت کی مدد کے بغیر یہ خواب کبھی ممکن نہیں ہوسکتا ہے۔ اس لئے اقلیتوں کو، خاص طور پر

مسلمانوں کو لبھانے کے لئے ڈرامے کئے جا رہے ہیں، صرف * بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماضی میں مسلمانوں کو ایسے کھلونوں سے بہلایا گیا، جن سے آج ایک بار پھر کانگریس کھیل رہی ہے، تاکہ مسلمانوں کو فریب دے کر مسلم ووٹ بینک پر قبضہ کیا جاسکے۔ سر، صدر محترم نے جسٹس راجندر سچر .....

شری اُپ سبھاپتی : اعظمی صاحب، * شبدا نپار لیمنٹری ہے، اس کا استعمال مت کیجئے۔

شری ابوعاصم اعظمی: سر، جو انپار لیمنٹری ہے، اسے نکال دیجئے۔

شری اُپ سبھاپتی : آپ لفظوں کو برتنے میں احتیاط برتئے۔

شری ابوعاصم اعظمی: میں کوشش کروں گا۔

شری اُپ سبھاپتی : جو بھی لفظ انپارلیمنٹری ہے، وہ نکال دیا جائے گا.....مداخلت.....وہ دیکھا جائے گا مگر * انپارلیمنٹری ہے، اب آپ استعمال مت کرئے.....مداخلت.....

شری ابوعاصم اعظمی: جو انپارلیمنٹری ہے، اسے نکال دیجئے۔

شری اُپ سبھاپتی : لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو ذرا احتیاط برتئے۔

شری ابوعاصم اعظمی: میں کوشش کر رہا ہوں، اگر کوئی غلط ہو تو کاٹ دیجئے پلیز۔ کہاں جذبات میں .....مداخلت.....صدرِ محترم، جسٹس راجندر سچر کی صدارت میں اقلیتوں کے تعلیمی، سماجی اور اقتصادی معاملات کی تحقیق کرنے کے لئے جو ہائی لیول کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی انوکھی اور کوئی بہت زیادہ لبھانے والی بات نہیں ہے بلکہ سابقہ ریکارڈ کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کے ذریعے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس کمیٹی کا وہی حشر ہوگا، جو گوپال سنگھ مائنارٹی پینل رپورٹ کا ہوا تھا۔ اقلیتوں اور مسلمانوں کو رجھانے کے لئے ۱۹۸۰ میں اندرا گاندھی کی سرکار نے ڈاکٹر گوپال سنگھ مائنارٹی پینل قائم کیا تھا اور اس پینل نے بڑی محنت کے ساتھ مسلمانوں سمیت ملک کی تمام مذہبی اقلیتوں، سماجی، تعلیمی اور

اقتصادی صورت حال کا ریسرچ کر کے جائزہ لیا تھا اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ سفارشات پیش کی گئی تھیں اور اس وقت کوئی دقت نہیں تھی، کہیں کوئی واویلہ نہیں مچا تھا کہ یہ ریسرچ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بعد بھی آج تک اس کمیٹی کی رپورٹ ردّی کی ٹوکری میں پڑی ہوئی ہے۔

سر، اسی طرح کا کھیل کانگریس آج سے نہیں، آزادی کے بعد سے کھیلتی چلی آ رہی ہے۔ کمیٹیوں اور کمیشنوں کی سیاست سے مسلمانوں اور اقلیتوں کو بہلایا جا رہا ہے۔ اردو ہندوستان کی زبان ہے اور ہندوستان مشترکہ گنگا۔جمنی تہذیب کی روایت ہے لیکن آزادی کے بعد سے ہندوستانی مسلمانوں نے اردو کو گلے لگا رکھا ہے اور ایک طرح سے ہندوستان میں اقلیتوں کی زبان، مائنارٹی لینگویج ہو کر رہ گئی ہے۔ اس

زبان کی ترقی کا تعلق اقلیتی طبقے، مسلمانوں کی سماجی، تعلیمی، اقتصادی ترقی سے ہے نہ کہ مسلمانوں کے مسلسل مطالبات کے تحت کانگریس سرکار نے اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لئے آئی۔کے۔گجرال کمیٹی کا گٹھن کیا تھا تقریباً چالیس سال پہلے، اور آئی۔کے۔گجرال کمیٹی نے اردو زبان کے تعلق سے کافی تحقیق اور محنت کے بعد سینٹرل گورنمنٹ کی رپورٹ پیش کی۔ آج تک اس رپورٹ پر کاروائی نہیں ہوئی۔ اس کی ساری رپورٹیں دھول چاٹ رہی ہیں۔

سر، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ ناناوتی کمیشن دہلی میں ۱۹۸۴ء کے دنگوں کے لئے بنایا گیا تھا۔ وہ رپورٹ آئی اور جگدیش ٹائٹلر صاحب کا نام اس میں تھا، انہیں نکال دیا گیا۔ میں نے اس ہاؤس کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ہمارے سکھ بھائیوں سے معافی مانگی۔ مگر اسی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ممبئی کے ۹۳۔۱۹۹۲ کے دنگوں کی رپورٹ شری کرشنا کمیشن رپورٹ بھی آئی اور اس رپورٹ کے اندر (*) نام کے ایک منسٹر کا نام ہے، لیکن آج تک (*) کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، انہیں نہیں نکالا گیا۔ ممبئی اور دہلی میں کیا فرق ہے؟ کیوں کہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اور شری کرشنا کمیشن پورے کا پورا اس چیز کو دکھا رہی ہے لیکن آج تک (*) کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔

شری اُپ سبھا پتی : جو اس ہاؤس کے ممبر نہیں ہے، ان کا نام نہ لیا جائے۔ وہ نام نکال دیجئے.....مداخلت.....

شری ابو عاصم اعظمی: ٹھیک ہے، نہیں ہیں۔ سونیا گاندھی کا بار بار نام لے رہے ہیں .....مداخلت..... صدرِ محترم، آپ کی توجہ شریمتی اندرا گاندھی کے زمانے میں وزیر اعظم کے ۱۵ نکاتی پروگرام کی طرف بھی میں لانا چاہتا ہوں۔ Prime Minister's 15 Point Programme for Minorities. اس کا اس لئے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا ہے کہ حکومت ہند اقلیتوں کے لئے ایک نیا ۱۵ نکاتی پروگرام تیار کر رہی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اندرا گاندھی کے زمانے میں اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے نام پر وزیر اعظم کا جو ۱۵ نکاتی پروگرام شروع کیا گیا تھا، آخر اس پر کیا عمل ہوا؟ کچھ عمل نہیں ہوا؟ اس

پروگرام کی کیا کاروائی دیکھی ہے؟ اس سے اقلیتوں کو کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق کانگریس حکومت نے وزیراعظم کے ۱۵ نکاتی پروگرام برائے اقلیت کو محض کاغذی خانہ پوری بنادیا، اور ۲۵ سالوں میں اس ۱۵ نکاتی پروگرام کے تحت مسلم اقلیت کا نہ تو کوئی بھلا ہوا ہے۔ لیکن کانگریس نے ضرور اس کا پروپیگنڈا کر کے مسلم ووٹ حاصل کر لئے ہیں۔ اس لئے میرا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم کے پندرہ نکاتی پروگرام، مائنارٹیز کا پچیس سالوں میں کارکردگی اور عمل کا جائزہ پہلے لیا جائے اور اس کے بعد کوئی نیا انا ؤنسمینٹ کیا جائے۔ پہلے حکومت جواب دے گی۔ اندرا گاندھی نے اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لئے پندرہ نکاتی وزیراعظم کا جو کارئے کرم شروع کیا تھا، کیا وہ کامیاب رہا؟ اس پروگرام سے اقلیتوں کی خیر خواہ فلاح نہیں ہوئی، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس بناء پر پندرہ نکاتی پروگرام پر ہم یقین نہیں کر سکتے، صرف کاغذی بہلاوے کے لئے مسلمانوں کو (*) بنا کر ووٹ بینک لینا سرکار بند کردے۔ ایک طرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ڈاٹا کا مسئلہ آیا، تو بہت لوگوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ اقلیتوں کی جو بھی ہائی لیول کمیٹیاں یا کمیشن بنے، وہ نمائشی کتنے ہیں اور حکومت کی نیت اس کے بارے میں کتنی درست ہے، یہ سوال

ماضی کے تجربے سے لگایا جا سکتا ہے۔ کانگریس سرکار نے جسٹس سچر کی صدارت میں جو ہائی لیول کمیٹی قائم کی ہے، وہ تقریباً گیارہ راجیوں کا دورہ کر چکی ہے اور مسلمانوں کے تعلق سے سرکاری محکموں سے بھی ڈاٹا حاصل کرنے میں اسے دشواریاں ہو رہی ہیں۔ جسٹس سچر نے جب گجرات کا دورہ کیا، تب انہیں کتنی دقت آئی۔ سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کے صورت حال، گجرات کے مسلمان کی اقتصادی، تعلیمی صورت حال اور دیگر معاملات پر ڈاٹا حاصل کرنے میں انہیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ گجرات ریاست میں تو ہیومن رائٹس کا بھی قیام نہیں ہے، اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس سچر رپورٹ میں ہندوستانی افواج میں مسلمانوں کے تعلق سے جو تنازع پیدا ہوا ہے، یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے اور اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ پی.ایم.او. نے اس سے اپنا دامن، اس تنازع سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کی۔ میں آج بتادوں، جو لوگ ایک طرف اس پر بہت واویلہ مچا رہے ہیں، میرے دائیں اور بائیں طرف، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک (*) بناتے ہیں اور ایک جو ہیں.....مداخلت.....

شری اُپ سبھاپتی : (٭) شبد پھر استعمال کر رہے ہیں؟ اس کو نکال دیجئے۔

شری ابوعاصم اعظمی: اچھا، غلط ہے، تو اس کو نکال دیجئے۔ یہ صرف پروپیگنڈہ کر رہے ہیں اور اپیلی میٹیشن نہیں ہو رہا ہے اور ایک طرف کے لوگ زبردستی اپنا ووٹ بینک بنانے کے لئے ان کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے، تو اس ہاؤس میں اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں......مداخلت......میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ۱۹۴۷ء سے اب تک کسی فوج کا بڑا کوئی مسلمان کیوں نہیں بنا؟ صرف ایک بنا اور وہ ادریس لطیف، وہ بھی کانگریس کی سرکار میں نہیں......مداخلت......ایک بار ادریس لطیف بنے، وہ بھی کانگریس کی سرکار میں، مرارجی ڈیسائی کی سرکار میں بنے۔ آپ کے پاس تو کوئی مدعا ہی نہیں ہوتا، سوائے سماج وادی پارٹی کے۔ ......مداخلت......

شری راجیو شکلا: تین فورسوں کا سروپریئے راشٹرپتی ہوتا ہے۔

شری ابوعاصم اعظمی : آپ کا کام ہو گیا ہے۔ ...آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے۔

شری اُپ سبھاپتی : آپ کا وقت بھی ہو گیا ہے اعظمی جی۔

شری ابوعاصم اعظمی : میں ایک بات کہتا ہوں۔ اگر میں کوئی چیز لا رہا ہوں اس ہاؤس کے اندر، تو بیس کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، راجو بھائی سن لیجئے آپ۔

میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے
تو دشمن کیوں نہ ہو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے

سمجھے آپ؟ آپ ذرا خوش ہوئے اگر میں کوئی چیز آپ کے سامنے لا رہا ہوں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری کہنی لگنے سے آپ اتنا چلا رہے ہیں اور دیا نگر جی اتنا بولے، تو ان کو پیار کر رہے ہیں آپ۔ کل ایسا نہ؟

کہ ہماری بھی ضرورت پڑ جائے آپ کو۔ دشمنی ایسی کیجئے جو ٹھیک ٹھیک رہے۔ اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اقلیت کے نام پر جتنا شور شرابہ ہو رہا ہے، آج اس ملک میں، ابھی ہمارے ساتھی نے ڈاٹا دیا، ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ ۱۴ کروڑ مسلمان اس دیش میں ہیں، لیکن نوکریوں میں کتنے ہیں؟ ڈیڑھ فیصد، کہیں دو فیصد اور کہیں بھی ہیں کہ اگر ملٹری اور ڈیفینس میں کہیں گنتی ہوگئی، تو یہ تعصب اس سے ہوگا۔ اس میں راجپوت ریجیمنٹ ہے، سکھ ریجیمنٹ ہے، میں بول چکا ہوں اس کے اوپر، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ بتائیے۔ ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی مسلمان تھے، جو ۱۹۴۷ء میں اس ملک کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔ ہمارے خون کے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھئے۔ جب بھی اس ملک میں جنگ کا بگل بجا ہے، تو انہی مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لئے انہیں مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور ان کے ہاتھ کانپے نہیں ہیں۔ میں آج دیوان کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی اس ملک میں آگے بڑھنے کا چانس دیجئے۔ ساتھیوں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جب بھی ہندوستان کی سرحدوں پر بگل بجے گا، آج ملک میں دو فیصد مسلمان اگر ملٹری میں ہیں، تو دس فیصد مسلمانوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ انشاءاللہ پچاس فیصد قربانی پیش کریں گے اور اس ملک کا جھنڈا اٹھا کر "انقلاب زندہ باد" کا لگاتے رہیں گے، لیکن آج بھی مسلمانوں کے لئے جب کچھ ہوتا ہے، ووٹ بینک کے چکر میں جب باہر نکلتے ہیں، تو گلے ملتے ہم ہے۔ ارے بھائی یہ تو ہم ہاؤس کے اندر اسی لئے سنا رہے تھے کہ تھوڑا چھپ جائے۔ آپ یہ سب بند کیجئے۔ آپ یہ بات کو یاد رکھئے، بیس فیصد مسلمان، ایک انسان کے بدن کا پانچواں حصہ، اگر کاٹ دو گے تو یہ ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کریں گے، لیکن اگر آپ نے ایران کے سامنے ہاتھ جوڑا تو میں ایک شعر کہوں گا ـ

یہ میرے ملک کا نقشہ نہیں کشکول کا نقشہ ہے
یہاں سے جو گزرتا ہے، ایک سکہ ڈال جاتا ہے

شری اُپ سبھاپتی : آپ شعر کے ساتھ ہی ختم کیجئے۔

شری ابوعاصم اعظمی: امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا بند کیجئے۔ اس نے دنیا میں تباہی اور بربادی کر دی ہے۔ اگر آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا تو آپ اس انجام کو بھی سوچ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو اس کی پوری کی پوری بھرپائی کرنی پڑے گی۔ میں اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقلیت کے لئے جو کاریہ کرم بنے ہیں، اس میں صرف دیگر دنوں کی طرح سے......مداخلت......

پروفیسر رام بخش ورما : ۔امریکہ نے سواگت کیوں کیا ہے۔.....مداخلت.....

شری ابو عاصم اعظمی : ارے بھائی، وہ تو ایک شخص کا کیا ہے اور وہ بھی وہاں پر بزنس کرنے کے لئے کیا ہے .....مداخلت.....ان سے ڈسکشن ہو رہا ہے.....مداخلت.....لیکن کوئی دباؤ نہیں ہے.....مداخلت.....

شری سبھاپتی : اچھا ٹھیک ہے۔

شری ابو عاصم اعظمی : وہ امریکہ جس نے افغانستان کو تمام برباد کر دیا بغیر یو.این.او. کی پرمیشن کے، وہ امریکہ جس نے تمام عراق کو برباد کر دیا۔ وہ امریکہ آج ایران کے طرف.....مداخلت.....

شری سبھاپتی : آپ تو سماپت کر رہے تھے؟

شری ابو عاصم اعظمی : میں کہتا ہوں کہ اگر اب کی بار یو. پی. اے سرکار نے ایران کے خلاف ووٹنگ کی تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ جن سے بہت محبت کر رہے ہیں وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ آگے آئیں گے اور آپ کے سامنے حشر بھی آئے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں.....مداخلت.....میں ختم کروں گا۔ میں اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والے بیس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہئے، صدرِ محترم، یو. پی. اے. جو کانگریس کا بنایا ہوا جو ایجنڈا تھا، وہ پڑھ دیا، لیکن آپ ان کو بلایئے اور کہئے کہ یہ جو اپنے آپ کو سیکولر سرکار کہتی ہے، انصاف کرنا چاہئے۔ آپ نے مجھے بولنے کا وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔

''ختم شد''

श्री नंदी येल्लैया: उपसभापति महोदय, मोशन ऑफ थैंक्स पर अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने प्वाइंट्स और परसेंटेज के बहुत से आंकड़े सदन में दिए हैं। मैं उन तमाम बातों पर नहीं जाता हूं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके बीस सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में जिक्र किया है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी का भारत की प्रधानमंत्री की हैसियत से जो शासन काल रहा है, उसमें उन्होंने भारत के गरीबों और दलितों के आर्थिक ढांचे को देखकर 'गरीबी हटाओ' का एक नारा दिया था। जिसकी वजह से गांव के रूरल एरिया में रहने वाले लोगों ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप इनकी ओर क्यों देख रहे हैं? आप, आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

श्री नंदी येल्लैया: ठीक है, मैं उनकी तरफ नहीं देखना चाहता हूं। मैं सीधे आपको देखना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री की हैसियत से जो देश के लोगों में गुरबत थी, दलितों के अंदर जागृति नहीं थी, वह उन्होंने उन लोगों में पैदा की। मैं अपने प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश का एक तजुर्बे से बयान कर रहा हूं। उस वक्त गांव में रहने वाले जो लोग थे, वे कहते थे, अगर इस गांव के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ हुआ है तो जो हमारी मां हस्तिनापुर के अंदर बैठी है, उनकी वजह से हुआ है। जो हमारे लिए देखभाल करती हैं, वे श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। गरीब लोगों में उनके प्रति एक तरह से कांफिडेंस और विश्वास था। मैं समझता हूं कि उस समय में, दलितों और माइनोरिटी के लोगों ने काफी प्रगति की, मैं यही निवदेन कर रहा हूं। उसके बाद UPA सरकार

बनने के बाद पहली बार हमारी Chairperson श्रीमती सोनिया गांधी और भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने एक ऐसा इम्प्लॉयमेंट गारंटी का प्रोग्राम दिया, मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा इम्प्लॉयमेंट गारंटी का प्रोग्राम नहीं था। आज National Rural Employment Guarantee Act के तहत एक स्कीम लाई गई है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है।

उपसभापति जी, आज हमारे गांवों के अंदर पानी का काम, सड़क का काम और कई दूसरे कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए मैं सोनिया गांधी, जो हमारी Chairperson हैं और हमारे प्रधानमंत्री, श्री मनमोहन सिंह को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इसके अलावा पहली बार हमारे आंध्र प्रदेश में इस स्कीम का उद्घाटन 11 जिलों में किया गया है हमारी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में आज़ादी के बाद जितनी तामीर इन प्रोग्रामों की होनी चाहिए थी, जितना constructive programme होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। हमारे rural areas में, remote areas में, जो लोग रहते हैं, आज भी केन्द्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से उनको इन कार्यक्रमों का जो लाभ पहुंचना चाहिए, वह लाभ उन तक नहीं पहुंचा है। इस Rural Employment Guarantee Programme के माध्यम से उनको विश्वास हो गया है कि अगर उनको काम नहीं भी मिलता है, तब भी उनको उस दिन की पूरी मजदूरी मिलेगी।

उपसभापति जी, हर स्टेट में rainfall में कुछ कमी आई है। इसकी वजह से लोग शहरों में जाते हैं, कुछ लोग मुंबई जाते हैं। दूसरे शहरों में जाने से उनकी माली हालत खस्ता हो जाती है और उनकी फैमिली की बरबादी होती है। इस Rural Employment Guarantee Programme की वजह से उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और राज्य सरकार या भारत सरकार की तरफ से उनको रोजगार की गारंटी देने का विश्वास दिया गया है।

उपसभापति जी, हमारे दलितों के बीच जो depressed classes league है, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, आज भी उनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, उनको खेती के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और सिंचाई के लिए भी उनके पास साधन नहीं हैं। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के माध्यम से ये तमाम facilities उन लोगों को देना, यह सरकार का कर्तव्य है। मैं समझता हूं कि UPA गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी मकान बनाने का, सड़कें बनाने का, टेलीफोन पहुंचाने का काम हो रहा है, इससे वहां के गांवों की काफी तरक्की होगी।

उपसभापति जी, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज भी हमारे देश के अंदर बहुत से लोगों के पास शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। हरेक आदमी बाबा साहब अम्बेडकर तो नहीं बन सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। उस ज़माने में untouchability की बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने काफी संघर्ष किया। उनकी काफी insult की गई। अगर बड़ौदा के महाराज की scholarship उनको नहीं मिली होती, तो आज भारत के

संविधान का ढांचा कौन तैयार करता, संविधान सभा का चेयरमैन कौन होता, यह हमें मालूम नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान व्यक्ति थे और आज भी वे भारत की शान हैं। आज गांवों के अंदर आप देखिए कि एजुकेशन इतनी costly हो गई है कि हरेक आदमी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है । अब मैं हरिजनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज दलितो को 8th क्लास, 9th क्लास पढ़ने के बाद कहीं कभी म्युनिसिपैलिटी में या कभी बेकार काम में लगा दिया जाता है। वे मैट्रिक तक भी नहीं जाते। इसमें उन्हें काफी आर्थिक प्रॉब्लम है यानी फाइनांशियल प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से कहूँगा कि दलितों के लिए शिक्षा कंपलसरी हो, क्योंकि आज शिक्षा के बगैर इस डेमोक्रेसी के अन्दर, इस प्रजातंत्र के अन्दर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मिड-डे मिल में, जहाँ पढ़ाई करने के लिए उनको एक टाइम खाना खिलाने का प्रावधान है। इसकी वजह से बहुत से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर मिला है। शिक्षा किसी की मोनोपॅली नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। डेमोक्रेसी के अन्दर हरेक आदमी, हरेक बच्चे, चाहे वह दलित हो, चाहे ओबीसी हो या माइनोरिटी हो, इसमें हरेक आदमी को शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है और अधिकार भी है।

इसके अलावा एक्स-सर्विसमेन के लिए जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके लिए एक नया प्रावधान किया गया है। आज हमारे एक्स-सर्विसमेन के रिटायर होने के बाद उनकी माली हालत बहुत बुरी होती है। हमारे एक्स-सर्विसमेन, हमारे फौजी लोग, जब कभी देश के अन्दर कुछ संघर्ष हुआ तो वे लोग सामने रह कर बलिदान देते हैं। इसलिए ऐसे एक्स-सर्विसमेन के लिए भी हमारे यूपीए गवर्नमेंट ने एक फंड खोला है। उन तमाम लोगों को इसमें काफी सहूलियतें हैं। इसमें काफी परिवर्तन किया गया है। उनके डेवलपमेंट करने के लिये इसमें तमाम उपाय हैं। इनका पेंशन भी इंक्रीज किया गया है। उन लोगों के लिए यह अपना कर्त्तव्य है, फर्ज ही सब कुछ है देश के लिए वे लोग बलिदान देते हैं। कभी हमारे बॉर्डर के अन्दर, कभी हमारे देश के अन्दर कोई आक्रमण हुआ, तो वही लोग सामने रह कर फाइट करते हैं। उपसभापति महोदय, इसलिए मैं आज इस सदन में कहूँगा कि हमारी भारत सरकार, हमारी यूपीए गवर्नमेंट, हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, डा॰ मनमोहन सिंह जी, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम लाये हैं। गरीबों का, दलितों का, माइनोरिटीज का, पूरे लोगों का इसमें जो ख्याल रखा गया है, इससे उनकी हालत में काफी परिवर्तन और सुधार होगा। इतना कहते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

SHRI LEKHRAJ BACHANI (Gujarat): Deputy Chairman, Sir, I am thankful to your honour for giving me the opportunity to express my views.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should confine to whatever time you have requested for.

श्री लेखराज बचानी: राष्ट्रपति जी का जो भाषण है, सरकार की जो नीतियाँ हैं ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have asked for 3-4 minutes; you are given this time.

SHRI LEKHRAJ BACHANI: I will take only three to four minutes; there are three points only.

47 पैरा में सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड बढ़ाने की बात है, अपनी सरकार ट्रेड बढ़ाना चाहती है, लेकिन in the first week of this February, इंडिया के एक प्रेसमैन ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ जी से एक प्रश्न पूछा कि ट्रेड और बिज़नेस बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? उसने जवाब में दिया है कि We cannot increase our trade and business with India our enemy country. General Musharraf has said this in the first week of this month, and, I have the cutting of the paper.

I would also like to submit that on 10th of June last, I was in Karachi, and, the Chief Minister of Sindh — his father was my friend — took me to the residence of Governor. Nine Indians who belonged to Hurriyat were there. I heard their speeches, उन्होंने भारत के खिलाफ और सेपरेटिज्म के लिए जो भाषण किया है, मैंने वापस आने के बाद ज्वाइंट सेक्रटरी को यह सब बताया। हुर्रियत के नेताओं को एनडीए सरकार ने कभी पाकिस्तान जाने के लिए परमिशन नहीं दी थी। वे अलग-अलग प्रान्तों में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में जाकर ऐसा वातावरण हिन्दुस्तान के खिलाफ बना रहे हैं। सर, यह जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, यह हिन्दुस्तान से नफरत के आधार पर चल रही है। हाँ, यह बात सही है कि वहाँ के लोगों और भारत के लोगों के बीच में कोई नफरत नहीं है।

People-to-people अच्छे कंटैक्ट हैं और I was born there. Recently, जो थार एक्सप्रेस चालू हुई है, I belong to that district and the Chief Minister also belongs to the same village. सर, इंसिडेंटली यह बात मैंने खुद सुनी, जो आपके आगे कह रहा हूं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हम रिलेशन सुधारने जा रहे हैं, लेकिन मैंने जो दो बातें कही हैं, उन्हें आप ध्यान में रखिए। अगर इस महीने में जनरल मुशर्रफ यह कहें कि India being an enemy country, we cannot increase our trade and business with them. What is this? We are doing our best to improve our relations with them. Hence our Govt. must go coutiously.

My second point is that there are so many paragraphs in this address regarding social reforms, social development and economic growth. लेकिन मैं इस हाऊस में स्पष्ट शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं। मैंने देखा है कि जितनी भी पंचवर्षीय

योजनाएं पूरी हुई हैं, उनमें से किसी भी योजना में कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ है। उसके क्या कारण हैं? उसका एक ही कारण है-पोपुलेशन की स्पीडिक ग्रोथ पोपुलेशन जिस अंक से बढ़ रही है और पोपुलेशन का जो विस्फोट हो रहा है, अगर सरकार इसको कंट्रोल नहीं करेगी और रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स नहीं लेगी, तो कोई भी प्लानिंग, कोई भी रिफॉर्म, कोई भी योजना हम कितनी भी करें और जिसके लिए करें, वही sectors में पोपुलेशन बढ़ता जाता है। मैं एक बार चाइना गया था and I studied minutely this subject चायना ने 1980 के बाद पोपुलेशन पर कंट्रोल के लिए मेजर्स लिए हैं। वहाँ पोपुलेशन में कभी जीरो परसेंट तो कभी एक परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है। यहां हिन्दुस्तान में अगर 1991 के फीगर देखें ओर 2001 के फीगर देखें, तो इसमें एक अलार्मिंग इंक्रीज़ है। यहां अलग-अलग सैक्शंस में, अलग-अलग सम्प्रदायों में और अलग-अलग स्ट्रेट्स में पोपुलेशनइस तरह बढ़ रहा है, जिससे बहुत imbalances हो रहे हैं। इससे देश में एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। मैं सरकार को इस संबंध में एक वार्निंग देना चाहता हूं। आपकी स्कीम्स, जो सोशल डेवलपमेंट के लिए हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हैं, वे तभी सक्सेसफुल हो सकेंगी, जब आप ...(समय की घंटी)... पोपुलेशन पर इफ्रेक्टिव कंट्रोल करेंगे। इन 3-4 वर्षों में मैंने देखा है कि प्राइवेट मैम्बर्स बिल्स बार-बार आए हुए हैं, लेकिन उन पर कोई चर्चा सक्सेसफुल नहीं हुई है और गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया है। इसलिए मैंने आपके सामने चाइना का एग्जाम्पल रखा है।

माननीय उपसभापति जी, तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, आपका वक्त हो गया है। ...(व्यवधान)...

श्री लेखराज बचानी: महोदय, एक लास्ट बात है। मैं आज इस आगॅस्ट हाऊस के सामने एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। I am not an astrologer. लेकिन मेरे मन में एक प्रिडिक्शन है, एक फीयर है। इस देश में जिस प्रभाव से और जिस वातावरण में अलग-अलग सेक्टर्स के बीच जो वातावरण उत्पन्न हो रहा है, वह उग्र हो रहा हे और जो पिक्चर्स हम टी॰वी॰ पर देख रहे हैं और जो बातें हो रही हैं और जिस हिसाब से स्पलिट की बातों का जिक्र हो रहा है, उस हिसाब से वह दिन दूर नहीं है, जब 50 वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान में कभी भी एक सेपरेट मिनी पाकिस्तान की डिमांड होगी अथवा नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में सेपरेट इंग्लिस्तान की डिमांड होगी। पाकिस्तान की डिमांड 1947 में नहीं हुई, वह बात 1932 से चलती आई, चलती आई ...(समय की घंटी)... और उसका परिणाम अगस्त, 1947 में आया। इसलिए मेरी एक नम्र विनती है कि आज असमें एक माननीय सदस्य श्री कर्णेन्दु जी ने जो कहा कि इंडिया एक है, we all Indians are one. हम क्यों अलग-अलग बातें करते हैं? हम माइनॉरिटीज़ के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन एक बात है कि जो कुछ करना हो, वह शुरुआत से करें। एलिमेंटरी और सेकेण्डरी एजुकेशन के लिए सरकार को जितना भी खर्च करना हो, तो आप माइनॉरिटीज को, शैडयुल्ड कास्ट, शेडयुल्ड ट्राइब और

ओ॰बी॰सी॰ को आगे लाएं। लेकिन, आगे आने के बाद जब मैरिट का सवाल आता है ...(व्यवधान)... तो सावधानी दिखानी चाहिए।

श्री उपसभापति: आपका समय समाप्त हो गया। ...(व्यवधान)...

श्री लेखराज वचानी: यह स्टॉप होना चाहिए। ...(समय की घंटी)... अगर यह मैरिट नहीं देखेंगे, तो अपना जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वह खतरे में रहेगा। ...(व्यवधान)... इसीलिए मैं कोई धर्म, कोई सम्प्रदाय या कोई सेक्टर की बात नहीं करता हूं। मैं केवल यह चेलेन्ज दे रहा हूं कि इस देश में कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं आनी चाहिए कि यहां एक मिनी पाकिस्तान हो अथवा कोई मिनी इंग्लिस्तान हो। ...(व्यवधान)... सर, मैं यह इसलिए कह रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: लेखराज जी, समाप्त करें अभी दो-तीन मैम्बर और रह गए हैं।

श्री लेखराज वचानी: सर, इस हाऊस में जो बात हो रही है, अगले 40-50 वर्षों में क्या होने वाला है? एक बात जो हम देख रहे हैं, वह बात हम इसलिए करते हैं, मैं कोई एस्ट्रोलोजर नहीं हूं।

श्री उपसभापति: आप समाप्त कीजिए।

श्री लेखराज वचानी: लेकिन, जो वातावरण पैदा हो रहा है, जो वोट बैंक से देख रहे हैं, वह यह कि इस देश मे कुछ खतरा है और वह खतरा मैं आपके समक्ष आज रिकॉर्ड में ला रहा हूं। अब अगले 30-40 वर्षों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वह तो आने वाली पीढ़ी देखेगीं administration में corruption बढ़ता जा रहा है। Effective measure लेना चाहिए।

श्री उपसभापति: श्रीमती वंगा गीता। आपका समय तीन मिनट है। ...(व्यवधान)... नहीं, आपका हो गया। मैंने उनको बुला लिया है ...(व्यवधान)

श्री लेखराज वचानी: सर, लासस्टली, आनली लास्ट पाइंट। इस देश के इंटीग्रेशन के बारे में राष्ट्रपति जी ने अपने इस अभिभाषण के पैरा में लिखा है। नेशनल यूनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इस बारे में हमें इससे ज्यादा चिंता करनी चाहिए और ऐसी चिंता करनी चाहिए कि हिंदुस्तान की इंटीग्रेशन, हिंदुस्तान की मजबूती, हिंदुस्तान की नेशनलिज्म और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस दुनिया के सामने इतनी आनी चाहिए, जैसे सब कहते हैं कि इक्कीसवीं सदी जो है, वह भारत की है। तो यह जो इक्कीसवीं सदी भारत की है, वह बात हमें साबित करनी चाहिए।

महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं, जो आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। (समाप्त)।

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for having given me this opportunity to speak. I want to say a few words regarding Women's Reservation Bill. His Excellency the hon. President has stated

in his Address that the Women's Reservation Bill will be passed in the near future. I would like to request the Government to come with a specific time-bound programme for the passage of this very, very important Bill. Sir, most surprisingly, every political party is supporting this Bill. All political parties are extending their support to this Bill. But I want to know where is the gap, who is objecting, and who is opposing and who is against this Bill. Sir, why is this delay? Every political party is saying that it is supporting this Bill. But this Bill is not getting passed. Sir, why all these eyewash statements? Let the nation known when the Bill will be passed. Sir, I request the hon. Prime Minister, who is sitting here, to discuss and pass the Bill in the near future. It is long pending. For the last ten years, we have been hearing the same statements that this Bill will be passed in the near future. But nothing has changed Sir, where there is a will, there is a way, "जहां चाह, वहां राह"। मनमोहन जी, कृपया आप जरुर अपने मन की गहराई से सोचिए और महिला आरक्षण के बिल को लाइए। धन्यवाद, सर।

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Sir, after greeting in the first paragraph, the Address proudly says, "The optimism is visible in the savings rate which is now over 29%". Sir, this is not an issue on which the Government can pat itself on its back. In fact, when you say that you are having more savings, it shows the incompetence of various Departments or Ministries and ineffectiveness of the Government of the day. When you say savings, they are not really the savings made by the people. In fact, it is the unspent money allocated to various Departments returned to the Government due to their failure and lacklustre implementation of schemes of the Government.

The Government says that it wishes to set up Biotechnology Regulatory Authority. When the GM crops, particularly cotton, have failed utterly in the country, what is the point in having another agency to oversee the whole thing? Is not the Genetic Engineering Approval Committee sufficient to look after all these things? Moreover, when Bt. Cotton has utterly failed in the country what is the reason behind GEAC approving 18 more new hybrids of Bt. Cotton for planting in India? When thousands of farmers have committed suicides, what are the reasons for introducing more and more varieties? I fail to understand the rationale behind this. Multinational companies like Monsanto, Maheyco, etc. are squeezing the blood of farmers. I only request you to save our poor farmers.

Sir, I have an important point to make on the Right to Information Act. The idea behind this legislation is to share information with the people. But, when it comes to implementation, we are back to square one. Bureaucrats don't want to disclose the notings on the files. Why? The paramilitary forces have been kept out of the purview of this Act. Why? Why they want to go out of the purview of this Act is, their omissions and commission come to light if they all are covered under this Act. So, I would only say that except classified documents, all other information should be made available when any person makes such a request. Thank you, Sir.

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): शुक्रिया, सदरे मोहतरम। मैं खुतबा-ए-सदारत पर, उसके फेवर में कुछ अपने महसूसात पेश करने के लिए हाऊस में खड़ा हुआ हूं।

सर, खुतबा-ए-सदारत का असल मतलब यह होता है कि साल भर तक हुकूमत ने कौन-कौन से इकदामात मुल्क को मफाद में और मुल्क के आवाम के मफाद में किए हैं, उन पर प्रेजिडेंट आफ इंडिया के ज़रिए रोशनी डाली जाए-मौजूदा सूरत-ए-हाल में हुकूमत फ्यूचर के लिए क्या-क्या इरादे रखती है और हुकूमत अपनी नेक ख्वाहिशात मुल्क की तरक्की और मुल्क के आवाम के लिए मुंसिफाना तौर पर किस तरह पहुंचाना चाहती है, उसका इज़हार किया जाए। हम खुतबा-ए-सदारत को जब पढ़ते हैं जो यह महसूस होता है कि जिंदगी के हर शोबे में पूरी-पूरी कोशिश इस बात की हुकूमत की तरफ से की गई है कि जिंदगी का हर वह नक्शा, जिसमें रंग भरने की जरुरत है, उसमें ईमानदारी से रंग भरा

(श्री सभापति महोदय पीठासीन हुए)

जाए, जहां-जहां इस्तेहसाल हो रहा है, जिन-जिन शोबों में खामियां हैं, उन खामियों को नेकनीयती के साथ खत्म किया जाए। नतीजें में हमने देखा है कि उसी का एक हिस्सा खुतबा-ए-सदारत में कौमी यकजहती भी है। कौमी यकजहती की बात मैंने पहले इसलिए ली है कि यह मुल्क हमेशा-हमेशा अपनी खायतों के साथ तारीख की राशनी में कौमी यकजहती का सबसे बड़ा अलम्बरदार बनकर खड़ा रहा है। हमारे इस मुल्क में दंगे-फसाद और तरह-तरह से जात के नाम पर, मज़हब के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों के जज्बात से खेलकर इंसानों का कुश्त-व-खून हुआ है, यह भी हमारे लिए एक बहुत दर्दनाक तारीख आजाद भारत की सैकुलर गवर्नमेंट के रहते हुए बन गई है, जिस पर मैं समझता हूं कि जो लोग भी कौमी यकजहती पर यकीन रखते हैं, उनका सर शर्मिंदगी से झुक जाता है और हर हुकूमत की यह जिम्मेदाराना पालिसी होनी चाहिए कि वह हुकूमत कौमी यकजहती को मामले में मकुम्मल तौर पर चौकस और बेदार रहे और किसी भी तरह से कौमी यकजहती को, कौमी एकता को तबाह-ओ-बर्बाद होने से हर

हाल में बचाए। हमारी हुकूमत ने इस सिलसिले मे जो नए कदम उठाए हैं, वे यकीनन काबिल-ए-तारीफ हैं औद इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो कुछ अपने इरादे जाहिर किए हैं, खुदा करे, इन इरादों का ख्याब शर्मिंदा-ए-ताबीर हो, इसलिए कि हम इस मुल्क में दो खुसूसी कौमी का जिक्र करना चाहेंगे-एक कौम, जिसे हिन्दू कौम के नाम से लोग जानते हैं। जब कौमियत के बड़े तनाजुर में हम इन दोनों को देखते हैं तो कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक हिन्दू भी हिन्दुस्तानी है और मुसलमान भी हिन्दुस्तानी हैं।

यह हिन्दुस्तानी कौम, जिसे हिन्दू और मुसलमान के नाम पर बार-बार बांटने की कोशिशें की गई, मैं किसी पर भी कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, इस सच्चाई को इधर के लोग भी मानते हैं और उधर के लोग भी मानते हैं, मगर हम अपने देश की यकजहती की ताक़त को उस वक्त समझ सकते हैं जब हम गुलाम भारत को अपनी नज़र के सामने रखें। डेढ़ सौ साल तक हमारे मुल्क पर गुलामी के काले बादल छाए रहे, नफरतों की बदलियां घिरती रहीं और वहशतों का पानी बरसता रहा। जलियां वाला बाग़ में हिन्दुस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहा, हिन्दुस्तानी स्वतन्त्रता सैनानियों का वतन-ए-अज़ीज़ की हिफाज़त के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ीं, वह जग ज़ाहिर है। हमारा सिर उस वक्त फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है, जब हम इतिहास की रौशनी में इस मुल्क़ के हिन्दु, मुस्लिम और सिक्खों की माओं की कोख़ उजड़ती हुई देखते हैं, आजाद भारत की कोख़ बसाने के लिए। जब हम यह देखते हैं कि हमारी बहनों की मांग का सिंदूर छीन लिया गया, हमारी बहनों की मांग उजाड़ दी गई, हमारे नौजवान बेदर्दी से अंग्रेजों की लाठी का शिकार हुए, हमारे बूढों की कमर तोड़ दी गई, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जुल्मों सितम की चक्कियां पीसनी पड़ीं। ऐसे में जहां एक ओर सरदार ऊधम सिंह की शख्सियत उभर कर आती है, जहां राम प्रसाद बिस्मिल की शख्सियत उभर कर आती है, वहीं अश्फ़ाक उल्लाह ख़ान जैसे उस मर्दे मुजाहिद को भी हम इस पार्लियामेंट से सलाम करना चाहते हैं, जो फ़ैजाबाद की जेल में जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था और जब उससे यह पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उस समय अश्फ़ाक उल्लाह खान ने अपनी ख्वाहिश का इरादा कुछ इस तरह जाहिर किया था-कि

''कुछ आरजू नहीं है बस आरजू है इतनी

ख़ाके वतन की मिट्टी रक्ष दे कोई क़फन में''।।

जब हम पलट कर अपनी हिन्दुस्तानी जम्हूरियत के चाहने वाले एक शैदाई रामप्रसाद बिस्मिल को देखते हैं, तो हमारा सिर फिर से फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है, जिन्होंने गोरखपुर की जेल की सलाखों से निकल कर तब तख्ता-ए-दार को चूमा है तो हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए वह मशहूर नारा दिया है, जिसको उर्दू ज़बान ने अपने खूबसूरत जामे में हमेशा के लिए महफूज़ कर दिया है,

''सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है
वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां
हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है।''

सदर-ए-मोहतरम, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दू शुरू होता है 'ह' से और मुस्लिम शुरू होता है 'म' से, कल यही हमारी वह ताक़त थी जो अंग्रेजों के मुकाबले में हिन्दुस्तान की आज़ादी का एक स्लोगन बन गई थी, आज अगर हम हिन्दुस्तान को महफूज़ रखना चाहते हैं तो हिन्दू का 'ह' वहां से हमें निकालना होगा, मुस्लिम का 'म' यहां से निकालना होगा और क़ौमी यकजहती के लिए जब उसे जोड़ेंगे तो 'हम' बनेगा, जब 'हम' बनेगा तो एक मज़बूत हिन्दुस्तान भी बनेगा।

सदर-ए-मोहतरम, उस मज़बूत हिन्दुस्तान की कल्पना हमारी हुकूमत ने की है और उसी मज़बूत हिन्दुस्तान का सपना सरदार मनमोहन सिंह साहब ने देखा है, इसलिए मैं कौमी यकजहती पर, चूंकि यह खुतबा-ए-सदारत का हिस्सा है, एक मिनट और लेना चाहूंगा। कौमी यकजहती खुतबा-ए-सदारत का एक अहम हिस्सा है। जब तक पीस नहीं होगा, एकता नहीं होगी, इत्तिहाद नहीं होगा, तब तक इंसाफ और न्याय का सूरज कहीं से रौशन होता हुआ दिखलाई नहीं देगा। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम सबसे ज्यादा बल कौमी यकजहती, कौमी एकता, हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख-ईसाई के प्यार पर दें ताकि हिन्दुस्तान को हम एक जन्नत-निशां मुल्क बना कर सारी दुनिया में इंसाफ के अलम्बरदार की हैसियत से खड़ा कर दें। हुकूमते हिन्द ने नेक नीयति के साथ इस मुल्क में उपेक्षित और बेरोज़गार, चाहे वे अक्लियत के लोग हों, या अक्सरीयत के लोग हों, उन पर भी अपनी नज़र डाली है और उसी का एक हिस्सा सौ दिन तक ग़रीब खानदान के लोगों को मज़दूरी और रोज़गार के ज़रिए रोज़ी-रोटी फराहम करवाना है। सर, गरीब की कोई जात या बिरादरी नहीं होती, हर जात-बिरादरी में ग़रीब बहुत ही ज्यादा सिसकता हुआ दिखलाई दे रहा है, मगर इस गरीब मज़दूर, किसान की हैसियत वह है जिस हैसियत को आज हम सभी लोग सलाम करें तो बेहतर होगा। यह पार्लियामेंट की लीला उसी गरीब के हाथ की लीला है, यह हवाई जहाज उसी गरीब के हाथों का बनाया हुआ है और आज हमारे लिए सहूलियतों का निशान है। यह रेलगाड़ी उसी गरीब की देन है, यह सड़कें, जिन पर अमीरों की बड़ी-बड़ी कारें चल रही हैं, उसी गरीब के हाथों की लीला है, यह समुन्दरों से निकलने वाला मोती उसी गरीब के डूबने का करिश्मा है। मगर, सर, आज उस गरीब का हाल हमारे मुल्क में यह है। कि जाड़े के जमाने में वह कम्बल के बगैर मरता है, गर्मी के जमाने में उसे लू के थपेड़े खा जाते हैं।

बरसात के जमाने में उसकी झौंपड़ी बह जाती है और वह दरख्तों पर टंगा हुआ दिखलाई देता है। मैं अपने एक शेर में हिन्दुस्तान के गरीब की सूरते हाल आपके सामने रखना चाहूंगा:

''फुटपाथ पर पड़ा था, वह भूख से मरा था,

कपड़ा उठाकर देख तो पेट पर लिखा था,

सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा,

हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा।''

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस खुतबा-ए-सदारत में हिन्दुस्तान की तरक्की का जो सपना देखा गया है, खुदा करे वह हमारा अपना बने और हर तबके के लोगों को यह अहसास हो कि हुकूमत हमारी है, मुल्क हमारा है, हमारे साथ अन्याय ही नहीं बल्कि न्याय की परिभाषा भी इस्तेमाल की जाएगी।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। मुल्क की सरहद और सीमा की हिफाजत के लिए हर कौम के अंदर जज्बा है, मैं खुद फौजी खानदान से आता हूं। मेरा खानदान एक दो सौ साल नहीं, चार सौ साल से इस मुल्क की सरहद और सीमा पर अपना खून पानी की तरह बहाने का जज्बा रखता है। सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर इस मुल्क का मुसलमान कहीं पिछड़ा है, कहीं पिछड़ गया है और गिनती के एतबार से इस गवर्नमेंट ने इस जरुरत को महसूस किया है कि मुसलमान को तालीम के मैदान में, रोजी-रोटी के मैदान मे और फौज के मैदान में, फॉर्सेज के मैदान में, देश के ऊपर अपनी जान देने का हौसला देकर खड़ा रख कर एक मजबूत सिपाही बनाने की जरुरत है तो मेरा ख्याल यह है कि मादरे वतन की हिफाजत ही हमारे ईमान का भी एक हिस्सा है, अपने वतन की हिफाजत करना हमारे लिए लाजिमी है। इसलिए अगर मुसलमानों को फौज में भी रखा जाए तो अब्दुल हमीद की याद फिर से ताजा होगी, अशफाकुल्लाह खान की रवायतें फिर से जिन्दा होंगी और साथ ही साथ ब्रिगेडियर उस्मान, जो हमारे कश्मीर का सम्मान भी है और हमारे कश्मीर को अटूट अंग बनाने में उसका योगदान भी है, ऐसे लोगों को नस्ल-दर-नस्ल पैदा करने की जरूरत है। इसलिए सच्चर कमेटी के जरिए जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी कांग्रेस की सदर मोहतरमा सोनिया गांधी ने मुशतरका कोशिशें की हैं, यह काबिले मुबारकबाद है। मैं यह नहीं कहता कि किसी जाति बिरादरी पर एहसान कर दिया जाए। मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर एहसान नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इंसाफ तो कीजिए, इंसाफ के तकाजे बोल रहे हैं कि हिन्दुस्तान की मुस्लिम मॉयनोरिटी यकीनन हर तरह उपेक्षित है। उसे हर मैदान में आगे लाकर अपने बड़े भाइयों के साथ शाना-बशाना खड़ा करने की जरूरत है ताकि मुल्क जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसकी तरक्की पर कोई दाग न लगे। एक ऐसा दरख्त जो हरा-भरा है, अगर उसकी दो-चार डालियां कट जाएंगी, सूख जाएंगी, उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो उस दरख्त की खूबसूरती का खात्मा हो जाएगा। हिन्दुस्तान इंसानियत का एक गुलिस्तां है, हिन्दुस्तान आदमियत का एक चमन है। इस

चमन में अगर मुस्लिम मॉयनोरिटीज के पत्ते सूख रहे हैं, डालें जल रही हैं तो उन्हें बचाकर मोहब्बत और कौमी एकता और सेक्युलरिज्म का पानी देने की जरूरत है ताकि सब के सब सब्ज़-व-शादाब रहें, आबाद रहें और मुल्क तरक्की कर सके। मैं खुतबा-ए-सदारत की हिमायत करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی ''مدھیہ پردیش'' : شکریہ، صدر محترم، میں خطبہ صدارت پر، اس کے فیور میں کچھ اپنے محسوسات پیش کرنے کے لئے ہاؤس میں کھڑا ہوا ہوں۔

سر، خطبہ صدارت کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال بھر تک حکومت نے کون کون سے اقدامات ملک کے مفاد میں اور ملک کے عوام کے مفاد میں کئے ہیں، ان پر پریسیڈنٹ آف انڈیا کے ذریعہ روشنی ڈالی جائے۔ موجودہ صورت حال میں حکومت فیوچر کے لئے کیا کیا ارادے رکھتی ہے اور حکومت اپنی نیک خواہشات ملک کی ترقی اور ملک کے عوام کے لئے منصفانہ طور پر کس طرح پہنچانا چاہتی ہے، جس کا اظہار کیا جائے۔ ہم خطبہ صدارت کو جب پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں پوری پوری کوشش اس بات کی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے کہ زندگی کا ہر وہ نقشہ، جس میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے، اس میں ایمانداری سے رنگ بھرا جائے،

(شری سبھاپتی صدر نشیں ہوئے)

جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے جن جن شعبوں میں خامیاں ہیں، ان خامیوں کو نیک نیتی کے ساتھ ختم کیا جائے۔ نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسی کا ایک حصہ خطبہ صدارت میں قومی یکجہتی بھی ہے۔ قومی یکجہتی کی بات میں نے پہلے اس لئے لی ہے کہ یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ اپنی روایتوں کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں قومی یکجہتی کا سب سے بڑا علمبردار بن کر کھڑا رہا ہے۔ ہمارے اس ملک میں دنگے فساد اور طرح طرح سے ذات کے نام پر، مذہب کے نام پر، مندر اور مسجد کے نام پر لوگوں کے جذبات سے کھیل کر انسانوں کا کشت وخون ہوا ہے، یہ بھی ہمارے لئے ایک بہت دردناک تاریخ آزاد بھارت کی سیکولر گورنمنٹ کے رہتے ہوئے بن گئی ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی قومی یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں، ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور ہر حکومت کی یہ ذمہ دارانہ پالیسی ہونی چاہئے کہ وہ حکومت قومی یکجہتی کے معاملے میں

†[]Transliteration of Urdu Script.

مکمل طور پر چوکس اور بیدار رہے اور کسی بھی طرح سے قومی یکجہتی کو، قومی ایکتا کو تباہ و برباد ہونے سے ہر حال میں بچائے۔ ہماری حکومت نے اس سلسلے میں جو نئے قدم اٹھائے ہیں، وہ یقیناً قابل تعریف ہیں اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے جو کچھ اپنے ارادے ظاہر کئے ہیں، خدا کرے ان ارادوں کا خواب

شرمندۂ تعبیر ہو۔ اس بات کو ہم اس ملک میں دو مختلف قوموں کو [illegible] کرنا چاہیں گے۔ ایک قوم، جسے ہندو قوم کے نام سے لوگ جانتے ہیں، دوسری قوم کو مسلم قوم کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ جب قومیت کے تناظر میں ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو کشمیر کی وادی سے لیکر کنیا کماری کی سرحدوں تک ہندو بھی ہندوستانی ہے اور مسلمان بھی ہندوستانی ہے۔ یہ ہندوستانی قوم، جسے ہندو اور مسلمان کے نام پر بار بار بانٹنے کی کوششیں کی گئی ہیں کسی پر بھی کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں۔ اس سچائی کو ادھر کے لوگ بھی مانتے ہیں اور ادھر کے لوگ بھی مانتے ہیں، مگر ہم اپنے دیش کی یکجہتی کی طاقت کو اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم قدیم بھارت کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں۔ ڈیڑھ سو سال تک ہمارے ملک پر غلامی کے کالے بادل چھائے رہے، نفرتوں کی بدلیاں گھرتی رہیں اور وحشتوں کا پانی برستا رہا۔ جلیاں والا باغ میں ہندوستانیوں کا خون بے دردی کے ساتھ بہا، ہندوستانی سوتنتر سیننانیوں کو وطن عزیز کی حفاظت کے لئے جو قربانیاں دینی پڑیں، وہ جگ ظاہر ہے۔ ہمارا سر اس وقت فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، جب ہم اتہاس کی روشنی میں اس ملک کے ہندو، مسلم اور سکھوں کی ماؤں کی کوکھ اجڑتی ہوئی دیکھتے ہیں، آزاد بھارت کی کوکھ بسانے کے لئے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی مانگ کا سیندور چھین لیا گیا، ہماری بہنوں کی مانگ اجاڑ دی گئی، ہمارے نوجوان بے دردی سے انگریزوں کی لاٹھی کا شکار ہوئے، ہمارے بوڑھوں کی کمر توڑ دی گئی، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ظلم و ستم کی چکیاں پیسنی پڑیں۔ ایسے میں جہاں ایک اور سردار ادھم سنگھ کی شخصیت ابھر کر آتی ہے، جہاں رام پرساد بسمل کی شخصیت ابھر کر آتی ہے، وہیں اشفاق اللہ خان جیسے اس مرد مجاہد کو بھی ہم اس پارلیمنٹ سے سلام کرنا چاہتے ہیں، جو فیض آباد کی جیل میں جب پھانسی کے تختے پر چڑھایا جا رہا تھا اور جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اس وقت اشفاق اللہ نے اپنی خواہش کا اظہار کچھ اس طرح ظاہر کیا تھا۔ کہ

کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو ہے اتنی
خاکِ وطن کی مٹی رکھ دے کوئی کفن میں

جب ہم پلٹ کر اپنی ہندوستانی جمہوریت کے چاہنے والے ایک خوگر امر شہید رام پرساد بسمل کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا سر پھر سے فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، جنہوں نے گورکھپور کی جیل کی سلاخوں سے نکل کر تختہ دار کو چوما ہے تو ہندوستان کی آزادی کے لئے وہ مشہور نعرہ دیا ہے، جس کو اردو زبان نے اپنے خوبصورت جامہ میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہے۔

سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے
دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے
وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں
ہم ابھی سے کیا بتائیں، کیا ہمارے دل میں ہے

صدرِ محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندو شروع ہوتا ہے 'ہ' سے اور مسلم شروع ہوتا ہے 'م' سے، کل یہی ہماری وہ طاقت تھی جو انگریزوں کے مقابلے میں ہندوستان کی آزادی کا ایک سلوگن بن گئی تھی، آج اگر ہم ہندوستان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہندو کا 'ہ' وہاں سے ہمیں نکالنا ہوگا، مسلم کا 'م' یہاں سے نکالنا ہوگا اور قومی یکجہتی کے لئے جب ہم اسے جوڑیں گے تو 'ہم' بنے گا، جب 'ہم' بنے گا تو ایک مضبوط ہندوستان بھی بنے گا۔

صدرِ محترم، اس مضبوط ہندوستان کی کلپنا ہماری حکومت نے کی ہے اور اسی مضبوط ہندوستان کا سپنا سردار منموہن سنگھ صاحب نے دیکھا ہے، اس لئے میں قومی یکجہتی پر، چونکہ یہ خطبہء صدارت کا ایک حصہ ہے، ایک منٹ اور لینا چاہوں گا۔ قومی یکجہتی خطبہء صدارت کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب تک پیس نہیں ہوگا، ایکتا نہیں ہوگی، اتحاد نہیں ہوگا، تب تک انصاف اور نیائے کا سورج کہیں سے روشن ہوتا ہوا دکھلائی نہیں دے گا۔ ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ بل قومی یکجہتی، قومی ایکتا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے پیار پر دیں، تاکہ ہندوستان کو ہم ایک جیتے نشاں ملک بنا کر ساری دنیا میں انصاف کے علمبردار کی حیثیت

سے کھڑا کریں۔ حکومت ہند نے نیک نیتی کے ساتھ اس ملک میں اُپیکشت اور بے روزگار، چاہے وہ اقلیت کے لوگ ہوں، یا اکثریت کے لوگ ہوں، ان پر بھی اپنی نظر ڈالی ہے اور اسی کا ایک حصہ سو دن تک غریب خاندان کے لوگوں کو مزدوری اور روزگار کے ذریعے روزی روٹی فراہم کروانا ہے۔

سر، غریب کی کوئی ذات یا برادری نہیں ہوتی، ہر ذات برادری میں غریب بہت ہی زیادہ سسکتا ہوا دکھلائی دے رہا ہے، مگر اس غریب مزدور، کسان کی حیثیت وہ ہے جس حیثیت کو آج ہم سبھی لوگ سلام کریں تو بہتر ہوگا۔ یہ پارلیمنٹ کی لیلا اسی غریب کے ہاتھ کی لیلا ہے، یہ ہوائی جہاز اسی غریب کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے اور آج ہمارے لئے سہولیتوں کا نشان ہے، یہ ریل گاڑی اسی غریب کی دین ہے، یہ سڑکیں، جن پر امیروں کی بڑی بڑی کاریں چل رہی ہے، اسی غریب کے ہاتھوں کی لیلا ہے، یہ سمندروں سے نکلنے والا موتی اسی غریب کے ڈوبنے کا کرشمہ ہے۔ مگر، سر، آج اس غریب کا حال ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جاڑے کے زمانے میں کمبل کے بغیر مرتا ہے، گرمی کے زمانے میں اسے لو کے تھپیڑے کھا جاتے ہیں۔ برسات کے زمانے میں اس کی جھوپڑی بہہ جاتی ہے اور وہ درختوں پر ٹنگا ہوا دکھلائی دیتا ہے۔ میں اپنے ایک شعر میں ہندوستان کے غریب کی صورت حال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔

فٹ پاتھ پر پڑا تھا، وہ بھوک سے مرا تھا
کپڑا اٹھا کر دیکھا تو پیٹ پر لکھا تھا
سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا
ہم بلبلیں ہیں اسکی، یہ گلستاں ہمارا

میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خطبہء صدارت میں ہندوستان کی ترقی کا جو سپنا دیکھا گیا ہے، خدا کرے وہ ہمارا اپنا بنے اور ہر طبقے کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ حکومت ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ہمارے ساتھ انیائے نہیں بلکہ نیائے کی پریبھاشا استعمال کی جائے گی۔

میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ملک کی سرحد اور سیما کی حفاظت کے لئے ہر قوم کے اندر جذبہ ہے، میں خود فوجی خاندان سے آتا ہوں۔ میرا خاندان ایک دو، سو نہیں چار سو سال سے اس ملک کی

سرحد اور سیما پر اپنا خون پانی کی طرح بہانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ سر، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کا مسلمان کہیں پچھڑا ہے، کہیں پچھڑ گیا ہے اور گنتی کے اعتبار سے اس سرکار نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ مسلمان کو تعلیم کے میدان میں، روزی روٹی کے میدان میں اور فوج کے میدان میں، فورسیز کے میدان

میں، پولیس کے اوپر اپنی جان دینے کا حوصلہ دے کر کھڑا رکھ کر ایک مضبوط سپاہی بنانے کی ضرورت ہے تو میرا خیال یہ ہے مادر وطن کی حفاظت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اپنے وطن کی حفاظت کرنا ہمارے لئے لازمی ہے۔ اس لئے اگر مسلمانوں کو فوج میں بھی رکھا جائے، تو عبدالحمید کی یاد پھر سے تازہ ہوگی۔ اشفاق اللہ خان کی روایتیں پھر سے زندہ ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ ہزیئر عثمان جو ہمارے کشمیر کا سمان بھی ہیں اور ہمارے کشمیر کو ووٹ الگ بنانے میں ان کا یوگدان بھی ہے، ایسے لوگوں کو نسل در نسل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے سچر کمیٹی کے ذریعے جس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے اور ہماری کانگریس کی صدر محترمہ سونیا گاندھی نے مشترکہ کوششیں کی ہیں یہ قابل مبارکباد ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ذات برادری پر احسان کر دیا جائے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر احسان نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم انصاف تو کیجئے۔ انصاف کے تقاضے بول رہے ہیں کہ ہندوستان کی مسلم مائنارٹی ہر طرح سے پچھڑی ہے۔ اسے ہر میدان میں آگے بڑھنے بڑے بھائیوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک جس طرح سے ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی پر کوئی داغ نہ لگے ایک ایسا درخت جو ہرا بھرا ہے، اگر اس کی دو چار ڈالیاں کٹ جائیں گی انھیں پانی نہیں ملے گا تو اس درخت کی خوبصورتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہندوستان، انسانیت کا ایک گلستاں ہے، ہندوستان آدمیت کا ایک چمن ہے۔ اس چمن میں اگر مسلم مائنارٹیز کے پتے سوکھ رہے ہیں، ڈالیں جل رہی ہیں تو انھیں بچا کر محبت اور قومی ایکتا اور سیکولرزم کا پانی دینے کی ضرورت ہے تاکہ سب کے سب سرسبز و شاداب رہیں، آباد رہیں اور ملک ترقی کر سکے۔ میں خطبہ صدارت کی حمایت کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، دھنیواد۔

"ختم شد"

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, I, on behalf of our Government, rise to join the hon. Members in conveying our sincere thanks to the hon. *Rashtrapatiji* for his Address to Parliament. I also thank hon. Members for their valuable comments. I assure the House that we will take note of the many genuine concerns raised regarding the Government's policies and programmes. I am also grateful for the many valuable suggestions made on how we can improve the quality of governance and address the concerns of our people. I greatly value these suggestions and I will try and address as many of these concerns as possible.

Mr. Chairman, Sir, the National Common Minimum Programme remains the basic guide for the formulation of policies and directions of our Government. Several hon. Members have made comments, some of our colleagues have expressed doubts whether we are moving in the right direction, in accordance with the mandate given to us by the Common Minimum Programme. There may be some differences in perception. But I wish to assure all the Members of this House that this Government is solidly committed to basing its policies and programmes on othe National Common Minimum Programme. We stand by it and we would like to be judged by our commitment to the National Common Minimum Programme.

Sir, the President's Address to the Parliament is the most important statement of Policy that the Government places before this august House at the beginning of every year. It is a statement in which the policies and priorities of the Government are outlined. It is not an exhaustive account of every concern that we have, nor a statement on every issue. Nevertheless, it offers a comprehensive survey of the Government's policies and priorities.

Sir, I do believe that the hon. Rastrapathiji has presented before us an important statement that should make every Indian proud and reassured. Proud, because India is once again on the march as a secular republic, as a self-confident nation, as one of the fastest growing economies in the world. Never before have our prospects been as bright as they are today. Reassured, because this march is not just of a few, but of all. Our pledge to ensure that our growth process is inclusive, caring and equitable has imparted a new sense of belonging to all sections of our society.

Sir, our Government came to power on a pledge to care for the *aam admini,* on a pledge to make India shine, but shine for all. Each of the development and employment-oriented programmes we have launched

has this single objective in mind. The national Rural Employment Guarantee Act, the revamping of the Sarva Shiksha Abhiyan, the Mid-Day Meal Programme which now covers 12 crore children , the ICDS looking after the nutrition and health of pregnant women and our children which now covers the entire country, Bharat Nirman covering rural roads, drinking water, irrigation, electricity housing and telecom, the National Rural Health Mission which lays particular emphasis on health care facilities in the most backward States of our Union, the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, the initiatives we have taken in infrastructure development, in reviving the manufacturing sector, in reviving agricultural growth, every initiative has been aimed at ensuring that while we accelerate growth we do so in an equitable, fair and just manner.

I sincerely believe, Sir, that meaningful solutions to the problems of mass poverty which still afflict millions and millions of our citizens can best be found in the framework of a rapidly expanding economy. But I am also equally firm in my conviction that while growth may be a necessary condition for solving the problems of poverty, but it is not a sufficient condition and that is why the need for deliberate measures to soften the harsh adges of extreme poverty. I submit to you, Sir, in these last 20 months that our Government has been in office we have made an earnest effort to soften the harsh edges of poverty. I wouldn't say that we have succeeded in removing poverty. But we have launched a process which over a period of time would soften very considerably the harsh edges of extreme poverty that prevail in our country. I would be the last one to assert that in twenty months we can implement all these programmes. The process has just begun, and we have a Herculean task before uas to ensure that the programmes which we have devised are effectively implemented. That would require a new wave of cooperation between the Centre and the States, taking full advantage of the massive opportunities in which the revitalised Panchayati Raj system. We need co-operative federalism; we need a broad-base national consensus between the Centre and the States regardless of their political affiliation, to make a success of the programmes that we have launched. We have just begun. Implentation will determin whether we succeed in what we have set out to achieve, and I appeal to all the hon. Members of this House to co-operate with the Government in realising the dreams of the founding fathers of our Republic, to get rid of chronic poverty, ignorance and disease which still affict millions and millions

of our citizens. And this was the essence of the Presidents' Address. Some of the hon. Members, sitting in the Opposition, — Shri Raj Nath Singh is not here; Shri Venkaiah Naidu is not here; Shri Jaswant Singh is here — have difficulties in appreciating this. I do not blame them. During their tenure in office, they were unable to present which a comprehensive account of development and better governance. Their focus was on a socially divisive agenda, on a non-developmental agenda; it on an agenda that mired the country in a low growth syndrom ...*(Interruptions)* Shri Raj Nath is not here; he raised issue about governance, who runs the UPA, what the authority of the Prime Minister is and he made other side remarks. I do not wish to waste the time of the House in dealing with this comment. But I do which to say that the issue of strength and weakness which is raised to deflect public attention form real issues the concern our people has to be judged by the performance of our Government ...*(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA: Is it the reply to questions put by us? ...(व्यवधान)... This is most unfortunate ...*(Interruptions)*

श्री राजू परमार (गुजरात): बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... उन्हें बोलने दीजिए । ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...*(Interruptions)* Please let him speak ...*(Interruptions)* I will not allow ...*(Interruptions)*

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: *

श्री राजू परमार: *

श्री रवि शंकर प्रसाद: (बिहार) *

श्रीमती सुषमा स्वराज: *

MR. CHAIRMAN: I won't allow ...*(Interruptions)* Please take you seat ...*(Interruptions)* Nothing will go on record ...*(Interruptions)* I won't allow anybody ...*(Interruptions)* Please take your seat ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: I won't allow. ...*(Interruptions)*

I won't allow. ...*(Interruptions)*

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

श्री सभापति: बैठिए ...(व्यवधान)... बैठ जाइए ...(व्यवधान)... हो गया।

---

*Not recorded.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, I was saying that the issue of strength and weakness is raised to deflect public attention from the real issues that concern the Indian people. This Government has delivered eight per cent growth. India is now poised for achieving a growth rate of close to eight to ten per cent. Our national investment rate of 31 per cent today is at an all-time high. Our national savings rate of 29 per cent of the GDP is at an all-time high. In the next five or six years, as our young population gains employment opportunities, the saving potential of our economy will go still higher. And, India is now poised for emerging as one of the fastest growing economies in the world. Certainly, we are today the fastest growing market economy in the world. This Government has economically and socially empowered the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, religious and linguistic minorities, farmers and the working class, the unemployed and the poor. This Government has revived investment and generated employment opportunities. This Government has ensured that India stands tall in the comity of nations. This Government has charted a new path. It is the progress along this path that has been spelt out in the President's Address. My authority derives from this record of performance, I secure my strength from my work.

I wholeheartedly, Sir, join hon. Members who have expressed their thanks to the Rashtrapatiji. Sir, several members, like Shri Gandhi Azad, have drawn our attention to the importance of proper implementation of various programmes we have launched , especially the National Rural Employment Guarantee Act. Sir, in the history of the world, never before has country of the size of one billion people come forward with an employment guarantee programme of the type we have devised. If this programme is well implemented, if we use the resources that we are now going to pour in this programme for building durable productive assets, not only will the problem of unemployment appear more manageable but our rural economy will get an unprecedented boost. Fifty per cent of the resources will be earmarked for improving water management practices in our country, and, therefore, this concern about irrigation, the concern about water emerging as the most serious problem for our country in the 21st century, I think will be taken care of to a considerable degree, if we successfully implement this revolutionary programme. This, as I said earlier, Sir, casts special and onerous responsibilities on all those who contribute to the processes of governance in our country. And I lay, particularly strong

emphasis on cooperation between the Central Government and State Government and also making full use of the potentialities of the Panchayati Raj System. Sir, our growth will not achieve the objectives we have in mind if we do not pay adequate attention to the development of backward regions. In devising some of the flagship programmes of our Government, we have paid particular attention to the more backward districts and more backward regions. For example, although the National Rural Employment Programme will in four years cover all the districts in our country. In the beginning the focus is to identify the most backward districts in States like Bihar, in States like Orissa, in States like Jharkhand, in States like Chhattisgarh, in States

अब्दुल हमीद की याद फिर से ताजा होगी, अशफाकुल्लाह खान की रवायतें फिर से जिन्दा होंगी और साथ ही साथ ब्रिगेडियर उस्मान, जो हमारे कश्मीर का सम्मान भी है और हमारे कश्मीर को अटूट अंग बनाने में उसका योगदान भी है, ऐसे लोगों को नस्ल-दर-नस्ल पैदा करने की जरूरत है। इसलिए सच्चर कमेटी के जरिए जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी कांग्रेस की सदर मोहतरमा सोनिया गांधी ने मुशतरका कोशिशें की हैं, यह काबिले मुबारकबाद है। मैं यह नहीं कहता कि किसी जाति बिरादरी पर एहसान कर दिया जाए। मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर एहसान नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इंसाफ तो कीजिए, इंसाफ के तकाजे बोल रहे हैं कि हिन्दुस्तान की मुस्लिम मॉयनोरिटी यकीनन हर तरह उपेक्षित है। उसे हर मैदान में आगे लाकर अपने बड़े भाइयों के साथ शाना-बशाना खड़ा करने की जरूरत है ताकि मुल्क जिस तरह से तरक्की की रहा है उसकी तरक्की पर कोई दाग न लगे। एक ऐसा दरख्त जो हरा-भरा हे, अगर उसकी दो-चार डालियां कट जाएंगी, सूख जाएंगी, उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो उस दरख्त की सूबसूरती का खात्मा हो जाएगा। हिन्दुस्तान इंसानियत का एक गुलिस्तां है, हिन्दुस्तान आदमियत का एक चमन है। इस चमन में अगर मुस्लिम मॉयनोरिटीज के पत्ते सूख रहे हैं, डालें जल रही हैं तो उन्हें बचाकर मोहब्बत और कौमी एकता और सेक्युलरिज्म का पानी देने की जरूरत है ताकि सब के सब सब्ज़-व-शादाब रहें, आबाद रहें और मुल्क तरक्की कर सके। मैं खुतबा-ए-सदारत की हिमायत करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, I, on behalf of our Government, rise to join the hon. Members in conveying our sincere thanks to the hon. *Rashtrapatiji* for his Address to Parliament. I also thank hon. Members for their valuable comments. I assure the House that we will take note of the many genuine concerns raised regarding the Government's policies and programmes. I am also grateful for the many valuable suggestions made on how we can improve the quality of governance

like Madhya Pradesh, in States like Uttar Pradesh because we know that when resources are in short supply, the more backward regions and the more underdeveloped regions of our country must receive the greatest attention. This is also the focus of attention of the National Rural Health Mission. So, I can assure hon. Members that our Government is fully alive to putting more resources for the development of the backward regions. We will soon be implementing the promised Backward Regions fund. Sir, Rs. 25,000 crores fund which we promised will soon become operational. It will pay particular attention to the development needs of backward regions. Sir, just as important is the issue of having equitable development of ensuring that all sections of society enjoy the benefits of growth. Whether it be the Bill to give Land Rights to Tribals in Forest Areas or the filling up of the backlog of Government jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or the range of legal measures for women's rights, these are all steps we have taken for ensuring the empowerment of all marginalized and weaker sections. Sir, the concern for the welfare of farmers has to be uppermost in the mind of any Government which cares about the well-being of its people. Sir, I assure you we spent a very considerable amount of our time and effort in revitalising our agricultural economy. We have committed ourselves to have an irrigation target of one crore hectares in the next five years. We have launched a massive National Horticulture Mission to diversify our rural economy. We have taken major measures to upgrade the quality and quantity of rural credit that flows to our farming community. In the first two years of our Government, the rural credit from banks and institutional sources has gone up by nearly 60 per cent. But I do recognise that is not enough. I do recognise that there are areas in our country where farmers are in distress. I know that in Vidarbha, in some parts of Andhra Pradesh and in some other cotton growing areas in particluar, there are, I think, difficulties. There are, I think, difficulties, which lead our farmers sometimes even to commit suicide. I promise the House that I have asked the Agriculture Minister to come out with a specific programme designed to take care of the problems of farmers of this type. ...(*Interruptions*)... We will do it. Sir, rural credit is at the heart of a modern agricultural economy in which commercial agriculture grows at the cost of subsistence agriculture. We have taken measure to streamline bank credit for the farming sector. But a very important segment of rural credit comes from the cooperative sector. The Cooperative system in our country, for reasons to which I do not wish to allude, is in serious difficulties. We have,

therefore, taken up a programme involving an outlay of about Rs. 13,000 crores to revitalise the short-term agricultural credit system centering on cooperatives. We will also soon becoming out with a revitalisation programme for restoring the health of long-term agricultural credit institutions such as the improvement of the credit worthiness of agricultural land development banks and other institutions which lend long term resources to our agriculture. Sir, if we really want to have a prosperous agriculture we have to relook at the functioning of the agricultural credit system. We have to have a fresh look at the functioning of the extension system. We have to have a new look at the way we manage our water resources, the way environmental concerns ought to be taken into account, the way we take measures so that degradation of our land and water resources ceases to be such a major problem as is the case today. Dr. Swaminathan and his group have produced a very valuable report dealing with the problems of the farm sector. I assure the House that we will take special measures to examine this report and come out with a balanced package to revitalise India's agricultural economy. Sir, several hon. Members have expressed concern about rise in prices. In a poor country, price stability has to be an imporant component of any policy programme that an effective Government can evolve. I submit to this august House, Sir, that we have done a reasonably good job considering that there has been an unprecedented rise in international oil prices in the last two years. But we can never be satisfied with the status quo. We have expanded the scope of the Antyodaya scheme which now covers over an additional one crore of people, we have now a mid-day meal programme which covers about 12 crore children. We have revamped and expanded the ICDS programme. All these are part and aprcel of a revamped system of food security. We have begun well. But I share the concern of the House that whether it comes to public distribution or other programmes, in dealing with food security we can never be complacent. Some hon. Members had expressed concern about the import of half a million tonnes of wheat. I wish to assure the hon. Members that this ia a precautionary measure, which will not hurt our farmers, but it will strengthen our ability to maintain reasonable price stability. For various reasons to which I do not wish to refer in detail, wheat stocks are unusually low at this time of the year and we have to worry about the next monsoon. We hope it will be a normal monsoon but if it is not a normal monsoon we have to take some precautionary measures and that is a meausre of prudent precaution. We

have taken this step and you have my assurance Sir, that this will not be allowed in any way to hurt the interest of our farming communities. Sir, some hon. Members have commented on Bharat Nirman and some of them have stated that this is a repackaging of existing schemes. Sir, I beg to differ. I urge hon. Members to apprise themselves of this innovative initiative. Never before has such a concerted and planned initiative been launched for rural infrastructure development. I sincerely believe that through Bharat Nirman we will be able to transform our rural economy and realise the vision of our Rashtrapathiji to provide urban amenities in rural areas. Now, I come to infrastruture. Some Member - Shri M. Venkaiah Naidu is not here - have complained that infrastructure growth has slowed down. I do not agree with this proposition. The President's Address gives a detailed account of the important steps taken by our Government to improve the quality of infrastructure in the country. It is this effort that has contributed to the unprecedented increase in the rate of investment in the economy in the last two years. The rate of investment, as I have already mentioned, is at an all-time high, of 31 per cent. Figures in individual sectors speak for themselves. Roads, railways, airports and airlines, ports and shipping, telecommunication, each and every sector is now on a high growth path, buzzing with activity. I am sure, all this will contribute to a further acceleration of income and employement growth. Sir, I would like to take this opportunity to draw the attention of the House to the remarkable turn around achieved by Indian Railways in the last two years, under the able leadership of my colleague, Shri Lalu Prasadji. He will be apprising the House of the considerable improvement in Railway finances, of the important policy changes, and of the long-term investments being made when he presents the Railways Budget. Under his dynaic leadership, Indian Railways have entred a new era of progress, modernisation and growth.

श्री सभापति : रेल मंत्री जी, आपको राबड़ी देवी जी को लाना चाहिए था।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : सर, राबड़ी देवी वॉच कर रही होंगी।

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, some newspapers have been commenting on the slow down in the road-building programme. That is far from the truth. In roadways, the reality is, we have contracted the largest number of BOT projects ever in the history of the National highways Authority of India. The pace of completion of Highways by the National highway Authority under the UPA Government is three times the average rate of completion under the NDA Government. And, the expanded NHDP programme will

cover an additional 37,000 kilometers, excluding the Golden Quadrilateral and the East, West, North, South corridors.

Sir, I should say a few words about the employment situation. Many hon. Members have expressed concerns about unemployment, and I share those concerns. We have a very young age profile of our labour force, and if we cannot provide productive job opportunities for this growing labour force, I think, we would be wasting an enormous opportunity, that our country now has to accelerate the pace of social and economic growth. Therefore, I welcome suggestions as to how, working together as a nation, we can improve the employment prospects, particularly, for the new young entrants to our labour force. Therefore, Sir, I have no hesitation in saying that the overall impact of all our initiatives will have to be to generate more employment and modernise the economy. The National Rural Employment Guarantee Act alone will be a major initiative. In addition, the huge investments we are making in infrastructural development and industry will create additional jobs. Our Government is deeply committed to the welfare of all our working people, not just members of organised trade unions, but also working people in the unorganised sector, in rural and urban areas. Some Members may have a greater concern for organised workers, and I share that concern, but our Government is equally committed to all workers, in all sectors of the economy. I would like to inform the august House that when it came to revitalising and reviving sick units in the public sector, we have not closed down a single unit in the last two years. Our effort has been to revive, to rehabilitate those units. That will be the direction in which we will be moving. Sir, I would like to take this opportunity to once again reassure our people that our Government is committed to the welfare of all our citizens, irrespective of caste, community, language or gender.

I welcome the concern expressed during the debate on the status of women. Our Government condemns the practice of female foeticide, and I should like to reaffirm once again our Government's commitment to 33 per cent reservation in the State and Central Legislatures...(*Interruptions*)...

Sir, I should say a few words about the internal security situation. Many hon. Members have raised the issue of the internal security situation in the country. Rashtrapatiji's Address has given a detailed account of the measures being taken by our Government in Jammu & Kashmir and the

7.00 P.M.

North-East. We are firm in our conviction that violence of any kind is not in consonance with the principles of our democracy and way of life and will be dealt with firmly.

Terrorism will not be given any quarter and will be treated with a firm hand. At the same time, we are willing to engage in a dialogue with all groups, inside and outside the electoral system, in all parts of the country, if they are willing to abjure violence and come to a peaceful resolution of issues. Our history, our culture and our legacy provide adequate space for such peaceful resolutions. Results of this are already visible in Jammu & Kashmir, where not only has violence come down substantially, but there is a ray of hope in the eyes of the people, hope about a peaceful, prosperous future. Even in the case of naxalism, we are committed to dealing with violence firmly while addressing the root causes of disaffection arising out of poverty, landlessness and deprivation.

Sir, I should say a few words about our minorities. I would like to once again reiterate our Government's commitment to the welfare of our minorities, particularly, the Muslim minority. We are committed to their educational, social and economic empowerment. The creation of a Ministry of Minority Affairs is to ensure that their problems get focussed attention of our Government. No less, no more. And, for any reasoned discourse or debate on the subject of their development, we need to have reliable, accurate data on their economic and social status. This is what the Justice Sachar Committee has set out to do. The Committee will complete its work and we will discuss it in the House in detail. It is unfortunate that an academic exercise, which will ensure better targeting of development programmes, is being given an unfortunate tilt. Let me assure the Members of the House, Sir, that the Armed Forces will continue to be apolitical, secular, professional and merit-based, as my colleague, the hon. Defence Minister, has already assured the Houses of Parliament.

I urge upon the Members to make a distinction between empowerment and appeasement. Our Government, as, indeed, any democratic government, must be committed to the empowerment of all and the appeasement of none and that is what our policy envisaged is.

Sir, I should say a few words about the cartoon controversy, which has caused a great deal of anguish among the Muslim communities all over

the world. Sir, on the specific issue of certain disparaging cartoons appearing in some publications abroad, I share the concern expressed in the House. Our Government is deeply concerned about the growing controversy over the publication of cartoons that has offended the Muslim community worldwide. At the same time, at the time when these offending cartoons were first published, our outrage at this had been conveyed, under my instructions, to the Danish Government, both in New Delhi and through our ambassador in Copenhagen, in October, 2005 itself. While expressing our distress over such lack of sensitivity to the religious sentiments of people, we urge that the concerned newspaper should express its apology and the Danish Government should ensure that such actions would not happen again. We condemn all actions which hurt the religious sentiments of any community and are of the view that such activities be dealt with seriously and firmly. We have the greatest regard and respect for all faiths and are committed to protecting their rights and beliefs, to preserving and strengthening the secular nature of our society. India's commitment to religious harmony and tolerance is unshakable and actions that cause hurt to the sentiments of any section of our people are not acceptable. I also urge all our political and religious leaders to exercise utmost restraint and not inflame public opinion. We must uphold our proud tradition as a democracy of conveying our point of view in a reasonable manner.

Sir, I should say a few words about foreign policy. There has been considerable comment in the debate in this House on our foreign policy orientation. I have had, Sir, several opportunities in the last one year to speak at length on many of these issues. I urge hon. Members to appreciate the fact that, by and large, we have had a national consensus on our foreign policy orientation and that has given us great strength in dealing with the world. I sincerely urge all our political parties to respect this tradition so that the hands of the Government are strengthened in dealing with the world. On my part, I assure this august House, that we will make every effort to strengthen the building of a national consensus on foreign policy issues. Sir, I had the opportunity recently of expressing my views on foreign policies when I laid the foundation stone of the Pandit Jawaharlal Nehru Bhawan. Panditji was not just the architect of modern India but also of the way in which free India chose to deal with the world. Panditji's vision was deeply embedded in our civilisational heritage. Our civilisation has a message for the world that informs our foreign policy vision. This has been

a message of unity in diversity, of respect for pluralism. inclusiveness and secularism.

Sir, it was our national interest to seek space in the world to facilitate our development. But our nationalism was not based on narrow chauvinism or aggressive jingoism. At the time of our Independence, the world had just rid itself of one manifestation of such negative nationalism when it defeated fascism. Our nationalism was elevated by larger universal principle as well as an abiding commitment to the well- being of our people. That is precisely why it was an enlightened nationalism.

Similarly, Panditji's idea of non-alignment, as I see it, was also based on the principle that we were not aligned with anyone against anyone, but only with our fundamental values and national interest. Non-alignment was neither an empty slogan nor a pretext to shirk the responsibility to define our own world-view based on our national interest. Indeed, non-alignment was an expression of our enlightened national interest and it continues to be so. We have worked hard to create the space needed to have the freedom to make policy choices in an increasingly inter-dependent world. The means we adopt to pursue our enduring objectives of peace, national security and development will, of course, change from time to time. As Panditji himself used to say, "We live in a dynamic world and we can never be prisoners of the past all the time." Thus, they will have to be evolved in response to the changing reality of an ever-changing world. While the instruments of our policy and the tactics and strategy we adopt may change with time, the values in which they are embedded are universal and will remain true for all time. Our diplomats are called upon to steer the course of India's foreign relations in an extremely complex global scenario. In recent years, we have witnessed a much sharper consonance between our foreign and domestic policies. The Indian economy has taken an outward orientation as a result of the reform policies that were initiated in the early 90s. Our growth rates have been increasing and we seek to sustain annual growth rates of 8-10 per cent in the future. These demands have created new challenges for our foreign policy in terms of seeking access to markets, sources of energy and investment and advanced technologies. These challenges have also led India towards new thrusts in our foreign policy and there are new directions in our policies towards our major economic partners towards our wider Asian neighbourhood and towards other developing countries. Sir, this House has my solemn assurance that in

pursuing our foreign policy, in ensuring our national security and in promoting our economic development, our Government will always have the nation's interest uppermost in our mind. I do believe we have the trust and the confidence of the people of India.

Mr. Chairman, Sir, I do not wish to deal at length with the Iranian Nuclear Programme. We will have an opportunity to discuss it tomorrow or day after.

I would like to say a few words about an issue which has figured in the House, that is, a letter that the U.S. Ambassador has written to the hon. Chief Minister of West Bengal. Sir, I have taken note of the strong sentiments expressed by hon. Members in the matter of the letter received by the Chief Minister of West Bengal from the U.S. Ambassador. I have no hesitation in saying that this letter was unwarranted and at variance with normal diplomatic practice, both in form and in substance. The Ministry of External Affairs has told the Ambassador very clearly that he should adhere to established protocol and channels of communication and desist from making such comments in the future. The Ambassador has noted this to prevent recurrence of such incidents in the future. Sir, we are mindful of the courtesy that is due to elected representatives of the country and will always uphold this.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, we had demanded his recall. The Government has given a statement, I think, this is the second time. He has no regret, nothing.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, the world today views India with great regard and respect. This is because the people of our country have demonstrated to the world that they are second to none. Our civilisational inheritance, our pluralism, our culture of tolerance and inclusiveness are the envy of many nations today. No Indian need feel any sense of inferiority or insecurity in today's world. India stands tall and we stand proud as an open society and an open economy. I am sure hon. Members rejoice in this sense of self-confidence of our people. This sense of national pride was reinvigorated in the recent visit of his majesty, the King of Saudi Arabia and President Chirac when they both paid tribute to our civilisational inheritance and our emerging economic strength. It is with this sense of

self-confidence that we now look forward to the visit of the President of the United States.

Sir, another issue that figured in the debate was the issue of turbans worn by Sikh children in France. Sir, let me assure — I think this is a matter which arose, probably in the other House — the Sikh community that I had, in fact, raised the issue of the French regulations on turbans with President Chirac and he gave me the same assurance that he gave to some other people who had raised the matter with him. I share the Sikh community's concern in this regard. I was assured by President Chirac that he would give due consideration to the sentiments of the Sikh community and take necessary action.

Sir, in conclusion, I would like to assure the House once again, that I will take a closer look at all the suggestions made during the debate and ensure that our Government is alive to the concerns expressed in this august House. I thank all hon. Members who participated in the debate. I would like this motion of Thanks on the President's Address to be passed unanimously. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mr. Prime Minister.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, the Prime Minister has been very kind enough to address all the concerns that we have articulated during the course of the debate. But on the issue of US Ambassador, since this was the second time that this happened and that we have demanded that he should be recalled, and, large sections of the members of both the Houses have articulated the same, I think, Sir, the Government should be forthcoming on this and categorically assure us in this regard. Just expressing and communicating our sentiments to the Ambassador sentiments is not enough, and, it is not becoming in terms of the defense of the national self-respect of the country.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, I share the sentiments expressed by the hon. Members but my own feeling is that in this case, the action that we have taken would suffice for the time being.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

MR. DEPUTY CHAIRMAN:Shri Rajnath Singh is not here. I shall now put the amendment nos. 46 to 55 moved by him to vote.

Amendment Nos. 46 to 55 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Sushma Swaraj is not here. i shall now put the amendment nos. 102-113 moved by her to vote.

Amendment Nos. 102-113 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri S.S. Ahluwalia is not here. I shall now put the amendment nos. 114-149 moved by him to vote.

Amendment Nos. 114-149 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendment nos. 150-152 moved by Shri Dipankar Mukherjee to vote. Are you pressing your Amendments or withdrawing it?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, how can I withdraw? Sir, when I spoke, you were in the Chair. I had addressed the issue and I wanted a discussion under Rule 170. Unfortunately, the Government, the Prime Minister did not find it fit even to refer to the issues which have been raised not only by me but many of us here, knowing fully well our opposition, Left's opposition to this. I specifically said that women's reservation could not be passed in spite of our support. And, this becomes a sort of deadline of 31st January. किसी ने अपने सिर की कसम दे दी तो उसे करवाना जरूरी है because we are opposing it.

So, I am moving the amendments unless the Government assures me that there will be discussion under Rule 170 on the Amendments moved by me. I am very sorry to say that the whole issue has not even been touched.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendments to vote ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, are we having a vote on this? If you want to have a vote, we have no problem ...(*Interruptions*)... But if the Government is not agreeing on the specific discussion ...(*interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Why is the Government shying away from a discussion on this? ...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You assure a discussion under Rule 170. We want to know this. It is the right of the Parliament to know the stand of the Government on this issue. The Government is committed to transparency. Let us have a discussion under Rule 170. Everyone of us has to say what he wants to say on this. How can the Parliament be by-passed?

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we have not challenged the Prime Minister when he asserted that the Government was moving along the Common Minimum Programme. And, our understanding of the issue is that there is a violation of the Common Minimum Programme. Still, we are insisting that if the Government agrees to a discussion, we will not move the amendment.

SHRI SITARAM YACHURI: Mr. Deputy Chairman, Sir, I will just seek your attention for a minute. We all like to appeal to the Prime Minister, since he is in the House, to give the assurance that we shall have a discussion on this. That is all that we are demanding. Let's have a discussion on this under Rule 170. And, on the basis of the discussion we can decide on that issue. You please agree for a discussion, Sir.

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, we have no objection to any type of discussions that the hon. Members want. Under what rule it should take place is a matter that should be discussed with the Chair ...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: So, he agrees that it is for the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, are you withdrawing them? Mr. Dipankar Mukherjee, are you withdrawing these Amendments?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I am not pressing them on the explicit assurance that these will be discussed under Rule 170.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing them?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I am withdrawing them on the explicit assurance from the House that it will be discussed under Rule 170.

Amendment Nos. 150-152 were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment nos. 153 to 162, by Dr. K. Malaisamy. Are you withdrawing, Dr. Malaisamy?

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): I am not pressing them, Sir.

Amendment Nos. 153 to 162 were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are depply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 16, 2006."

The motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER

The status of implementation of the recommendations contained in the Fifth Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU): Sir, I lay a copy of the Report on the Table of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tommorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at twenty-three minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 23rd February, 2006.

MGIPMRND—1015RS—25-09-2006.